RAO'S ACADEMY
for Competitive Exams

मई–2022

करेन्ट अफेयर्स
मैग्जीन

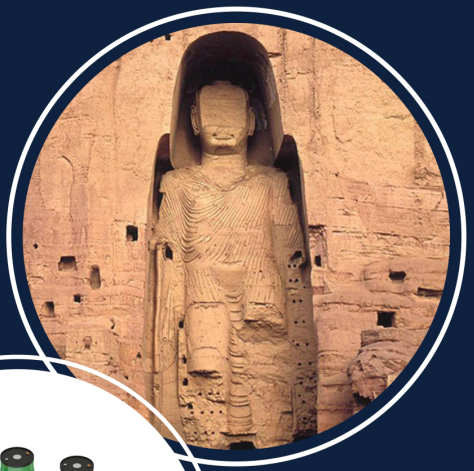

- अर्थव्यवस्था
- सामाजिक मुद्दे
- विविध
- कला और संस्कृति
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी
- अंतर्राष्ट्रीय सम्बंध
- सरकारी योजना
- राजव्यवस्था एवं प्रशासन
- पर्यावरण एवं परिस्थितिकी

RAO'S ACADEMY
for Competitive Exams

आर-26, जोन-II, रेलवे पटरी के सामने, एम.पी. नगर, भोपाल
सम्पर्क सूत्र
0755.7967814, 7967718, 918318618002

YOUR SUCCESS OUR PRIORITY
R
RAO'S ACADEMY
for Competitive Exams
(A unit of RACE)

विषय-सूची

Current Affairs

मई, 2022

विषय-सूची पेज क्रमांक

1. कला और संस्कृति 1-4

- हिन्दू नव वर्ष उत्सव
- बामियान बुद्धा
- माधवपुर मेला
- महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती
- प्रधानमंत्री संग्रहालय
- महावीर जयंती 2022

2. राजव्यवस्था एवं प्रशासन 5-12

- इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का तेज और सुरक्षित प्रसारण
- सामूहिक विनाश के हथियार अधिनियम में संशोधन
- सामूहिक विनाश के हथियार
- भारत सरकार-संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग ढांचा 2023-27
- विमान वस्तुओं में हितों का संरक्षण और प्रवर्तन विधेयक, 2022
- प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र
- प्रतिनिधित्व में कोटा
- देशद्रोह का मुद्दा
- फ्लैग कोड

3. पर्यावरण एवं परिस्थितिकी 13-21

- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA)
- फोर्टिफाइड चावल
- बंगाल तट करता है सर्वाधिक कटाव का सामना

विषय-सूची

- ऑरोरा
- असम में हाइड्रोजन संयंत्र
- आक्रामक उपजाति
- लंबी अवधि का औसत
- दक्षिण भारतीय तटरेखा
- सुंदरबन पर रिपोर्ट
- काजीरंगा पशु गलियारों पर सुप्रीम कोर्ट का पैनल
- वायु गुणवत्ता डेटाबेस

4. अर्थव्यवस्था **22-28**

- न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)
- घरेलू पेटेंट फाइलिंग
- नागालैंड में शहरी विकास
- GIFT & IFSC esa Longevity Hub
- खनिज उत्पादन
- डिजिटल बैंकिंग इकाइयां (DBU)
- इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक
- भारत-यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (सीईपीए)

5. विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी **29-35**

- जीएसएलवी-एफ10
- जीनोम अनुक्रमण
- स्वदेशी बुद्धिमान परिवहन प्रणाली (आईटीएस)
- ग्लोबल वार्मिंग चुनौती
- झींगा की खेती
- पोर्टेबल सोलर रूफटॉप
- 5जी सेवा
- एलसीआरडी

विषय-सूची

6. सामाजिक मुद्दे **36-41**

- धूम्रपान
- एवीजीसी प्रचार कार्य
- राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक
- रेशम शहरों का वैश्विक नेटवर्क
- स्वनिधि से समृद्धि
- हरियाणा में चारे के परिवहन पर प्रतिबंध
- राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (NCF)
- ई-बीसीएएस

7. अंतर्राष्ट्रीय सम्बंध **42-48**

- (OPEC+)
- स्मारकों और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस
- चीन-पाक आर्थिक गलियारा
- फॉकलैंड आइलैंड
- सतत विकास लक्ष्यों
- नाटो
- वैश्विक सुरक्षा पहल
- साइबर सुरक्षा
- यू.ए.ई. गोल्डन वीजा

8. सरकारी योजना **49-54**

- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएम-जीकेएवाई)
- रैंप (RAMP)
- न्यू इंडिया लिट्रेसी प्रोग्राम

विषय-सूची

- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
- आयुष वीजा
- ई-श्रम पोर्टल
- जिवला

9. विविध **55-62**

- मनाली - सरचू रोड
- पीएम गति शक्ति
- पिनाका एमके-आई रॉकेट सिस्टम
- जीसीटीएम
- मलेरिया से मुक्त
- S-400 वायु रक्षा मिसाइल
- अतिरिक्त तटस्थ शराब (ईएनए)
- दिल्ली विश्वविद्यालय
- ऑपरेशन सतर्क

1 कला और संस्कृति

हिन्दू नव वर्ष उत्सव

चर्चा में क्यों

भारत के राष्ट्रपति ने हिंदू नव वर्ष की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं भेजी।

महत्वपूर्ण बिंदु

- भारत के राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने चैत्र शुक्लदी, उगादी, गुड़ी पड़वा, चेती चंद, नवरेह और साजिबू चीराओबा की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं भेजी हैं।
- बसंत और भारतीय नव वर्ष की शुरुआत का स्वागत करने के लिए देश भर में विविध तरीकों से मनाए जाने वाले ये त्यौहार हमारी सांस्कृतिक और सामाजिक एकता के बंधन को मजबूत करते हैं।
- आनंदमय उत्सव हमारे समाज में सद्भाव और बंधुत्व की भावना को मजबूत करते हैं।

नवरेह

- 'नवरेह' शब्द संस्कृत के 'नववर्ष' से लिया गया माना जाता है जिसका अर्थ है नया साल।
- कश्मीरी पंडित अपनी देवी शारिका को नवरेह त्योहार समर्पित करते हैं और त्योहार के दौरान उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं।

चेती चंडी

- चेती चंद सिंधी नए साल की शुरुआत और सिंधी संत झूलेलाल के नाम से लोकप्रिय इष्टदेव उदरोलाल की जयंती का प्रतीक है।
- सिंधी नए सुरुचिपूर्ण कपड़े पहनते हैं और भव्य झूलेलाल जुलूस में शामिल होते हैं। उत्सव के बाद एक सांस्कृतिक कार्यक्रम और लंगरसाब होता है।

उगादी

- 'उगादी' पारंपरिक नव वर्ष दिवस आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है।

चैत्र सुकलादि

- तेलुगु नव वर्ष चंद्र कैलेंडर के अनुसार 'चैत्र शुद्ध पद्यमी' को मनाया जाता है। इस अवसर पर, भक्त मंदिरों में पूजा-अर्चना करने के लिए उमड़ते हैं।

बामियान बुद्धा

खबरों में क्यों

तालिबान शासन मेस अयनक में प्राचीन बुद्ध प्रतिमाओं की रक्षा करेगा।

महत्वपूर्ण बिंदु

- अफगानिस्तान में तालिबान शासन ने कहा है कि वह मेस अयनक में प्राचीन बुद्ध की मूर्तियों की रक्षा करेगा, यहाँ एक तांबे की खदान का स्थान भी है जहाँ तालिबान-चीनी निवेश की उम्मीद कर रहे हैं।

प्राचीन बामियान बुद्ध

- बामियान घाटी, हिंदू कुश पहाड़ों में और बामियान नदी के किनारे, प्रारंभिक रेशम मार्गों का एक प्रमुख नोड था, जो वाणिज्यिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान दोनों के केंद्र के रूप में विकसित था।
- यूनेस्को के अनुसार, बामियान का उदय मध्य एशिया में बौद्ध धर्म के प्रसार के साथ निकटता से जुड़ा था, और बदले में उस समय की राजनीतिक और आर्थिक धाराओं से जुड़ा था।
- बलुआ पत्थर की चट्टानों से तराशी गई बामियान बुद्ध की प्रतिमाओं के बारे में कहा जाता है कि ये 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व की हैं, और कभी दुनिया में सबसे ऊंची खड़ी बुद्ध प्रतिमा थीं।
- उनकी रोमन ड्रैपरियों में और दो अलग-अलग मुद्राओं के साथ, मूर्तियाँ गुप्त, ससैनियन और हेलेनिस्टिक कलात्मक शैलियों के संगम के महान उदाहरण थीं।
- स्थानीय लोगों द्वारा साल्सल और शामामा को बुलाया गया, वे क्रमशः 55 और 38 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचे। सालसाल का अर्थ है "प्रकाश ब्रह्मांड के माध्यम से चमकता है", जबकि शम्मा "रानी माँ" है।

RAO'S ACADEMY for Competitive Exams (A unit of RAO'S) YOUR SUCCESS OUR PRIORITY

- तालिबान ने पहली बार 27 फरवरी, 2001 को मूर्तियों को नष्ट करने के अपने इरादे की घोषणा की। भारत ने कलाकृतियों के हस्तांतरण और सुरक्षा की व्यवस्था करने की पेशकश की।
- तालिबान के अलावा, आतंकवादी समूह आईएसआईएस ने अपने "मूर्तिपूजक" संबंधों के कारण पूर्व-इस्लामी दुनिया से डेटिंग कलाकृतियों को भी नष्ट कर दिया है।
- 2003 में, यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थलों की सूची में बामियान बुद्धों के अवशेषों को शामिल किया।
- यह प्रस्तावित किया गया था कि मूर्तियों को उन टुकड़ों के साथ फिर से बनाया जाना चाहिए जो अभी भी उपलब्ध थे, और उनके निचे में बहाल किए गए थे, लेकिन इसका विरोध किया गया था।

माधवपुर मेला

खबरों में क्यों

प्रधानमंत्री ने गुजरात में माधवपुर मेले को भारत की सांस्कृतिक विविधता और जीवंतता का अनूठा उत्सव बताया।

महत्वपूर्ण बिंदु

- भारत के प्रधानमंत्री ने मन की बात से एक क्लिप

साझा की जिसमें उन्होंने गुजरात में माधवपुर मेले को भारत की सांस्कृतिक विविधता और जीवंतता के अनूठे उत्सव के रूप में विस्तार से बताया।
- 2018 से, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से, गुजरात सरकार ने उत्तर-पूर्वी राज्यों के मौजूदा मुख्यमंत्रियों और कलाकारों को आमंत्रित करके मेले में जनसभाओं और सांस्कृतिक संध्याओं जैसे साइड-इवेंट का आयोजन शुरू किया।
- इसी तरह के कार्यक्रम गुजरात के 20 मंदिरों में आयोजित किए जा रहे थे और भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के आठ राज्यों में कई समारोह आयोजित किए जा रहे थे।
- सरकार उत्तर-पूर्वी राज्यों और गुजरात के कलाकारों द्वारा बनाए गए उत्पादों की विशेषता वाले हस्तशिल्प उत्सव का भी आयोजन करती है।

मेले के बारे में

- मेला, पोरबंदर से लगभग 60 किलोमीटर दक्षिण में माधवपुर के तटीय गांव में आयोजित किया जाता है और रुक्मिणी के साथ हिंदू देवता भगवान कृष्ण के विवाह का जश्न मनाता है।
- कहा जाता है कि हजारों साल पहले भगवान कृष्ण का विवाह उत्तर पूर्व की राजकुमारी रुक्मणी से हुआ था। यह शादी पोरबंदर के माधवपुर में हुई थी और उसी शादी के प्रतीक के तौर पर आज भी वहां माधवपुर मेला लगता है।
- माधवपुर मेला एक भारत, श्रेष्ठ भारत का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण बनाता है।
- माधवपुर मेला राम नवमी से शुरू होता है, जिस दिन हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार भगवान राम का जन्म होता है। हिंदू कैलेंडर में विवाह के विभिन्न अनुष्ठान त्रयोदशी या चौत्र महीने के 13 वें दिन तक चलते हैं।

महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती

खबरों में क्यों

प्रधानमंत्री ने महात्मा ज्योतिबा फुले को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी।

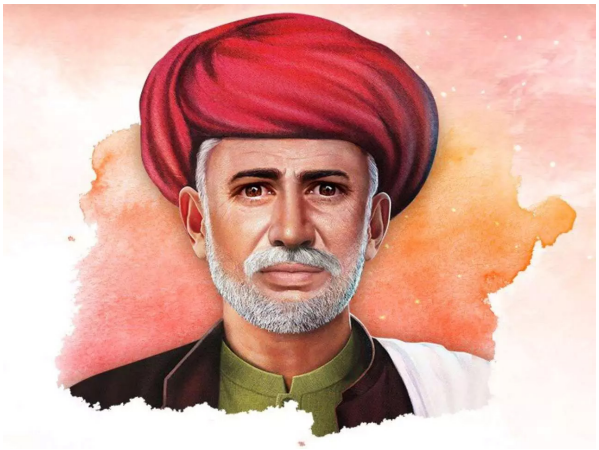

महत्वपूर्ण बिंदु

- प्रधानमंत्री ने महान समाज सुधारक, दार्शनिक और लेखक महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है।
- महाराष्ट्र के सामाजिक कार्यकर्ता और सुधारक ज्योतिराव गोविंदराव फुले के सम्मान में देश में हर साल 11 अप्रैल को ज्योतिबा फुले जयंती के रूप में मनाया जाता है।
- महात्मा फुले को अनगिनत लोगों के लिए सामाजिक न्याय और आशा के स्रोत के रूप में व्यापक रूप से सम्मानित किया जाता है और उन्होंने सामाजिक समानता, महिला सशक्तिकरण और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास किया।
- फुले ने भारत में अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था के उन्मूलन की दिशा में काम किया। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई के साथ भारत में महिलाओं की शिक्षा के लिए बीज बोए।
- नागपुर में एक स्कूटर रैली आयोजित की गई और जिले के अन्य हिस्सों में महात्मा फुले के जीवन पर प्रेरणादायक गीतों के व्याख्यान और संगीत समारोह जैसे कई अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

ज्योतिबा फुले के बारे में

- उनका जन्म 1827 में महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था।
- वह 'माली' जाति के थे और उनका मूल शीर्षक 'गोरहे' था।
- 1841 में, ज्योतिराव ने स्कॉटिश मिशन के हाई स्कूल, पूना में प्रवेश लिया और 1847 में अपनी शिक्षा पूरी की।
- मात्र 13 वर्ष की आयु में ज्योतिराव का विवाह सावित्रीबाई से हो गया।
- 1851 में ज्योतिबा ने लड़कियों के लिए एक स्कूल की स्थापना की और अपनी पत्नी से लड़कियों को स्कूल में पढ़ाने के लिए कहा।
- बाद में, उन्होंने लड़कियों के लिए दो और स्कूल और निचली जातियों के लिए एक स्वदेशी स्कूल, विशेष रूप से महारों और मांगों के लिए खोला।
- 1873 में, ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज (सत्य के साधकों का समाज) का गठन किया।
- ज्योतिराव ने हिंदुओं के प्राचीन पवित्र ग्रंथ वेदों की कड़ी निंदा की।
- उन्होंने 'तृतीय रत्न', 'ब्राह्मणंचे कसाब', 'इशारा' जैसी कुछ कहानियां लिखीं।
- गुलामगिरी 1873 में ज्योतिराव गोविंदराव फुले या महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई थी।

प्रधानमंत्री संग्रहालय

खबरों में क्यों

पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय का उदघाटन किया।

महत्वपूर्ण बिंदु

- प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता के बाद से देश के सभी प्रधानमंत्रियों को समर्पित प्रधानमंत्री संग्रहालय, या प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया।
- संग्रहालय का अनावरण, जिसे जनता के लिए खोल दिया जाएगा, चल रहे आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में हुआ।
- इस अवसर पर पीएम मोदी ने संग्रहालय का पहला प्रवेश टिकट भी खरीदा।
- प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने इस सुविधा को 'भारत के प्रत्येक प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि' के रूप में वर्णित किया।

- प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण से निर्देशित, संग्रहालय स्वतंत्रता के बाद से भारत के प्रत्येक प्रधानमंत्री के योगदान का सम्मान करता है, चाहे उनकी विचारधारा या कार्यालय कुछ भी हो।
- प्रधानमंत्री संग्रहालय दिल्ली में पुनर्निर्मित तीन मूर्ति भवन में स्थित है। यह देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निधन तक 16 साल तक उनका निवास स्थान था।
- संग्रहालय ब्लॉक-I के रूप में नामित तत्कालीन तीन मूर्ति भवन को एकीकृत करता है, जबकि नवनिर्मित भवन को ब्लॉक-II के रूप में नामित

किया गया है।

- संग्रहालय ने सामग्री में विविधता और प्रदर्शन के बार - बार रोटेशन को शामिल करने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी-आधारित इंटरफेस को नियोजित किया है।
- होलोग्राम, आभासी वास्तविकता, संवर्धित वास्तविकता, मल्टी-टच, मल्टीमीडिया, इंटरैक्टिव कियोस्क, कम्प्यूट. रीकृत काइनेटिक मूर्तियां, स्मार्टफोन एप्लिकेशन, इंट. रेक्टिव स्क्रीन, अनुभवात्मक इंस्टॉलेशन आदि प्रदर्शनी सामग्री को अत्यधिक इंटरैक्टिव और आकर्षक बनने में सक्षम बनाते हैं।
- इसके अलावा, स्वतंत्रता संग्राम पर प्रदर्शन और भारत के संविधान का निर्माण फैसिलिटी में 43 दीर्घाएं हैं।
- इसके अतिरिक्त, यह भी बताया गया कि संग्रहालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक समावेशी प्रयास है, जिसका उद्देश्य युवा पीढ़ी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों के नेतृत्व, दूरदृष्टि और उपलब्धियों के बारे में संवेदनशील और प्रेरित करना है।
- संग्रहालय की इमारत का डिजाइन उभरते भारत की कहानी से प्रेरित है, जिसे इसके नेताओं के हाथों से आकार और ढाला गया है।
- डिजाइन में टिकाऊ और ऊर्जा संरक्षण प्रथाओं को शामिल किया गया है। परियोजना पर काम के दौरान कोई पेड़ नहीं काटा गया है और न ही प्रतिरोपित किया गया है।
- संग्रहालय का लोगो राष्ट्र और लोकतंत्र का प्रतीक धर्म चक्र धारण करने वाले भारत के लोगों के हाथों का प्रतिनिधित्व करता है।
- स्वतंत्रता संग्राम और संविधान के निर्माण पर प्रदर्शन से शुरू होकर, संग्रहालय इस कहानी को बताता है कि कैसे हमारे प्रधानमंत्रियों ने विभिन्न चुनौतियों के माध्यम से देश को नेविगेट किया और देश की सर्वांगीण प्रगति सुनिश्चित की।

महावीर जयंती 2022

खबरों में क्यों

इस साल महावीर जयंती 14 अप्रैल को को मनाई जा रही है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- महावीर जयंती 24वें और अंतिम तीर्थंकर, भगवान महावीर के जन्म का प्रतीक है, जिन्होंने जैन धर्म के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- जैन धर्म के दिगंबर और श्वेतामबर मत के अनुसार, भगवान महावीर का जन्म राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के पुत्र के रूप में हुआ था।
- जैन मानते हैं कि जैन धर्म एक सनातन धर्म (है जिसमें तीर्थंकर जैन ब्रह्मांड विज्ञान के हर चक्र का मार्गदर्शन करते हैं।
- परसपरोपाग्रहो जीवनम (आत्माओं का कार्य एक दूसरे की मदद करना है) जैन धर्म का आदर्श वाक्य है, जबकि जैन धर्म में शंकर मंत्र सबसे आम और बुनियादी प्रार्थना है।
- कहा जाता है कि 30 वर्ष की आयु में, भगवान महावीर ने आध्यात्मिक जागृति की खोज में सभी सांसारिक संपत्तियों को त्याग दिया था।
- उन्होंने "केवल ज्ञान" या सर्वज्ञता प्राप्त करने से पहले 12 वर्षों तक गहन ध्यान और तपस्या का अभ्यास किया।

- माना जाता है कि वह गौतम बुद्ध के समकालीन थे।
- महावीर एक उपदेशित अहिंसा या अहिंसा, सत्य (सत्य), अस्तेय (चोरी न करने), ब्रह्मचर्य (शुद्धता) और अपरिग्रह (गैर-लगाव) में विश्वास करते थे।
- महावीर की शिक्षाओं को उनके मुख्य शिष्य इंद्रभूति गौतम ने एक साथ रखा था।
- उनकी शिक्षाओं को उनके प्रमुख शिष्य इंद्रभूति गौतम ने जैन आगम के रूप में संकलित किया था।
- सत्य और आध्यात्मिक स्वतंत्रता की तलाश में, उन्होंने 72 वर्ष की आयु में ज्ञान (निर्वाण) प्राप्त किया।
- महावीर जयंती पर धार्मिक जुलूस (रथ यात्रा) निकाले जाते हैं। जैन मंदिरों को झंडों से सजाया जाता है और गरीबों और जरूरतमंदों को प्रसाद दिया जाता है।
- जानवरों को वध से बचाने में योगदान देने के लिए

2 राजव्यवस्था एवं शासन

इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का तेज और सुरक्षित प्रसारण

खबरों में क्यों

शीर्ष अदालत ने अपने आदेशों के सुरक्षित प्रसारण के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया।

महत्वपूर्ण बिंदु

- सुप्रीम कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है कि जमानत पर उसके सभी आदेश और कैदियों की रिहाई एक सुरक्षित नेटवर्क के माध्यम से सीधे जेलों और संबंधित उच्च न्यायालयों को डिजिटल रूप से प्रेषित की जाती है जिसमें किसी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप शामिल नहीं होगा।
- 'फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स' (फास्टर) नामक सॉफ्टवेयर का उपयोग एक सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक संचार चौनल के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को शीर्ष अदालत द्वारा पारित अंतरिम आदेश, स्थगन आदेश और जमानत आदेशों को संप्रेषित करने के लिए किया जाएगा।
- सर्वोच्च न्यायालय या किसी भी न्यायालय द्वारा पारित आदेश अब किसी भी पक्ष के हस्तक्षेप के बिना सुरक्षित रूप से प्रेषित किए जा सकते हैं।
- यह हमारे आदेशों की गोपनीयता, सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। दूसरे चरण में, यह भौतिक रूप से रिकॉर्ड भी प्रेषित कर सकता है।
- सुप्रीम कोर्ट की ई-कमेटी के जजों ने एससी रजिस्ट्री के अधिकारियों के साथ मिलकर इसकी निगरानी की।
- जेलों, उच्च न्यायालयों और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के स्तर पर कुल 73 नोडल अधिकारियों को संचार के प्रसारण के लिए पॉइंट पर्सन के रूप में नामित किया गया था।
- कुल 1,887 ई-मेल आईडी एक सुरक्षित न्यायिक संचार नेटवर्क के हिस्से के रूप में बनाए गए थे, जो संबंधित अधिकारियों को एक सुरक्षित मार्ग के माध्यम से शीर्ष अदालत के डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित आदेशों को प्रेषित करने के लिए थे।

सामूहिक विनाश के हथियार अधिनियम में संशोधन

खबरों में क्यों

सामूहिक विनाश के हथियार (WMD) और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) संशोधन विधेयक पारित।

महत्वपूर्ण बिंदु

- सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) संशोधन विधेयक, 2022 लोकसभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया है।
- विधेयक सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005 में संशोधन करने का प्रयास करता है, ताकि भारत के अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के अनुरूप सामूहिक विनाश के हथियारों और उनके वितरण प्रणालियों के प्रसार के वित्तपोषण के खिलाफ प्रावधान किया जा सके।
- 2005 के अधिनियम ने सामूहिक विनाश के हथियारों के निर्माण, परिवहन, और हस्तांतरण, और उनके वितरण के साधनों पर रोक लगा दी।

सामूहिक विनाश के हथियार

- अभिव्यक्ति "सामूहिक विनाश का हथियार" (WMD) को आमतौर पर 1937 में इंग्लैंड के चर्च के नेता, कैंटरबरी के आर्कबिशप द्वारा बास्क शहर में नागरिकों की हवाई बमबारी के संदर्भ में इस्तेमाल किया गया माना जाता है। स्पेनिश गृहयुद्ध के दौरान जनरल फ्रेंको के समर्थन में जर्मन और इतालवी फासीवादियों द्वारा।

RAO'S ACADEMY for Competitive Exams (A unit of RACE)

- यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के अनुसार, "सामूहिक विनाश का एक हथियार एक परमाणु, रेडियोलॉजिकल, रासायनिक, जैविक या अन्य उपकरण है जिसका उद्देश्य बड़ी संख्या में लोगों को नुकसान पहुंचाना है।"

भारत का 2005 WMD अधिनियम परिभाषित करता है:

- ♦ माइक्रोबियल या अन्य जैविक एजेंटों के रूप में जैविक हथियार, या प्रकार के विषाक्त पदार्थ और मात्रा में जिनका रोगनिरोधी, सुरक्षात्मक या अन्य शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए कोई औचित्य नहीं है; और हथियार, उपकरण या डिलीवरी सिस्टम विशेष रूप से शत्रुतापूर्ण उद्देश्यों या सशस्त्र संघर्ष में ऐसे एजेंटों या विषाक्त पदार्थों का उपयोग करने के लिए डिजाइन किए गए हैं।
- ♦ रसायनिक हथियार जहरीले रसायनों और उनके पूर्ववर्तियों के रूप में जहां शांतिपूर्ण, सुरक्षात्मक, और कुछ निर्दिष्ट सैन्य और कानून प्रवर्तन उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है; उन जहरीले रसायनों के जहरीले गुणों के माध्यम से मौत या अन्य नुकसान पहुंचाने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए युद्धपोत और उपकरण; और कोई भी उपकरण विशेष रूप से इन युद्ध सामग्री और उपकरणों के उपयोग के संबंध में उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है।

WMDs के उपयोग पर नियंत्रण

- रसायनिक, जैविक और परमाणु हथियारों के उपयोग को कई अंतरराष्ट्रीय संधियों और समझौतों द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
- उनमें से जिनेवा प्रोटोकॉल, 1925, जो रासायनिक और जैविक हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है; और जैविक हथियार सम्मेलन, 1972, और रासायनिक हथियार सम्मेलन, 1992, जो क्रमशः जैविक और रासायनिक हथियारों पर व्यापक प्रतिबंध लगाते हैं।
- भारत ने 1972 और 1992 दोनों संधियों पर हस्ताक्षर और पुष्टि की है। इन संधियों के बहुत कम गैर-हस्ताक्षरकर्ता देश हैं, भले ही कई देशों पर गैर-अनुपालन का आरोप लगाया गया है।
- परमाणु हथियारों के उपयोग और प्रसार को परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) और व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि (सीटीबीटी) जैसी संधियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

भारत सरकार-संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग ढांचा 2023-27

खबरों में क्यों

नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र ने आगामी भारत सरकार -संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग फ्रेमवर्क 2023-27 पर कार्यशाला आयोजित की।

महत्वपूर्ण बिंदु

- नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र ने आगामी भारत सरकार-संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग फ्रेमवर्क (UNSDCF) 2023-27 पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सत्यापन कार्यशाला का आयोजन किया।
- यह पहली ऐसी मण्डली थी जिसमें 30 केंद्रीय मंत्रालयों के अधिकारियों, 26 संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के प्रमुखों और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।
- पिछला भारत सरकार-यूएनएसडीएफ 2018-22 राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने के लिए सहयोग, परिणाम और रणनीतियों का एजेंडा था।
- भारत में संयुक्त राष्ट्र की कुल 26 संस्थाओं की योजनाओं और कार्यक्रमों को कैप्चर करने वाला एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण साधन है।
- जैसे ही 2018-22 की रूपरेखा अपने कार्यान्वयन के अंतिम वर्ष में प्रवेश कर गई, भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र ने इसे अगले पांच वर्षों, 2023-27 के लिए नवीनीकृत करने के लिए प्रतिबद्ध किया।
- भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने पर 2023-27 सहयोग ढांचे पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
- भारत की राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए, नीति आयोग ने अगले पांच वर्षों में 'संपूर्ण सरकार' और 'संपूर्ण संयुक्त राष्ट्र' के अभिसरण का आह्वान किया।
- नीति आयोग ने बताया कि कार्यशाला 'नए भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें और अधिक मजबूत और प्रासंगिक बनाने के लिए भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र के बीच साझेदारी के विभिन्न रूपों को फिर से देखने और पुनर्जीवित करने का

RAC'S ACADEMY for Competitive Exams (A unit of RAC'S)

एक अवसर' था।

- नीति आयोग ने 2023-27 के ढांचे को अंतिम रूप देते हुए नवोन्मेषी और भविष्यवादी सोच की आवश्यकता पर बल दिया।
- नीति आयोग ने कहा कि 'इस कार्यशाला की सफलता अगले पांच वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र भारत की टीम के साथ किए जाने वाले सामूहिक कार्य के लिए टोन सेट करेगी'।
- 2018-22 के ढांचे की मुख्य उपलब्धियों में से एक कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भारत सरकार के साथ संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों की भागीदारी रही है।
- अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने, आवश्यक दवाएं और चिकित्सा आपूर्ति देने, दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को सुविधाजनक बनाने से लेकर नीतिगत सहायता प्रदान करने और सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं को लाने तक, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने कोविड संकट के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- 2023-27 की रूपरेखा का लक्ष्य 2030 एजेंडा के चार स्तंभों- लोग, समृद्धि, ग्रह और भागीदारी- को भारत की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ संरेखित करना और देश भर में काम कर रहे संयुक्त राष्ट्र की सभी संस्थाओं के प्रयासों को दिशा प्रदान करना है।

नए ढांचे ने छह परिणाम क्षेत्रों की पहचान की है:

i. स्वास्थ्य और कल्याण

ii. पोषण और भोजन

iii. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

iv. आर्थिक विकास और अच्छा काम

v. पर्यावरण, जलवायु, धुलाई और लचीलापन

vi. लोगों, समुदायों और संस्थानों को सशक्त बनाना।

- 2023-27 के ढांचे में अधिक लचीला, समावेशी और टिकाऊ भारत के लिए साझा दृष्टिकोण और रणनीतियां शामिल होंगी।
- जबकि नीति आयोग और संबंधित मंत्रालय केंद्रीय स्तर पर ढांचे का संचालन करेंगे, राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश इस दृष्टिकोण को साकार करने और रणनीतियों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

विमान वस्तुओं में हितों का संरक्षण और प्रवर्तन विधेयक, 2022

खबरों में क्यों

हाल ही में, मंत्रालय ने विमान वस्तु विधेयक, 2022 में हितों के संरक्षण और प्रवर्तन के मसौदे पर हितधारकों की टिप्पणियां मांगी हैं।

महत्वपूर्ण बिंदु

- नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक नए कानून का प्रस्ताव किया है जो अंतरराष्ट्रीय विमान पट्टे पर देने वाली कंपनियों को भारतीय एयरलाइन के साथ वित्तीय विवाद के मामले में भारत से बाहर विमानों को वापस लेने और स्थानांतरित करने में मदद करेगा, एक समय में कई क्षेत्रीय एयरलाइनों को किराए पर विमानों से इनकार कर दिया गया है।
- भारत के केपटाउन कन्वेंशन में शामिल होने के 14 साल बाद प्रस्तावित कानून आया है।
- मंत्रालय ने विमान वस्तु विधेयक, 2022 में हितों के संरक्षण और प्रवर्तन के मसौदे पर हितधारकों की टिप्पणियां मांगी हैं।
- बिल मोबाइल उपकरण और प्रोटोकॉल में अंतर्राष्ट्रीय हितों पर कन्वेंशन के प्रावधानों को लागू करता है
- विमान उपकरण के लिए विशिष्ट मामले जिसे 2001 में केप टाउन में एक सम्मेलन में अपनाया गया था।
- भारत ने 2008 में दो लिखतों को स्वीकार किया। ये लेनदार के लिए डिफॉल्ट उपचार प्रदान करते हैं और विवादों के लिए एक कानूनी व्यवस्था बनाते हैं।
- मंत्रालय का कहना है कि मसौदा कानून आवश्यक है क्योंकि कई भारतीय कानून जैसे कंपनी अधिनियम, 2013 और दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 केप टाउन कन्वेंशन और प्रोटोकॉल के विपरीत हैं।
- इसमें कहा गया है कि भारतीय संस्थाओं को भी नुकसान हुआ है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान एक कार्यान्वयन कानून की मांग करते हैं।
- प्रस्तावित कानून किसी विमान वस्तु को वापस लेने, या उसकी बिक्री या पट्टे या इसके उपयोग से होने वाली आय के संग्रह के साथ-साथ डी-पंजीकरण और विमानों के निर्यात जैसे उपायों का प्रावधान करता है।

RAO's ACADEMY for Competitive Exams (A unit of RACE)

- यह एक दावे के अंतिम न्यायनिर्णयन के लंबित उपायों के साथ-साथ अपने भारतीय खरीदार के खिलाफ दिवाला कार्यवाही के दौरान एक देनदार के दावे की रक्षा करने का भी सुझाव देता है।
- कई छोटी एयरलाइनों को पट्टे पर विमान प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण हो रहा है क्योंकि पट्टेदारों को बहुत अधिक जोखिम दिखाई देता है क्योंकि संपत्ति की वसूली की लागत अत्यधिक और समय लेने वाली होती है।
- जब जेट एयरवेज 2019 में बंद हो गई और अपने विमान के किराए का भुगतान करने में विफल रही, तो अंतरराष्ट्रीय पट्टे पर देने वाली कंपनियों को भी विमानों को वापस लेने और निर्यात करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

केप टाउन कन्वेंशन

- मोबाइल उपकरण में अंतर्राष्ट्रीय हितों पर कन्वेंशन 16 नवंबर 2001 को केप टाउन में संपन्न हुआ, जैसा कि विमान उपकरण के लिए विशिष्ट मामलों पर प्रोटोकॉल था।
- कन्वेंशन और प्रोटोकॉल का प्राथमिक उद्देश्य उच्च मूल्य वाली विमानन संपत्तियों, जैसे एयरफ्रेम, एयरक्राफ्ट इंजन और हेलीकॉप्टरों के लिए कुछ निश्चित और विरोधी अधिकार प्राप्त करने की समस्या का समाधान करना है, जिनकी प्रकृति में कोई निश्चित स्थान नहीं है।
- यह समस्या मुख्य रूप से इस तथ्य से उत्पन्न होती है कि कानूनी प्रणालियों में प्रतिभूतियों, शीर्षक प्रतिधारण समझौतों और पट्टा समझौतों के लिए अलग-अलग दृष्टिकोण हैं, जो उधार देने वाले संस्थानों के लिए उनके अधिकारों की प्रभावकारिता के बारे में अनिश्चितता पैदा करता है।
- यह ऐसी विमानन परिसंपत्तियों के लिए वित्तपोषण के प्रावधान को बाधित करता है और उधार लेने की लागत को बढ़ाता है।

कन्वेंशन और प्रोटोकॉल के लाभ

पूर्वानुमेयता और प्रवर्तनीयता: सभी अनुबंधित राज्या. में मान्यता प्राप्त एक अंतरराष्ट्रीय हित बनाकर और एक अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक ब्याज पंजीकरण प्रणाली की स्थापना करके, कन्वेंशन और प्रोटोकॉल प्रतिभूतियों के विरोध और विमानन संपत्ति के विक्रेताओं द्वारा आयोजित ब्याज के संबंध में पूर्वानुमेयता में सुधार करते हैं।

लागत बचत: कन्वेंशन और प्रोटोकॉल का उद्देश्य लेनदारों के लिए जोखिम को कम करना है, और परिणाम स्वरूप, देनदारों को उधार लेने की लागत, परिणामस्वरूप बेहतर कानूनी निश्चितता के माध्यम से। यह अधिक आधुनिक और इस प्रकार अधिक ईंधन कुशल विमानों के अधिग्रहण के लिए ऋण देने को बढ़ावा देता है।

सम्मेलन के चार प्रोटोकॉल चार प्रकार के चल उपकरणों के लिए विशिष्ट हैं:

- विमान उपकरण (विमान और विमान इंजन; 2001 में हस्ताक्षरित)।
- रेलवे रोलिंग स्टॉक (2007 में हस्ताक्षरित)।
- अंतरिक्ष संपत्तियां (2012 में हस्ताक्षरित)।
- खनन कृषि और निर्माण उपकरण (2019 में हस्ताक्षरित)।

प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र

खबरों में क्यों

सरकार ने मार्च 2024 तक जनऔषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 10,000 करने का लक्ष्य रखा है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) की कार्यान्वयन एजेंसी, फार्मास्युटिकल्स एंड मेडिकल

डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया (पीएमबीआई) ने प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र (पीएमबीजेके) खोलने के लिए व्यक्तियों, बेरोजगार फार्मासिस्ट,

सरकार द्वारा नामित एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों, ट्रस्ट, सोसायटी आदि से आवेदन आमंत्रित किए हैं।

- आवेदन एक ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आमंत्रित किए गए हैं। पात्र आवेदकों को **पहले आओ पहले आओ** के आधार पर पीएमबीजेपी के नाम पर ड्रग लाइसेंस लेने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी जाएगी।
- आम आदमी विशेष रूप से गरीबों के लिए सस्ती दर पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से, सरकार मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्रों (पीएमबीजेके) की संख्या बढ़ाकर 10,000 करने का लक्ष्य रखा है।
- पीएमबीजेपी के तहत देश के सभी 739 जिलों को कवर किया गया है, इन 406 जिलों के 3579 प्रखंडों को कवर करने के लिए नए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
- छोटे शहरों और प्रखंड मुख्यालयों के निवासी अब जन औषधि केंद्र खोलने के अवसर का लाभ उठा सकते हैं।
- यह योजना महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, पहाड़ी जिलों, द्वीप जिलों और पूर्वोत्तर राज्यों सहित विभिन्न श्रेणियों के लिए प्रोत्साहन/विशेष प्रोत्साहन प्रदान करती है। इससे देश के कोने-कोने में लोगों तक सस्ती दवा की पहुंच आसान होगी।
- पीएमबीजेपी के उत्पाद समूह में 1616 दवाएं और 250 सर्जिकल उपकरण शामिल हैं जो देश भर में कार्यरत 8600 से अधिक प्रधान मंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्रों (पीएमबीजेके) के माध्यम से बिक्री के लिए उपलब्ध हैं।
- इसके अलावा, कुछ आयुष उत्पादों जैसे आयुष किट, बलरक्षा किट और आयुष-64 टैबलेट को प्रतिरक्षा बूस्टर के रूप में परियोजना के उत्पाद समूह में जोड़ा गया है जिसे चयनित केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है।
- उत्पाद बास्केट में सभी प्रमुख चिकित्सीय समूह शामिल हैं जैसे हृदयवाहिनी, कैंसर रोधी, मधुमेह रोधी, संक्रमण रोधी, एलर्जी रोधी, जठरांत्र संबंधी दवाएं, न्यूट्रास्युटिकल्स आदि।
- इसके अलावा, पीएमबीआई एफएसएसएआई के तहत फास्ट-मूविंग कंज्यूमर गुड्स (एफएमसीजी) उत्पादों और खाद्य उत्पादों और पीएमबीजेपी के तहत अत्यधिक मांग वाले आयुर्वेदिक उत्पादों के लॉन्च पर काम कर रहा है ताकि उनके उत्पाद समूह का विस्तार किया जा सके।

पीएमबीजेपी के बारे में

- प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) फार्मास्युटिकल विभाग द्वारा जनता को सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया एक अभियान है।
- जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए पीएमबीजेपी स्टोर स्थापित किए गए हैं, जो कम कीमतों पर उपलब्ध हैं लेकिन महंगी ब्रांडेड दवाओं की तरह गुणवत्ता और प्रभावकारिता के बराबर हैं।

उद्देश्य

- ♦ जेनेरिक दवाओं के बारे में जनता में जागरूकता पैदा करना।
- ♦ मेडिकल प्रैक्टिशनरों के माध्यम से जेनेरिक दवाओं की मांग पैदा करना।
- ♦ शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से जागरूकता पैदा करना कि उच्च मूल्य उच्च गुणवत्ता का पर्याय नहीं होना चाहिए।
- ♦ सभी चिकित्सीय समूहों को कवर करने वाली सभी सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली जेनेरिक दवाएं प्रदान करें।
- ♦ योजना के तहत सभी संबंधित स्वास्थ्य देखभाल उत्पाद भी प्रदान करें।

पीएमबीजेपी का लाभ

- ♦ जन औषधि पहल जेनेरिक दवाओं को बेचने वाले समर्पित स्टोरों के माध्यम से सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराएगी जो कम कीमतों पर उपलब्ध हैं लेकिन महंगी ब्रांडेड दवाओं के रूप में गुणवत्ता और प्रभावकारिता के बराबर हैं।
- ♦ किफायती दवाओं और उनके नुस्खे के बारे में अधिक जागरूकता को बढ़ावा देना।
- ♦ सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से सस्ती कीमतों पर गैर-ब्रांडेड गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराएं।

RAO'S ACADEMY for Competitive Exams (A unit of RACE)

- ♦ डॉक्टरों को, विशेष रूप से सरकारी अस्पताल में जेनेरिक दवाएं लिखने के लिए प्रोत्साहित करें।
- ♦ स्वास्थ्य देखभाल में पर्याप्त बचत करना, विशेष रूप से गरीब रोगियों और पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोगों के मामले में जिन्हें लंबे समय तक नशीली दवाओं के उपयोग की आवश्यकता होती है।

प्रतिनिधित्व में कोटा

खबरों में क्यों

केंद्र सरकार ने विभागों से एससी, एसटी के प्रतिनिधित्व पर डेटा एकत्र करने को कहा।

महत्वपूर्ण बिंदु

- केंद्र सरकार ने सभी विभागों को कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की नीति को लागू करने से पहले अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता पर डेटा एकत्र करने के लिए कहा है।
- इसने विभागों को पदोन्नति के लिए विचार किए जा रहे अधिकारियों की उपयुक्तता का सावधानीपूर्वक आकलन करने के लिए भी कहा है।
- एक आदेश में, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने सुप्रीम कोर्ट के एक जनवरी के आदेश का हवाला दिया, जिसमें कुछ शर्तों को रेखांकित किया गया था जिन्हें सरकार द्वारा पदोन्नति में आरक्षण की नीति को लागू करने के उद्देश्य से पूरा किया जाना है।
- इन शर्तों में "अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता के संबंध में मात्रात्मक डेटा का संग्रह" शामिल है।
- सभी मंत्रालयों/विभागों को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि पदोन्नति में आरक्षण की नीति को लागू करने और उसके आधार पर किसी भी पदोन्नति को करने से पहले उपरोक्त शर्तों का पालन किया जाता है।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रशासन की दक्षता बनी रहे, डीपीसी (विभागीय पदोन्नति समिति) पदोन्नति के लिए विचार किए जा रहे अधिकारियों की उपयुक्तता का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करेगी।
- केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) फोरम ने जनवरी में डीओपीटी से अपने सदस्यों के लंबे समय से रुके हुए पदोन्नति को तुरंत फिर से शुरू करने का आग्रह किया था।
- सीएसएस फोरम सीएसएस के अधिकारियों का एक संघ है, जिसके सदस्य केंद्रीय सचिवालय के कामकाज की रीढ़ होते हैं।
- सरकारी अधिकारियों के संघ, सीएसएस फोरम के अनुसार, केंद्र सरकार के कार्यालयों में अनुभाग अधिकारी, अवर सचिव, उप सचिव, निदेशक और संयुक्त सचिव स्तर के 6,210 अधिकारी हैं। इस कुल संख्या में से 1,839 पद रिक्त हैं क्योंकि अधिकारियों को पदोन्नत नहीं किया गया है।

अटॉर्नी जनरल का मत है कि पदोन्नति में आरक्षण की नीति को लागू करते समय तीन शर्तों को पूरा करना होता है।

i. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता के संबंध में मात्रात्मक डेटा का संग्रह;

ii. इस डेटा को प्रत्येक संवर्ग के लिए अलग से लागू करना; और

iii. यदि कोई रोस्टर मौजूद है, तो रोस्टर के संचालन की इकाई संवर्ग होगी या जिसे रोस्टर में रिक्तियों को भरने के संबंध में मात्रात्मक डेटा एकत्र और लागू करना होगा।

देशद्रोह का मुद्दा

खबरों में क्यों

शरद पवार ने हाल ही में भीमा कोरेगांव जांच आयोग के समक्ष अपने हलफनामे से हलचल मचा दी थी।

महत्वपूर्ण बिंदु

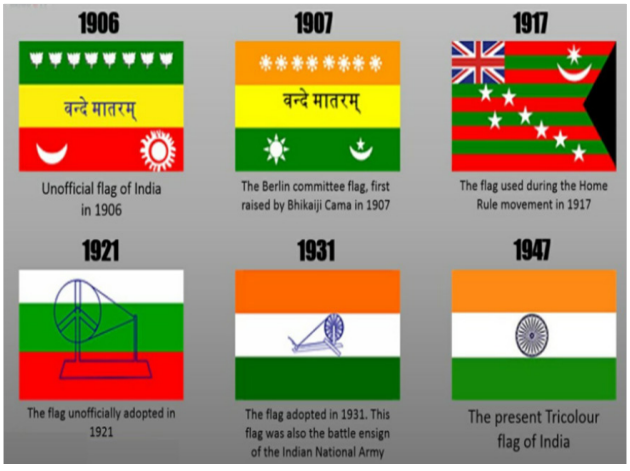

RAU'S ACADEMY for Competitive Exams (A unit of RACE)

- एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भीमा कोरेगांव जांच आयोग के समक्ष अपने हलफनामे से हड़कंप मचा दिया।
- उन्होंने जोर देकर कहा कि पुरातन राजद्रोह कानून को निरस्त किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) जैसे कानून हैं जो इन गतिविधियों से प्रभावी ढंग से निपट सकते हैं।
- भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 124ए सरकार को गिराने की कोशिश के लिए राजद्रोह के आरोपों से संबंधित है। यह अपराध आजीवन कारावास से दंडनीय है और अभियुक्त को मुकदमे के दौरान भी जमानत मिलने की कोई संभावना नहीं है।
- पवार ने इस बात पर जोर दिया कि IPC की धारा 124A का अक्सर उन लोगों के खिलाफ दुरुपयोग किया जाता है जो सरकार की आलोचना करते हैं, उनकी स्वतंत्रता को दबाते हैं, और शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से उठाई गई असहमति की किसी भी आवाज को दबा देते हैं और इसे निरस्त कर दिया जाना चाहिए।
- वकीलों का एक वर्ग राकांपा प्रमुख की भावनाओं को प्रतिनिधित्व करता है, इस बात की वकालत करता है कि इन दिनों इस खंड का अधिक दुरुपयोग किया जा रहा है; सरकार की आलोचना करने वाले किसी भी व्यक्ति को कड़े राजद्रोह के तहत गिरफ्तार किया जाता है।
- देशद्रोह की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले अपराधों से निपटने के लिए अलग-अलग धाराएं हैं - देश के खिलाफ युद्ध छेड़ना, समुदायों के बीच नफरत पैदा करना, लोगों को हिंसा के लिए उकसाना और अन्य।
- आईपीसी की धारा 124A (देशद्रोह) और 153 (वर्गों के बीच वैमनस्य को बढ़ावा देना) की व्याख्या की आवश्यकता है, खासकर प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में।
- हालांकि अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि अकेले कानून का दुरुपयोग इसे अमान्य नहीं बनाता है, इसके दुरुपयोग की अंतर्निहित क्षमता के कारण धारा 124A को रद्द करने का एक विशेष मामला है।
- सभी व्यवस्थाओं के बीच व्यवहार का एक पैटर्न है जो किसी भी मामले के तथ्यों के लिए इसकी प्रयोज्यता की जांच किए बिना इसे लागू करने की प्रवृत्ति का संकेत देता है।
- हाल के मामलों से पता चलता है कि राजद्रोह का इस्तेमाल तीन राजनीतिक कारणों से किया जाता है: सरकार की विशेष नीतियों और परियोजनाओं के खिलाफ आलोचना और विरोध को दबाने के लिए, मानवाधिकार रक्षकों, वकीलों, कार्यकर्ताओं और पत्रकारों से असहमति की राय को अपराधीकरण करने के लिए, और राजनीतिक स्कोर को निपटाने के लिए, कभी-कभी सांप्रदायिक रंग के लिए।
- यह नहीं भूलना चाहिए कि इस धारा को 1962 में संविधान पीठ द्वारा मुख्य रूप से "घृणा या अवमानना में लाना", या "कानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति असंतोष पैदा करना" शब्दों के आयात को पढ़कर बरकरार रखा गया था और इसकी सीमा को सीमित कर दिया गया था। केवल भाषण या लेखन के उन उदाहरणों की गुंजाइश है जो सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने के लिए एक हानिकारक प्रवृत्ति दिखाते हैं।
- 2016 में, सरकार ने खुद संसद में स्वीकार किया कि राजद्रोह की परिभाषा बहुत व्यापक है और इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है।
- विधि आयोग ने 2018 में एक परामर्श पत्र भी जारी किया जिसमें कहा गया था कि "लोकतंत्र में, एक ही गीत की किताब से गाना देशभक्ति का मानदंड नहीं है। लोगों को अपने तरीके से अपने देश के प्रति अपना स्नेह दिखाने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए।"
- जबकि नए दिशा-निर्देश और सुरक्षा उपाय जारी करना इसके दुरुपयोग की संभावना को कम करने का एक तरीका है, यह अधिक मददगार होगा यदि धारा 124A को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए।

फ्लैग कोड

खबरों में क्यों

झंडा संहिता में संशोधन से खादी कार्यकर्ता नाराज।

महत्वपूर्ण बिंदु

- खादी संघों, कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय ध्वज के लिए

RAO'S ACADEMY for Competitive Exams (unit of RAO'S) YOUR SUCCESS OUR PRIORITY

गैर-खादी सामग्री की अनुमति देने के कदम पर पीएम और एचएम को पत्र लिखा।

- हर बार नई दिल्ली में लाल किले पर तिरंगा फहराया गया, उत्तर कर्नाटक के लोगों के पास गर्व महसूस करने का एक कारण था, क्योंकि हुबली में देश की एकमात्र बीआईएस-अनुमोदित ध्वज निर्माण इकाई में हाथ से बुने हुए खादी ध्वज को बनाया गया था।
- हाल ही में, राष्ट्रीय ध्वज संहिता में संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार का कदम, पॉलिएस्टर और आयातित कपड़े की अनुमति देना, कई लोगों के लिए एक झटके के रूप में आया है।
- खादी कार्यकर्ता एक संशोधन करने के लिए केंद्र के खिलाफ हैं, जिसे वे "अपवित्र" मानते हैं।
- उनका तर्क है कि यह कदम न केवल खादी की परिभाषा को कमजोर करेगा बल्कि स्वतंत्रता संग्राम की भावना को भी कमजोर करेगा।
- भारत के ध्वज संहिता 2002 के भाग 1 के नियम 1. 2 के अनुसार, ध्वज के लिए केवल खादी या हाथ से काता हुआ कपड़ा ही सामग्री थी।
- अन्य सामग्री का उपयोग दंडनीय था। लेकिन हाल के संशोधन ने इसे बदल कर "राष्ट्रीय ध्वज हाथ से काता और हाथ से बुने हुए या मशीन से बने, कपास, पॉलिएस्टर, ऊन, रेशम खादी बंटिंग से बना होगा।"
- इसका मतलब है कि मशीन से बना पॉलिएस्टर जो भारत में बनता है या कहीं और से आयात किया जाता है, अब तिरंगे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

चिंता

- इस कदम का कड़ा विरोध करते हुए, हुबली के बेंगेरी में कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्ता संघ (केकेजीएसएस), जो कि बीआईएस-अनुमोदित झंडा बनाने वाली इकाई है, ने पहले ही प्रधान मंत्री और भारत के गृह मंत्री को पत्र लिखा है।
- संशोधन उन हजारों गरीब ग्रामीण महिलाओं की आजीविका छीन लेगा जो खादी कपड़ा उत्पादन, मरने और झंडे सिलने के विभिन्न चरणों में लगी हुई हैं।

YOUR SUCCESS OUR PRIORITY
RAO'S ACADEMY
for Competitive Exams
(A unit of RACE)

3 भूगोल, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA)

खबरों में क्यों

राष्ट्रीय राजधानी के बाहर पहली बार NTCA की बैठक अरुणाचल प्रदेश में हुई

महत्वपूर्ण बिंदु

- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) की 20वीं बैठक अरुणाचल प्रदेश के पक्के बाघ अभ्यारण्य में आयोजित की गई।
- अरुणाचल हॉर्नबिल नेस्ट एडॉप्शन और एयर गन सरेंडर अभियान जैसे कार्यक्रमों के साथ अनुकरण करने के लिए एक मॉडल प्रस्तुत करता है।
- केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा अरुणाचल प्रदेश में 20वें एनटीसीए की अध्यक्षता की गयी।
- केंद्रीय मंत्री द्वारा बाघों के पुनरुत्पादन और जंगली में पूरकता के लिए मानक संचालन प्रक्रिया, बाघ अभयारण्यों के लिए वन अग्नि लेखा परीक्षा प्रोटो. कॉल, एनटीसीए द्वारा तैयार भारत में बाघ अभयारण्यों के MEE पर तकनीकी मैनुअल का विमोचन किया गया।
- केंद्रीय मंत्री ने वन क्षेत्र और बाघ अभ्यारण्य के संरक्षण और बेहतर विकास के लिए स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी पर भी जोर दिया।

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए)

- एनटीसीए का गठन वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38 एल (1) के तहत किया गया है।
- यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है।
- इसकी स्थापना 2005 में टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिशों के बाद की गई थी।
- 2018 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में जंगली में 2,967 बाघ हैं, जिनमें से आधे से अधिक मध्य प्रदेश और कर्नाटक में हैं।

पक्के टाइगर रिजर्व

- पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामेंग जिले में स्थित है।
- यह उत्तर में टेंगा रिजर्व फॉरेस्ट, पश्चिम में दोइमारा रिजर्व फॉरेस्ट, दक्षिण में नामेरी नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व (असम) और कुछ कृषि भूमि के साथ-साथ पूर्व में पापुम रिजर्व फॉरेस्ट से घिरा हुआ है।
- यह चार निवासी हॉर्नबिल प्रजातियों के अद्भुत दृश्य के लिए जाना जाता है।
- टाइगर रिजर्व ने अपने हॉर्नबिल नेस्ट एडॉप्शन प्रोग्राम के लिए 'संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण' की श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2016 भी जीता है।

फोर्टिफाइड चावल

खबरों में क्यों

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तीन चरणों में फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति को मंजूरी देने की घोषणा की।

महत्वपूर्ण बिंदु

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति के लिए अपनी मंजूरी दे दी है:

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस)
- एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस)
- प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण-पीएम पोषणऔर
- सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UT) में भारत सरकार की अन्य कल्याण योजनाएं (OWS) 2024 तक चरणबद्ध तरीके से।

फोर्टिफाइड चावल की पूरी लागत (लगभग 2,700 करोड़ रुपये प्रति वर्ष) भारत सरकार द्वारा जून, 2024 तक (इसके पूर्ण कार्यान्वयन तक) खाद्य सब्सिडी के हिस्से के रूप में वहन की जाएगी।

पहल के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित तीन चरणों की परिकल्पना की गई है:

चरण- I: मार्च, 2022 तक पूरे भारत में आईसीडीएस और

YOUR SUCCESS IS OUR PRIORITY
RAO's ACADEMY
for Competitive Exams
(A unit of RACE)

पीएम पोषण को कवर करना जो कार्यान्वयन के अधीन है। चरण- II: मार्च 2023 तक स्टेंटिंग (कुल 291 जिलों) पर सभी आकांक्षी और ज्यादा बोझ वाले जिलों में प्लस टीपीडीएस और ओडब्ल्यूएस से ऊपर का चरण-I।
चरण-IIप्लस: ऊपर चरण-II प्लस मार्च 2024 तक देश के शेष जिलों को कवर करना।

- इससे पहले, "सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चावल का फोर्टिफिकेशन और उसका वितरण" पर केंद्र प्रायोजित पायलट योजना 2019-20 से शुरू होकर 3 साल की अवधि के लिए लागू की गई थी।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च 2023 तक अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) को जारी रखने की भी मंजूरी दी।
- ग्यारह (11) राज्य- आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और झारखंड ने पायलट योजना के तहत अपने चिन्हित जिलों (प्रति राज्य एक जिला) में फोर्टिफाइड चावल का सफलतापूर्वक वितरण किया।

फोर्टिफाइड चावल

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसए आई) ने फोर्टिफिकेशन को "भोजन में आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों की सामग्री को जानबूझकर बढ़ाना ताकि भोजन की पोषण गुणवत्ता में सुधार किया जा सके और स्वास्थ्य के लिए न्यूनतम जोखिम के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया जा सके" के रूप में परिभाषित किया गया है।

- चावल का सुदृढ़ीकरण नियमित चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों को जोड़ने की एक प्रक्रिया है। सूक्ष्म पोषक तत्वों को आहार आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जोड़ा जाता है।
- चावल की मजबूती के लिए विभिन्न तकनीकें उपलब्ध हैं, जैसे कोटिंग और डस्टिंग। भारत में चावल की मजबूती के लिए 'एक्सट्रूजन' को सबसे अच्छी तकनीक माना जाता है। इसमें एक एक्सट्रूडर मशीन का उपयोग करके मिश्रण से गढ़वाले चावल की गुठली (FRKs) का उत्पादन शामिल है।

बंगाल तट करता है सर्वाधिक कटाव का सामना

खबरों में क्यों

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अनुसार,"लगभग 34% भारतीय समुद्र तट खतरे की अलग-अलग डिग्री के अधीन है।"

महत्वपूर्ण बिंदु

- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने एक प्रश्न के उत्तर में लोकसभा को सूचित किया कि मुख्य भूमि की 6,907.18 किमी लंबी भारतीय तटरेखा में से लगभग

State	Coast Length(km)	Erosion (km)	Percentage
Gujarat	1945.60	537.5	27.6 %
Daman & Diu	31.83	11.02	34.6 %
Maharashtra	739.57	188.26	25.5 %
Goa	139.64	26.82	19.2 %
Karnataka	313.02	74.34	23.7 %
Kerala	592.96	275.33	46.4 %
Tamil Nadu	991.47	422.94	42.7 %
Puducherry	41.66	23.42	56.2%

34% कटाव की अलग-अलग डिग्री के अधीन है जबकि समुद्र तट का 26% अभिसरण प्रकृति और शेष 40% स्थिर अवस्था में है।

- नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च (एनसीसीआर), चेन्नई, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) का एक संलग्न कार्यालय, रिमोट सेंसिंग डेटा और जीआईएस मैपिंग तकनीकों का उपयोग करके 1990 से तटरेखा क्षरण की निगरानी कर रहा है।
- 1990 से 2018 तक मुख्य भूमि की लगभग 6,907.18 किलोमीटर लंबी भारतीय तटरेखा का विश्लेषण किया गया है।
- प्रतिशत के संदर्भ में, देश के पूर्वी तट पर स्थित पश्चिम बंगाल, जिसकी 534.35 किमी लंबी तटरेखा है, को 1990 से 2018 की अवधि में लगभग 60.5% तट (323.07 किमी) के साथ कटाव का सामना करना पड़ा।
- इसके बाद पश्चिमी तट पर केरल आता है, जिसकी तटरेखा 592.96 किमी है और इसका 46.4% (275. 33 किमी) कटाव का सामना करना पड़ा है। तमिलनाडु, 991.47 किमी की लंबी तटरेखा के साथ, इसके 42.7% (422.94 किमी) के साथ कटाव दर्ज किया गया।
- गुजरात, जिसकी सबसे लंबी तटरेखा 1,945.60 किमी है, ने इसके 27.06% (537.5 किमी) के

RAO'S ACADEMY for Competitive Exams (A Unit of RAO'S)

साथ कटाव दर्ज किया। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में, 41.66 किमी लंबी तटरेखा के साथ, इसके तट का लगभग 56.2% (23.42 किमी) कटाव दर्ज किया गया है।

- एमओईएस के तहत एक अन्य संगठन, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज (आइएनसीओआईएस) ने समुद्र तल पर डेटा का उपयोग करते हुए 1:100000 पैमाने पर भारत की संपूर्ण तटरेखा के लिए तटीय सुभेद्यता सूचकांक (सीवीआई) मानचित्रों का एक एटलस तैयार और प्रकाशित किया है। इसके माध्यम से वृद्धि, तटीय ढलान, तटरेखा परिवर्तन दर, तटीय ऊंचाई, तटीय भू-आकृति विज्ञान, ज्वार की सीमा और महत्वपूर्ण लहर ऊंचाई, मंत्रालय ने संसद को सूचित किया।
- 'भारतीय तट के साथ तटरेखा परिवर्तन का राष्ट्रीय आकलन' पर एक रिपोर्ट जुलाई, 2018 में जारी की गई थी और तटरेखा सुरक्षा उपायों को लागू करने के लिए विभिन्न केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों और हितधारकों के साथ साझा की गई थी।
- सभी मानचित्रों की डिजिटल और हार्ड कॉपी 25 मार्च, 2022 को जारी की गई। मंत्रालय अपने संस्थानों के माध्यम से तटीय कटाव के खतरों से निपटने के लिए राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को तकनीकी समाधान और सलाह भी दे रहा है।

ऑरोरा

खबरों में क्यों

'मृत' सनस्पॉट फटने के बाद आइसलैंड के ऊपर आश्चर्य. जनक ऑरोरा चमक देखी गयी।

महत्वपूर्ण बिंदु

- एक सनस्पॉट जो पिछले हफ्ते "मृतकों में से जाग गया" और मध्यम आकार के सौर फ्लेयर के साथ उग आया, साथ ही प्लाज्मा के बड़े पैमाने पर उत्सर्जन ने भी उत्तरी आसमान को चमकदार रोशनी में प्रकाशित किया।
- प्रभाव की एक आश्चर्यजनक छवि ने ऑरोरा को आइसलैंड के ऊपर बादलों के माध्यम से बारिश करते हुए दिखाया।
- चमकदार उत्तरी रोशनी मध्यम आकार के सौर तूफान से उत्पन्न हुई थी, जो उपग्रहों द्वारा देखे गए सौर कणों के विस्फोट से जुड़ी थी।
- जिस सनस्पॉट में विस्फोट हुआ उसे काव्यात्मक रूप से "मृत" करार दिया गया क्योंकि यह हाल ही में प्रस्फुटित हुआ था,यह एक शांत सौर पैच का हिस्सा बन गया था।
- फिर भी, जब उन सौर कणों ने पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के साथ सम्पर्क कर वायुमंडल में उच्च वायु के अणु उत्तेजित हो गए, जिससे अविश्वसनीय स्काई शो का निर्माण हुआ।

ऑरोरा:

- ऑरोरा एक प्राकृतिक घटना है जो आकाश में एक प्राकृतिक रंग (हरा, लाल, पीला या सफेद) प्रकाश के प्रदर्शन की विशेषता है।
- यह एक प्रकाश शो है जो तब होता है जब सूर्य से विद्युत-आवेशित कण पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसी गैसों के कणों से टकराते हैं।
- इसे कभी-कभी 'ध्रुवीय प्रकाश' कहा जाता है। यह मुख्य रूप से आर्कटिक और अंटार्कटिक जैसे उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखा जाता है।
- वे आम तौर पर 'अरोरल जोन' नामक एक बैंड में होते हैं। ऑरोरल जोन अक्षांश में 3 से 6 डिग्री चौड़ा है। यह भू-चुंबकीय ध्रुवों से 10 से 20 डिग्री के बीच स्थित है।

अलग - अलग प्रकार:

- ऑरोरा विभिन्न रूपों में प्रकट हो सकते हैं जैसे कि स्ट्रीमर, पैच, आर्क, बिखरी हुई रोशनी, विसरित प्रकाश आदि। इस प्राकृतिक प्रकाश प्रभाव को उत्तरी ऊंचाई में 'ऑरोरा बोरेलिस' के रूप में जाना जाता है, जबकि दक्षिणी अक्षांशों में प्रभाव को 'ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस' के रूप में जाना जाता है। .
- उत्तरी गोलार्ध में होने वाले ऑरोरा को ऑरोरा बोरेलिस के रूप में जाना जाता है और ऑरोरा जो दक्षिणी गोलार्ध में होता है उसे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस के रूप में जाना जाता है।
- ऑरोरा बोरेलिस को उत्तर ध्रुवीय ज्योति के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस को दक्षिण ध्रुवीय ज्योति के रूप में भी जाना जाता है।

RAO'S ACADEMY for Competitive Exams (A unit of RACE) YOUR SUCCESS OUR PRIORITY

प्रभाव:

- ऑरोरा संचार लाइनों, रेडियो लाइनों और बिजली लाइनों को प्रभावित करते हैं।

असम में हाइड्रोजन संयंत्र

खबरों में क्यों

OIL ने असम में भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया।

महत्वपूर्ण बिंदु

- अन्वेषण और उत्पादन प्रमुख ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL) ने असम में भारत का पहला 99.999% शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया है।

- हरित हाइड्रोजन, जिसमें जीवाश्म ईंधन को बदलने की क्षमता है, अक्षय ऊर्जा जैसे पवन या सौर ऊर्जा का उपयोग करके उत्पादित हाइड्रोजन गैस को दिया गया नाम है, जो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में शामिल नहीं है।
- मध्य असम के जोरहाट में स्थापित हरित हाइड्रोजन पायलट संयंत्र में प्रति दिन 10 किलो हाइड्रोजन का उत्पादन करने की स्थापित क्षमता है। प्लांट को तीन महीने के भीतर चालू कर दिया गया था।

उन्होंने कहा कि यह संयंत्र भारत का पहला आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन (एईएम) तकनीक का उपयोग करने वाला भी है। हरित हाइड्रोजन का उत्पादन 500-kW सौर संयंत्र द्वारा 100-kW AEM इलेक्ट्रोलाइजर सरणी का उपयोग करके उत्पन्न बिजली से किया जा रहा है।

1. ओआईएल ने मिश्रित ईंधन के वाणिज्यिक अनुप्रयोगों के लिए प्राकृतिक गैस के साथ हरे हाइड्रोजन के मिश्रण पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआई. टी)-गुवाहाटी के साथ एक विस्तृत अध्ययन शुरू किया है।
2. हाइड्रोजन गैस, जो जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं करती है, परिवहन, बिजली उत्पादन और औद्योगिक गतिविधियों में ईंधन के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है।
3. एक ईंधन सेल में जो किसी रसायन की ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करता है, हाइड्रोजन गैस बिजली और जलवाष्प उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती है, इस प्रकार यह जीवाश्म ईंधन के लिए एक संभावित स्वच्छ विकल्प बनाती है।

ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में

- हरित हाइड्रोजन अक्षय ऊर्जा या निम्न कार्बन ऊर्जा से उत्पन्न हाइड्रोजन है।
- हरे हाइड्रोजन में ग्रे हाइड्रोजन की तुलना में काफी कम कार्बन उत्सर्जन होता है, जो प्राकृतिक गैस के भाप सुधार से उत्पन्न होता है, जो हाइड्रोजन बाजार का बड़ा हिस्सा बनाता है।
- प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रोलिसिस नामक एक रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से हाइड्रोजन - एक सार्वभौमिक, हल्का और अत्यधिक प्रतिक्रियाशील ईंधन - के उत्पादन पर आधारित है।
- यह विधि पानी में ऑक्सीजन से हाइड्रोजन को अलग करने के लिए विद्युत प्रवाह का उपयोग करती है। यदि यह बिजली अक्षय स्रोतों से प्राप्त की जाती है, तो हम वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित किए बिना ऊर्जा का उत्पादन करेंगे।

लाभ

100% टिकाऊ: हरित हाइड्रोजन दहन के दौरान या उत्पादन के दौरान प्रदूषणकारी गैसों का उत्सर्जन नहीं करता है।

भंडारण योग्य: हाइड्रोजन को स्टोर करना आसान है, जो इसे बाद में अन्य उद्देश्यों के लिए और कभी-कभी इसके उत्पादन के तुरंत बाद उपयोग करने की अनुमति देता है।

बहुमुखी: हरे हाइड्रोजन को बिजली या सिंथेटिक गैस में बदला जा सकता है और घरेलू, वाणिज्यिक, औद्योगिक या गतिशीलता उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है।

परिवहन योग्य: इसे प्राकृतिक गैस के साथ 20% तक के अनुपात में मिलाया जा सकता है और समान गैस पाइप और बुनियादी ढांचे के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं - इस प्रतिशत को बढ़ाने के लिए मौजूदा गैस नेटवर्क में विभिन्न तत्वों को बदलने की आवश्यकता होगी ताकि उन्हें संगत बनाया जा सके।

RAC's ACADEMY for Competitive Exams (A Unit of RACE)

हानि

उच्च लागतः अक्षय स्रोतों से ऊर्जा, जो इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से हरित हाइड्रोजन उत्पन्न करने की कुंजी है, उत्पन्न करना अधिक महंगा है, जो बदले में हाइड्रोजन को प्राप्त करना अधिक महंगा बनाता है।

उच्च ऊर्जा खपतः सामान्य रूप से हाइड्रोजन और विशेष रूप से हरे हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए अन्य ईंधनों की तुलना में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है।

सुरक्षा संबंधी मुद्देः हाइड्रोजन एक अत्यधिक अस्थिर और ज्वलनशील तत्व है और इसलिए रिसाव और विस्फोटों को रोकने के लिए व्यापक सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होती है।

आक्रामक प्रजाति

खबरों में क्यों

आक्रामक प्रजातियों से पश्चिमी घाट के वन्यजीवों के आवासों को खतरा है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- वायनाड वन्यजीव अभयारण्य सहित नीलगिरि बायोस्फीयर रिजर्व (एनबीआर) के वन क्षेत्रों में आक्रामक पौधों, विशेष रूप से सेना स्पेक्टैबिलिस के बड़े पैमाने पर विकास को रोकने के लिए प्रभावी कदमों की कमी, पश्चिमी घाट के वन्यजीव आवासों के संरक्षण के लिए गंभीर चिंता का विषय है।
- आक्रामक विदेशी पौधों की प्रजातियां गैर-देशी प्रजातियां हैं जो एक नए पारिस्थितिकी तंत्र में फैलती हैं और स्थानीय जैव विविधता के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करके आर्थिक नुकसान का कारण बनती हैं।
- आक्रामक प्रजातियां स्थानीय प्रजातियों को बढ़ने और वन्यजीवों को आगे बढ़ने नहीं देती हैं। ऐसी विदेशी प्रजातियों से निकलने वाला राल जैसा पदार्थ मिट्टी को अम्लीय बना देता है, जिससे किसी भी अन्य पौधों की प्रजातियों के विकास को रोका जा सकता है।
- आक्रामक प्रजातियां अब पश्चिमी घाट के सबसे प्रतिष्ठित वन्यजीव आवासों में फैल गई हैं, देशी वनस्पतियों को बाहर निकालकर हाथियों, हिरणों, गौर और बाघों के आवासों को नष्ट कर रही हैं।
- प्रजातियों के ऐलेलोपैथिक लक्षण इसके तहत अन्य पौधों को बढ़ने से रोकते हैं। यह रासायनिक युद्ध का एक रूप है जहां शेड की पत्तियां सड़ जाती हैं और मिट्टी की रासायनिक संरचना को बदल देती हैं, जिससे यह अन्य पौधों की प्रजातियों के विकास के लिए अनुपयुक्त हो जाती है।
- यह जमीनी स्तर पर प्राथमिक उत्पादकता को अत्यधिक प्रभावित करता है। आक्रामक प्रजातियों के तहत वन तल लगभग शून्य है। घास और जड़ी-बूटियाँ पूरी तरह से नष्ट हो जाती हैं और शाकाहारी अपने चारे से वंचित हो जाते हैं।
- आक्रामक प्रजातियों ने 1980 के दशक में वायनाड में अपना रास्ता खोज लिया, जब पौधे के पौधे पहली बार सामाजिक वानिकी विंग की नर्सरी में उगाए गए, और एवेन्यू के पेड़ों के रूप में लगाए गए। वायनाड में इसकी शुरुआत के लगभग 25 वर्षों के बाद इसे पुनः उत्पन्न करते हुए देखा गया था।
- समय के साथ, यह कर्नाटक के बांदीपुर और नागरहोल टाइगर रिजर्व और तमिलनाडु में मुदुमलाई और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व में भी स्थापित हो गया।
- कर्नाटक और केरल के वन विभागों ने लगभग 10 साल पहले महसूस किया कि पेड़ देशी जैव विविधता के लिए खतरा है और इसके प्रसार को रोकने के लिए कार्रवाई शुरू की।
- अध्ययन में पाया गया कि वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य का लगभग 23% क्षेत्र सेना स्पेक्टाबिलिस से प्रभावित है। अध्ययन में कहा गया है कि अभयारण्य के सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में एक हेक्टेयर में 1,305 पेड़ पाए गए। निकटवर्ती टाइगर रिजर्व में प्रजातियां लगभग समान दर से फैल रही हैं।
- केरल वन विभाग ने पेड़ों को उखाड़ने, कमरबंद करने, काटने, पेड़ की शाखाओं को काटने और यहां तक कि रसायनों के प्रयोग का परीक्षण करके पेड़ों को हटाने का प्रयास किया। हालाँकि, सभी प्रयास व्यर्थ थे। इसके बजाय, प्रत्येक कटे हुए पेड़ के स्टंप से कई कॉपिस शूट बढ़ने लगे।

लंबी अवधि का औसत

खबरों में क्यों

IMD को लगातार चौथे साल सामान्य मॉनसून से बारिश की उम्मीद है।

RAO'S ACADEMY for Competitive Exams (A unit of RACE) YOUR SUCCESS OUR PRIORITY

महत्वपूर्ण बिंदु

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आई एम डी) ने इस साल के लिए जारी अपने पहले लंबी दूरी के पूर्वानुमान (एल आर एफ) में कहा कि देश में लगातार चौथे साल सामान्य मानसून रहने की संभावना है।

- 2019, 2020 और 2021 में भी चार महीने के जून-सितंबर दक्षिण-पश्चिम मानसून के मौसम में बारिश सामान्य श्रेणी में रही।
- IMD बेंचमार्क "दीर्घकालिक औसत" (एलपीए) के संबंध में "सामान्य", "सामान्य से नीचे", या "सामान्य से ऊपर" मानसून की भविष्यवाणी करता है।
- आईएमडी के अनुसार, "वर्षा का LPA एक विशेष क्षेत्र में एक निश्चित अंतराल (जैसे महीने या मौसम) के औसत के लिए 30 साल, 50 साल, आदि जैसी लंबी अवधि में दर्ज की गई वर्षा है।
- सामान्य मानसून की आईएमडी की भविष्यवाणी 1971-2020 की अवधि के एलपीए पर आधारित थी, जिसके दौरान भारत में पूरे देश में औसतन 87 सेमी. बारिश हुई थी।
- आईएमडी ने पूर्व में 1961-2010 की अवधि के लिए 88 सेमी. और 1951-2000 की अवधि के लिए 89 सेमी. पर एलपीए की गणना की है।
- जबकि यह मात्रात्मक बेंचमार्क पूरे देश के लिए जून से सितंबर तक दर्ज की गई औसत वर्षा को संदर्भित करता है, हर साल होने वाली बारिश की मात्रा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र और महीने दर महीने भिन्न होती है।
- आईएमडी देश के प्रत्येक मौसम क्षेत्र के लिए एलपीए भी रखता है - यह संख्या शुष्क उत्तर पश्चिमी भारत के लिए लगभग 61 सेमी से लेकर आर्द्र पूर्व और पूर्वोत्तर भारत के लिए 143 सेमी. से अधिक तक होती है।
- आईएमडी 2,400 से अधिक स्थानों और 3,500 रेन-गेज स्टेशनों पर वर्षा के आंकड़े दर्ज करता है।
- क्योंकि वार्षिक वर्षा न केवल एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में और महीने दर महीने, बल्कि एक विशेष क्षेत्र या महीने के भीतर भी साल-दर-साल बहुत भिन्न हो सकती है, प्रवृत्तियों को सुचारू करने के लिए एक एलपीए की आवश्यकता होती है ताकि एक उचित सटीक भविष्यवाणी की जा सके।
- असामान्य रूप से उच्च या निम्न वर्षा (अल-नीनो या ला-नीना जैसी घटनाओं के परिणामस्वरूप) के साथ-साथ आवधिक सूखे के वर्षों और तेजी से सामान्य होने के कारण किसी भी दिशा में बड़े बदलाव के लिए 50-वर्षीय एलपीए कवर करता है। जलवायु परिवर्तन के कारण चरम मौसम की घटनाएं।

आईएमडी अखिल भारतीय पैमाने पर पांच वर्षा वितरण श्रेणियां रखता है। ये:

- सामान्य या लगभग सामान्य, जब वास्तविक वर्षा का प्रतिशत प्रस्थान एलपीए का +/- 10% है, यानी एलपीए का 96-104% के बीच;
- सामान्य से नीचे, जब वास्तविक वर्षा का विचलन एलपीए के 10% से कम होता है, जो कि एलपीए का 90-96% होता है;
- सामान्य से अधिक, जब वास्तविक वर्षा एलपीए का 104-110% हो;
- कमी, जब वास्तविक वर्षा का प्रस्थान एलपीए के 90% से कम हो; और
- आधिक्य, जब वास्तविक वर्षा का विचलन एलपीए के 110 प्रतिशत से अधिक हो।

दक्षिण भारतीय तटरेखा

खबरों में क्यों

कोच्चि, तिरुवनंतपुरम की तटरेखा 2050 तक जलमग्न हो सकती है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- RMSI, नोएडा स्थित एक आईटी परामर्श फर्म, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (IPCC) के एक अध्ययन के अनुसार, प्रमुख तटीय शहरों के लिए रिपोर्ट, 2050 तक समुद्र के बढ़ते स्तर के कारण, जनसंख्या, संपत्ति और बुनियादी ढांचे की एक महत्वपूर्ण संख्या के कारण कोच्चि और तिरुवनंतपुरम में चार अन्य शहरों - मुंबई, चेन्नई, विजाग, मंगलुरु - जलमग्न होंगे।
- IPCC आकलन रिपोर्ट बताती है कि 2050 तक भारत का समुद्र स्तर काफी बढ़ जाएगा।
- उत्तर हिंद महासागर (एनआईओ) में समुद्र के स्तर में वृद्धि 1874 से 2004 तक 1.06-1.75 मिमी. प्रति वर्ष की दर से हुई और पिछले ढाई दशकों(1993-2017) में यह 3.3 मिमी प्रति वर्ष हो गई है।

RAO'S ACADEMY for Competitive Exams (A unit of RAO'S) YOUR SUCCESS OUR PRIORITY

- RMSI ने अपनी तटीय बाढ़ मॉडलिंग क्षमताओं का इस्तेमाल विभिन्न समुद्र-स्तर वृद्धि पूर्वानुमान अध्ययनों के आधार पर शहरों के बाढ़ (जलमग्न) स्तरों को मैप करने के लिए किया।
- बाढ़ के आधार पर, इसने उन इमारतों की संख्या और प्रमुख बुनियादी ढांचे की पहचान करने के लिए एक विश्लेषण किया जो इनमें से प्रत्येक शहर में संभावित रूप से जलमग्न हो सकते हैं।

केरल

तिरुवनंतपुरम में, संभावित नई तटरेखा और उच्च ज्वार के साथ समुद्र तट के कारण, क्रमशः 349 और 387 इमारतों के प्रभावित होने की संभावना है। इन इमारतों में लगभग 60% आवासीय और 40% वाणिज्यिक भवन शामिल हैं। इसी तरह, लगभग तीन किमी सड़क की लंबाई प्रभावित होने की पहचान की गई है।

IPCC के बारे में

जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (आईपीसीसी) जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान का आकलन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र निकाय है।

आईपीसीसी जलवायु परिवर्तन पर वैज्ञानिक, तकनीकी और सामाजिक-आर्थिक ज्ञान की स्थिति, इसके प्रभावों और भविष्य के जोखिमों और जलवायु परिवर्तन की दर को कम करने के विकल्पों के बारे में व्यापक मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करता है।

यह अपनी सदस्य सरकारों द्वारा सहमत विषयों पर विशेष रिपोर्ट भी तैयार करता है, साथ ही कार्यप्रणाली रिपोर्ट जो ग्रीनहाउस गैस सूची तैयार करने के लिए दिशानिर्देश प्रदान करती है।

आईपीसीसी छठी मूल्यांकन रिपोर्ट पर काम कर रहा है जिसमें तीन कार्य समूह योगदान और एक संश्लेषण रिपोर्ट शामिल है।

वर्किंग ग्रुप-I के योगदान को अगस्त 2021 में और वर्किंग ग्रुप-II के योगदान को फरवरी 2022 में अंतिम रूप दिया गया था।

सुंदरबन पर रिपोर्ट

खबरों में क्यों

सीएजी रिपोर्ट रामसर साइटों, ईकेडब्ल्यू, सुंदरबन में घोर पर्यावरण उल्लंघन पर प्रकाश डालती है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (CAG) की एक हालिया ऑडिट रिपोर्ट ने पश्चिम बंगाल, पूर्वी कोलकाता वेटलैंड्स (EKW) और सुंदरबन में दो रामसर स्थलों में अवैध निर्माण और पर्यावरण मानदंडों के उल्लंघन की ओर इंगित किया है।
- सुंदरबन में ईकेडब्ल्यू और तटीय विनियमन क्षेत्र क्षेत्र में अवैध निर्माण थे।
- हालांकि, इन पारिस्थितिक रूप से नाजुक क्षेत्रों में भी इस तरह के उल्लंघनों को शायद ही कभी दंडित किया गया हो; कुछ दुर्लभ अवसरों पर, (जब) वे किए गए, यह कोलकाता उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में था।
- EKW, एक अद्वितीय पेरी-अर्बन इकोसिस्टम जो कोलकाता के पूर्वी किनारे पर स्थित है, राज्य के दक्षिण और उत्तर 24 परगना जिले के 37 मौजों में फैले लगभग 12,500 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करता है।

कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि

- ईकेडब्ल्यू की सीमाओं को चित्रित करने में विफलता और भूमि के अनियंत्रित हस्तांतरण के परिणामस्वरूप ईकेडब्ल्यू के चरित्र में परिवर्तन हुआ और ईकेड. ब्ल्यूएमए (पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि प्रबंधन प्राधिकरण) द्वारा प्रभावी कार्रवाई की कमी हुई।
- EKWMA द्वारा प्रभावी उपायों के अभाव में, जलाशय सूख गए और अवैध रूप से भर दिए गए। 2007 से, EKWMA ने उल्लंघन के 357 मामलों की पहचान की है, जिनमें से 101 मामलों की पहचान दिसंबर 2015 और मार्च 2020 के बीच की गई थी।
- इसमें आगे कहा गया है कि 101 उल्लंघनकर्ताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने पर।
- 51 मामले ईकेडब्ल्यू क्षेत्र में अनधिकृत दो/तीन मंजिला भवनों, संगमरमर के गोदामों, मोटरबाइक और कार शोरूम के निर्माण, जलाशयों के सूखने और भरने के 23 मामले और चारदीवारी के निर्माण के 27 मामले थे; ये आर्द्रभूमि के पारिस्थितिक चरित्र को बदल देते हैं और इसलिए ईकेडब्ल्यू अधिनियम का उल्लंघन करते हैं।
- रिपोर्ट में एक धार्मिक प्राधिकरण द्वारा उल्लंघन और प्लास्टिक उद्योगों द्वारा आर्द्रभूमि के अतिक्रमण पर

RAO'S ACADEMY for Competitive Exams (A unit of RACE) YOUR SUCCESS OUR PRIORITY

भी चर्चा की गई है। रिपोर्ट बताती है कि भूमि उपयोग पैटर्न में परिवर्तन भगवानपुर मौजा में देखा गया था, जहां "पूर्ण जल निकायों और तटबंधों के तहत क्षेत्र 2002 में 522.94 हेक्टेयर से घटकर 2016 में 116.07 हेक्टेयर अतिक्रमण के कारण हो गया।

- अध्ययन में आगे पता चला कि मौजा में, 1998 में क्रियाशील 47 भेरी (मछली तालाब) में से 2017 में केवल 10 भेरी बची थीं।
- इस प्रकार EKWMA भागबनपुर मौजा में आर्द्रभूमि को संरक्षित करने में विफल रहा।
- सीएजी ने बताया है कि राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण ने मार्च 2020 तक आर्द्रभूमि मित्र (नागरिक नेटवर्क) का गठन नहीं किया था।

जैव विविधता को नष्ट करने वाली पारिस्थितिकी परियोजनाएं

- सीएजी रिपोर्ट ने सुंदरबन में विशेष रूप से झारखाली में एक पारिस्थितिक पर्यटन परियोजना के लिए सीआरजेड मानदंडों के गंभीर उल्लंघन को उजागर किया है।
- "भारत सरकार ने 69 एकड़ मैंग्रोव को साफ करने के बाद सुंदरबन के झारखली में एक पर्यावरण-पर्यटन केंद्र की एक परियोजना शुरू की थी (अक्टूबर 2015)। यहां तक कि नदी चौनल, मगरमच्छों के प्रजनन स्थल पर भी परियोजना का दावा किया गया था।"

काजीरंगा पशु गलियारों पर सुप्रीम कोर्ट का पैनल

खबरों में क्यों

काजीरंगा पशु गलियारों पर हमले पर सुप्रीम कोर्ट के पैनल ने असम की आलोचना की।

महत्वपूर्ण बिंदु

- सुप्रीम कोर्ट के एक पैनल ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व के पशु गलियारों पर अवैध निर्माण गतिविधियों की जाँच में ढिलाई के लिए असम सरकार को उकसाया है।
- 1,300 वर्ग किमी वन्यजीव आवास, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल और दुनिया के एक सींग वाले गैंडों का सबसे प्रसिद्ध पता, नौ अधिसूचित पशु गलियारे हैं।
- इनमें से सात अमगुरी, बागोरी, चिरांग, देवसुर, हरमती, हातिदंडी और कंचनजुरी नागांव जिले में हैं जबकि हल्दीबाड़ी और पनबारी निकटवर्ती गोलाघाट जिले में हैं।
- सुप्रीम कोर्ट की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) ने एक बैठक में मुख्य सचिव और असम सरकार के अन्य प्रतिनिधियों को जल्द से जल्द पशु गलियारों पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण पर कार्रवाई रिपोर्ट प्रदान करने का निर्देश दिया था।
- अवैध गतिविधियां 12 अप्रैल, 2019 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हैं, जिसमें निजी भूमि पर नए निर्माण पर रोक लगा दी गई है, जो काजीरंगा के जानवरों के बाढ़-प्रवण पार्क के अंदर और बाहर जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले गलियारों के भीतर हैं।
- बैठक के कार्यवृत्त में कहा गया है कि असम सरकार को सीईसी को आश्वस्त करने के लिए बनाया गया था कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए, पशु गलियारों पर उनके परिसीमन से पहले और बाद में किए गए निर्माण की तस्वीरें भी उपलब्ध कराएगी।
- राज्य सरकार ने सीईसी को उन अधिकारियों के नाम और पदनाम प्रदान करने का भी आश्वासन दिया, जिन्होंने अदालत के आदेश का उल्लंघन करते हुए निर्माण गतिविधियों के लिए अनुमति दी थी, साथ ही संबंधित दस्तावेजों और अवैध संरचनाओं को हटाने या गिराने के लिए जारी नोटिस की प्रतियों के साथ।
- अन्य रिपोर्टों में राज्य सरकार को काजीरंगा के वन्य जीव पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र के अतिक्रमण के खिलाफ की गई कार्रवाई के साथ-साथ निर्माण गतिविधियों की सूची प्रदान करने के लिए कहा गया है, जिन्हें राष्ट्रीय बोर्ड की एक उप-समिति की मंजूरी नहीं मिली थी।
- सीईसी 2020 से असम सरकार को पशु गलियारों पर अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पत्र लिख रहा है। उत्तरार्द्ध धीमा हो गया है क्योंकि कुछ विधायक कथित तौर पर ऐसी गतिविधियों में शामिल हैं।

YOUR SUCCESS OUR PRIORITY
RAC'S ACADEMY for Competitive Exams (A unit of RACE)

वायु गुणवत्ता डेटाबेस

खबरों में क्यों

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने वायु गुणवत्ता डेटाबेस 2022 जारी किया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने पिछले सप्ताह एक रिपोर्ट में खुलासा किया कि वैश्विक आबादी का लगभग 99% हिस्सा ऐसी हवा में सांस ले रहा है जिसमें स्वीकृत वायु गुणवत्ता सीमा से परे प्रदूषक हैं।
- डब्ल्यूएचओ ने अपने वायु गुणवत्ता डेटाबेस में 2022 के अपडेट के बाद अवलोकन किया।

वैश्विक स्वास्थ्य निकाय ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 117 देशों में फैले 6,000 से अधिक शहर वायु गुणवत्ता की निगरानी कर रहे हैं और निम्न और मध्यम आय वाले देशों में रहने वाले लोग सूक्ष्म कणों और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अस्वास्थ्यकर स्तरों से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। इसने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए जीवाश्म ईंधन और अन्य कदमों के उपयोग को कम करने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला।

वायु गुणवत्ता डेटाबेस

- वायु गुणवत्ता डेटाबेस हवा की गुणवत्ता और हवा में कणों की सांद्रता पर डेटा का संकलन है।
- इसे 2011 में शुरू किया गया था और तब से इसे समय-समय पर अपडेट किया जाता रहा है।
- डेटाबेस का इरादा डब्ल्यूएचओ के अनुसार जनसंख्या जोखिम के मजबूत अनुमान प्रदान करके वायु प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारियों के अध्ययन में मदद करना है।

वर्तमान अद्यतन

- इस वर्ष डेटाबेस के पांचवें अपडेट के बाद, पहली बार, डेटाबेस में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वार्षिक औसत सांद्रता का जमीनी माप शामिल है, जिसे डब्ल्यूएचओ "एक सामान्य शहरी प्रदूषक और कण पदार्थ और ओजोन का अग्रदूत" कहता है।
- हालांकि, यह डेटा 2011, 2014, 2016 और 2018 में डेटाबेस के पिछले संस्करणों में दर्ज नहीं किया गया था।
- साथ ही, 2018 में अंतिम अपडेट के बाद से करीब 2,000 और शहर/मानव बस्तियां पीएम 2.5 और पीएम 10 के लिए डेटा रिकॉर्ड कर रही थीं।
- डेटाबेस का पांचवां और वर्तमान अपडेट इसे जमीनी स्तर पर वायु प्रदूषण के जोखिम के कवरेज में अभी तक सबसे व्यापक बनाता है।
- इस प्रकार, 2022 संस्करण में 117 देशों में 6,743 मानव बस्तियों से 2010 और 2019 के बीच के वर्षों के लिए पीएम 2.5, पीएम 10 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के वार्षिक साधनों के बारे में डेटा होगा।
- डेटाबेस में औसत आमतौर पर पूरे शहर/कस्बे के लिए होता है, न कि व्यक्तिगत निगरानी स्टेशनों पर।

RAO'S ACADEMY for Competitive Exams (A unit of RACE)

4 अर्थव्यवस्था

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)

खबरों में क्यों

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2022-23 सत्र के लिए कच्चे जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को मंजूरी दे दी है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- 2022-23 सीजन के लिए कच्चे जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2022-23 के लिए 4,750 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 250 रुपये की वृद्धि हुई है।
- 2022-23 सीजन के लिए कच्चे जूट का घोषित एमएसपी बजट 2018-19 में सरकार द्वारा घोषित उत्पादन की अखिल भारतीय भारित औसत लागत के कम से कम 1.5 गुना के स्तर पर एमएसपी तय करने के सिद्धांत के अनुरूप है।
- जूट को खपत, उत्पादन, उपयोग और उपलब्धता के मामले में कपास के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फाइबर माना जाता है। जूट उद्योग 3,70,000 से अधिक श्रमिकों और 40 लाख से अधिक किसानों को रोजगार देने के लिए जिम्मेदार है।
- भारतीय पटसन निगम (जेसीआई) मूल्य समर्थन संचालन करने के लिए केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी के रूप में जारी रहेगा। ऑपरेशन में किसी भी नुकसान के मामले में, केंद्र सरकार द्वारा उनकी पूरी तरह से प्रतिपूर्ति की जाएगी।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)

- एक फसल के लिए एमएसपी वह मूल्य है जिस पर सरकार को उस फसल को किसानों से खरीदना/खरीदना होता है यदि बाजार मूल्य इससे नीचे आता है।
- एमएसपी बाजार कीमतों के लिए एक मंजिल प्रदान करते हैं, और यह सुनिश्चित करते हैं कि किसानों को एक निश्चित "न्यूनतम" पारिश्रमिक प्राप्त हो ताकि उनकी खेती की लागत (और कुछ लाभ) की वसूली की जा सके।
- एमएसपी की घोषणा केंद्र सरकार करती है और इसलिए यह सरकार का निर्णय है।
- लेकिन सरकार बड़े पैमाने पर कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों पर अपने निर्णय को आधार बनाती है।

एमएसपी द्वारा कवर की जाने वाली फसलों में शामिल हैं:

- 7 प्रकार के अनाज (धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी और जौ),
- 5 प्रकार की दालें (चना, अरहर/तूर, उड़द, मूंग और मसूर),
- 7 तिलहन (रेपसीड-सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, कुसुम, नाइजरसीड),
- 4 व्यावसायिक फसलें (कपास, गन्ना, खोपरा, कच्चा जूट)

एमएसपी की सिफारिश करते समय, सीएसीपी निम्नलिखित कारकों को देखता है:

- किसी वस्तु की मांग और आपूर्ति;
- इसकी उत्पादन लागत;
- बाजार मूल्य रुझान (घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों);
- अंतर-फसल मूल्य समता;
- कृषि और गैर-कृषि के बीच व्यापार की शर्तें (अर्थात, कृषि आदानों और कृषि उत्पादों की कीमतों का अनुपात);
- उत्पादन की लागत पर मार्जिन के रूप में न्यूनतम 50 प्रतिशत; और
- उस उत्पाद के उपभोक्ताओं पर एमएसपी के संभावित प्रभाव।

RAO'S ACADEMY for Competitive Exams (A unit of RACE)

घरेलू पेटेंट फाइलिंग

खबरों में क्यों

घरेलू पेटेंट फाइलिंग 11 वर्षों में पहली बार अंतरराष्ट्रीय पेटेंट से आगे निकल गई।

महत्वपूर्ण बिंदु

- भारत ने बौद्धिक संपदा (आईपी) नवाचार पारिस्थि. तिकी तंत्र के संदर्भ में एक और मील का पत्थर हासिल किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, आईपी नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
- घरेलू पेटेंट फाइलिंग ने 11 वर्षों में पहली बार जनवरी-मार्च तिमाही के दौरान भारतीय पेटेंट कार्यालय में अंतरराष्ट्रीय पेटेंट फाइलिंग को पीछे छोड़ दिया।
- दाखिल किए गए कुल 19,796 पेटेंट आवेदनों में से 10,706 भारतीय आवेदकों द्वारा दाखिल किए गए, जबकि गैर-भारतीय आवेदकों द्वारा 9,090 दाखिल किए गए।
- डीपीआईआईटी और आईपी कार्यालय के समन्वित प्रयास से समाज के सभी वर्गों में आईपी जागरूकता में वृद्धि हुई है। इस प्रयास से एक ओर आईपीआर फाइलिंग की संख्या में वृद्धि हुई है और दूसरी ओर आईपी कार्यालयों में पेटेंट आवेदन की पेंडेंसी कम हुई है।
- पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा की गई कुछ प्रमुख पहलों ने भारत के आईपी शासन को मजबूत किया है, जिसमें अन्य श्रेणियों के साथ-साथ स्टार्टअप्स और एमएसएमई के लिए त्वरित परीक्षा के प्रावधान शामिल हैं।
- वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि पेटेंट दाखिल करना 2014-15 में 42,763 से बढ़कर 2021-22 में 66,440 हो गया है। यह सात साल में 50 फीसदी की बढ़ोतरी है।
- इसने 2014-15 (5978) की तुलना में 2021-22 (30,074) में पेटेंट के अनुदान में पांच गुना वृद्धि देखी।
- सरकार ने आगे बताया कि पेटेंट परीक्षा के समय को दिसंबर 2016 में 72 महीने से घटाकर वर्तमान में 5-23 महीने कर दिया गया है, जबकि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 2015-16 में 81वें से बढ़कर 2021 में 46वें (+35 रैंक) हो गई है।
- मंत्रालय ने पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा की गई कुछ प्रमुख पहलों पर प्रकाश डाला जिसमें शुल्क रियायतें शामिल हैं जैसे ऑनलाइन फाइलिंग पर 10 प्रतिशत की छूट, स्टार्टअप्स, छोटी संस्थाओं और शैक्षणिक संस्थानों के लिए 80 प्रतिशत शुल्क रियायत, और स्टार्टअप्स और एमएसएमई के लिए शीघ्र परीक्षा के प्रावधान किया गया।

क्च्प्ज् के बारे में

औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (DIPP) का नाम बदलकर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) कर दिया गया। डीपीआईआईटी में शामिल होंगे:

- आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देना (खुदरा व्यापार सहित),
- व्यापारियों और उनके कर्मचारियों का कल्याण,
- व्यवसाय करने में आसानी को सुगम बनाने से संबंधित मामले,
- स्टार्ट-अप से संबंधित मामले।

नागालैंड में शहरी विकास

खबरों में क्यों

नागालैंड में शहरी विकास का समर्थन करने के लिए ADB वित्त पोषण करेगा।

महत्वपूर्ण बिंदु

- भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने नागालैंड में 16 जिला मुख्यालय कस्बों (डीएचटी) में जलवायु अनुकूल शहरी बुनियादी ढांचे को डिजाइन करने, संस्थागत क्षमता को मजबूत करने और नगरपालिका संसाधन जुटाने में सुधार के लिए + 2 मिलियन प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग (पीआरएफ) ऋण पर हस्ताक्षर किए।
- एडीबी वित्त पोषण शहरी क्षेत्र की रणनीति तैयार करने, व्यवहार्यता अध्ययन और चयनित उप परियोजनाओं के विस्तृत इंजीनियरिंग डिजाइन और परियोजना कार्यान्वयन, संसाधन जुटाने और एंकरिंग सुधारों में राज्य स्तर की एजेंसियों की क्षमता निर्माण के माध्यम से आगामी परियोजना की उच्च तैयारी सुनिश्चित करेगा।

RAO'S ACADEMY for Competitive Exams (A Unit of RACE)

- नागालैंड के कस्बे और शहर जलवायु परिवर्तन, बुनियादी सुविधाओं की कमी, खराब कनेक्टिविटी जैसी दीर्घकालिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।
- शहरी क्षेत्रों के आसपास के प्रमुख परिवहन मार्ग मानसून के मौसम में भूस्खलन से बुरी तरह प्रभावित होते हैं। बरसाती पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था न होने से शहरी सड़कों की हालत खराब है।
- दीमापुर को छोड़कर अधिकांश शहरों में पानी की भारी कमी है और अपर्याप्त सीवरेज या सेप्टेज प्रबंधन प्रणाली है। ये सभी मुद्दे राज्य के आर्थिक विकास को बाधित करते हैं।
- पीआरएफ ऋण 16 डीटीएच में जल आपूर्ति, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और शहरी सड़कों को डिजाइन करने में मदद करेगा, जिसमें जलवायु अनुकूल विशेषताएं और गरीब और कमजोर लोगों तक बेहतर पहुंच होगी।
- राज्य एजेंसियों के क्षमता निर्माण से शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) द्वारा स्वयं के संसाधन जुटाने में मदद मिलेगी, आगामी परियोजना को लागू करने और क्षेत्र और संस्थागत सुधार शुरू करने के लिए उनकी तैयारी में सुधार होगा।

GIFT & IFSC में Longevity Hub

खबरों में क्यों

दीर्घायु वित्त पर विशेषज्ञ समिति ने GIFT-IFSC में दीर्घायु केंद्र स्थापित करने की सिफारिश की।

महत्वपूर्ण बिंदु

- अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) ने दीर्घायु वित्त पर विशेषज्ञ समिति का गठन किया।
- समिति ने विश्व स्तर पर दीर्घायु अर्थव्यवस्था में उभरते रुझानों की जांच की और पाया कि 60 साल से अधिक उम्र के लोग अभी भी क्रय शक्ति के मामले में एक अत्यधिक उत्पादक जनसांख्यिकीय समूह हैं और +15 ट्रिलियन की वैश्विक व्यय शक्ति के साथ वित्तीय प्रणाली का सबसे धनी हिस्सा हैं।
- दीर्घायु उद्योग के विकास के लिए वित्तीय सेवा क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए, समिति ने GIFT-IFSC में पहले वैश्विक दीर्घायु हब (GLH) की स्थापना की सिफारिश की।
- समिति ने यह भी सुझाव दिया कि हब को प्रमुख कॉरपोरेट्स और वित्तीय संस्थानों जैसे बैंक, पेंशन फंड, एसेट मैनेजमेंट फंड, बीमा कंपनियों, आदि के साथ समन्वय में विभिन्न दीर्घायु वित्त समाधान प्रदान करके दीर्घायु अर्थव्यवस्था के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
- आईएफएससी में एक मजबूत दीर्घायु वित्त केंद्र बनाने की दीर्घकालिक दृष्टि धन प्रबंधन, बीमा, पेंशन, चांदी उद्यमिता और औसत दर्जे के पर्यटन में अवसर खोल सकती है।
- यह GIFT-IFSC को दीर्घायु वित्त में एक वैश्विक नेता के रूप में उभरने में मदद करेगा, बेबी बूमर्स, जनरल एक्स और जनरल वाई को हॉर्ट्स की आवश्यकताओं को तुरंत पूरा करेगा और मिलेनियल्स के लिए रास्ता तय करेगा।
- समिति के सदस्यों में बैंकिंग, बीमा, धन प्रबंधन, फिनटेक, कानूनी, अनुपालन और प्रबंधन परामर्श जैसे क्षेत्रों सहित संपूर्ण दीर्घायु वित्त पारिस्थितिकी तंत्र के नेता शामिल थे।

गिफ्ट-आईएफएससी

- गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट) एसईजेड विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 ("एसईजेड अधिनियम 2005") के तहत भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) है।
- इसे वैश्विक वित्तीय सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। GIFT IFSC 105 हेक्टेयर भूमि के साथ एक बहु सेवा विशेष आर्थिक क्षेत्र है और अप्रैल 2015 में अपना कारोबार शुरू किया।
- भारत सरकार ने अप्रैल 2015 में GIFT मल्टी सर्विसेज SEZ में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) का संचालन किया।
- केंद्रीय बजट 2016 ने GIFT SEZ में IFSC के लिए प्रतिस्पर्धी कर व्यवस्था प्रदान की।

गिफ्ट एसईजेड एडवांटेज

- अनुमानित 5,00,000 प्रत्यक्ष रोजगार और इतनी ही संख्या में अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन।
- वित्तीय प्रोत्साहन, नियामक स्वतंत्रता और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा प्रदान करना।

RAO'S ACADEMY for Competitive Exams (A Unit of RACE)

- विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा और अद्वितीय कनेक्टिविटी और परिवहन पहुंच।
- स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अंतर्निहित प्रौद्योगिकियों के साथ पर्यावरण मानदंडों का कड़ाई से पालन।
- आईटी और आईटीईएस कंपनियों, वित्त कंपनियों, कमोडिटी एक्सचेंज, वैश्विक व्यापार, बीमा, अपतटीय बैंकिंग और डेटा केंद्रों का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय केंद्र।

खनिज उत्पादन

खबरों में क्यों

खनिज उत्पादन रिकॉर्ड 13.2 प्रतिशत संचयी वृद्धि हुयी है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- भारतीय खान ब्यूरो के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-फरवरी, 2021-22 की अवधि के लिए संचयी वृद्धि पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 13.2 प्रतिशत बढ़ी है।
- खनन एवं उत्खनन क्षेत्र के खनिज उत्पादन का सूचकांक इस वर्ष फरवरी माह में पिछले वर्ष फरवरी की तुलना में 4.5 प्रतिशत अधिक रहा।
- इस वर्ष फरवरी में महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन स्तर था - कोयला 795 लाख टन, लिग्नाइट 47 लाख टन, पेट्रोलियम (कच्चा) 23 लाख टन, क्रोमाइट 373 हजार टन और सोना 125 किलोग्राम।

संचयी वृद्धि

- संचयी वृद्धि एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग एक निर्धारित अवधि में वृद्धि के प्रतिशत का वर्णन करने के लिए किया जाता है।
- संचयी वृद्धि का उपयोग अतीत में वृद्धि को मापने के लिए किया जा सकता है और इस प्रकार, जनसंख्या वृद्धि की योजना बनाने, जैविक कोशिका वृद्धि का अनुमान लगाने, बिक्री वृद्धि को मापने आदि के लिए उपयोग किया जा सकता है।
- यह पता लगाने में एक उपयोगी वर्णनात्मक उपकरण है कि समय के साथ विकास कैसे विकसित हुआ है या विकास कैसे विकसित होता रहेगा।
- सीएजीआर को तीन इनपुट की आवश्यकता होती है: एक निवेश का प्रारंभिक मूल्य, उसका अंतिम मूल्य और समय अवधि (वर्षों में व्यक्त)।

डिजिटल बैंकिंग इकाइयां (DBU)

खबरों में क्यों

वित्त मंत्री ने 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की स्थापना पर अपनी बजट घोषणा को दोहराया।

महत्वपूर्ण बिंदु

- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां स्थापित करने की अपनी बजट घोषणा को दोहराया। यह डिजिटल वित्तीय समावेशन के सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए है।
- 2022-23 के बजट में वित्त मंत्री ने कहा कि देश में डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और फिनटेक इनोवेशन तेजी से बढ़े हैं।
- सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए इन क्षेत्रों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है कि डिजिटल बैंकिंग का लाभ देश के कोने-कोने तक उपभोक्ता-हितैषी तरीके से पहुंचे।
- इस एजेंडा को आगे बढ़ाते हुए, और हमारी आजादी के 75 साल पूरे होने पर, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां (डीबीयू) स्थापित करने का प्रस्ताव है।
- हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंक संघ के एक कार्यकारी समूह की रिपोर्ट के बाद डीबीयू के लिए दिशा-निर्देशों की घोषणा की।

डीबीयू क्या हैं?

- एक डिजिटल बैंकिंग इकाई एक विशिष्ट निश्चित बिंदु व्यवसाय इकाई या हब है जो डिजिटल बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं को वितरित करने के साथ-साथ मौजूदा वित्तीय उत्पादों और सेवाओं को किसी भी समय स्वयं-सेवा मोड में डिजिटल रूप से सेवा देने के लिए कुछ न्यूनतम डिजिटल बुनियादी ढांचे का केंद्र है।

इन डीबीयू की स्थापना कौन करेगा?

- पिछले डिजिटल बैंकिंग अनुभव वाले वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, भुगतान बैंकों और स्थानीय क्षेत्र के बैंकों के अलावा) को हर मामले मेंआरबीआई से अनुमति लेने की आवश्यकता के

RAO'S ACADEMY for Competitive Exams (A unit of RACE) YOUR SUCCESS IS OUR PRIORITY

बिना, टियर 1 से टियर 6 केंद्रों में डीबीयू खोलने की अनुमति है, जब तक कि अन्यथा विशेष रूप से प्रतिबंधित न हो।

डीबीयू द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं

- आरबीआई के अनुसार, प्रत्येक डीबीयू को कुछ न्यूनतम डिजिटल बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करनी चाहिए।
- ऐसे उत्पाद डिजिटल बैंकिंग सेगमेंट की बैलेंस शीट की देनदारियों और संपत्ति दोनों पक्षों पर होने चाहिए। पारंपरिक उत्पादों के लिए डिजिटल रूप से मूल्य वर्धित सेवाएं भी इस तरह योग्य होंगी।
- सेवाओं में विभिन्न योजनाओं के तहत बचत बैंक खाते, चालू खाते, सावधि जमा और आवर्ती जमा खाते, ग्राहकों के लिए डिजिटल किट, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और मास ट्रांजिट सिस्टम कार्ड, व्यापारियों के लिए डिजिटल किट, यूपीआई शामिल हैं। क्यूआर कोड, भीम आधार और पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस)।
- अन्य सेवाओं में पहचाने गए खुदरा, एमएसएमई या योजनाबद्ध ऋणों के लिए ग्राहकों के लिए आवेदन करना और उन्हें शामिल करना शामिल है। इसमें ऐसे ऋणों का संपूर्ण डिजिटल प्रसंस्करण, ऑनलाइन आवेदन से लेकर वितरण तक और राष्ट्रीय पोर्टल के तहत कवर की गई सरकारी प्रायोजित योजनाओं की पहचान करना शामिल हो सकता है।
- वर्तमान में, नियोबैंक के रूप में काम करने वाली फिनटेक डिजिटल बैंकिंग सेवाएं प्रदान करती हैं, लेकिन वे गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के साथ साझेदारी में ऐसा करती हैं। भारत में सेवाओं की पेशकश करने वाले कुछ नियोबैंक हैं जुपिटर, फाई मनी, नियो, रेजरपे एक्स।

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक

खबरों में क्यों

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के लिए वित्तीय सहायता को मंजूरी दे दी है

महत्वपूर्ण बिंदु

खहाल ही मेंइंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) ने परिचालन शुरू करने के केवल तीन में अपने 5 करोड़ ग्राहकों का आंकड़ा पार किया है और देश में सबसे तेजी से बढ़ते डिजिटल भुगतान बैंक में से एक बन गया है।

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के लिए 820 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है।
- आईपीपीबी ने अपने 1.36 लाख डाकघरों के माध्यम से इन पांच करोड़ खातों को डिजिटल और पेपरलेस मोड में खोला, जिनमें से 1.20 लाख लगभग 1.47 लाख डोरस्टेप बैंकिंग सेवा प्रदाताओं की मदद से ग्रामीण क्षेत्रों में हैं।
- कुल खाताधारकों में से, लगभग 48% महिला खाता धारक थीं, जबकि 52% पुरुष थे, जो महिला ग्राहकों को बैंकिंग नेटवर्क के अंतर्गत लाने पर बैंक के ध्यान को दर्शाता है।
- लगभग 98% महिलाओं के खाते दरवाजे पर खोले गए और 68% से अधिक महिलाएं डीबीटी का लाभ उठा रही थीं।
- आईपीपीबी ने खुलासा किया कि इसने युवाओं को डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आकर्षित किया। 41% से अधिक खाताधारक 18 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के थे।
- आईपीपीबी डाक विभाग की अपनी पैतृक शक्ति का लाभ उठाने में सक्षम रहा है और देश भर में वित्तीय समावेशन परिदृश्य को लगातार बदल रहा है और नया आकार दे रहा है।
- निकट भविष्य में, आईपीपीबी का प्रयास जेएएम, सहमती आदि जैसे भारतीय स्टैक का लाभ उठाकर दरवाजे पर क्रेडिट सहित विभिन्न नागरिक-केंद्रित वित्तीय सेवाओं की पेशकश करने वाले एक एकीकृत सेवा मंच का निर्माण करना है।

आईपीपीबी के बारे में

- इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, डाक विभाग और संचार मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, जहां भारत सरकार की 100 प्रतिशत इक्विटी है। भुगतान बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शासित होगा।
- आईपीपीबी बचत और चालू खातों, धन हस्तांतरण, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, बिल और उपयोगिता भुगतान, और उद्यम और व्यापारी भुगतान जैसे उत्पादों की एक श्रृंखला की पेशकश करेगा।

RAO'S ACADEMY for Competitive Exams (A unit of RACE)

- इन उत्पादों और संबंधित सेवाओं को बैंक के अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए कई चौनलों (काउंटर सेवाओं, माइक्रो-एटीएम, मोबाइल बैंकिंग ऐप, एसएमएस और आईवीआर) में पेश किया जाएगा।
- आईपीपीबी किसी भी एटीएम डेबिट कार्ड की पेशकश नहीं करेगा। इसके बजाय, यह अपने ग्राहकों को एक क्यूआर कोड-आधारित बायोमेट्रिक कार्ड प्रदान करेगा। इसने बीमा उत्पादों को बेचने के लिए पीएनबी मेटलाइफ और बजाज आलियांज के साथ पहले ही करार कर लिया है और उम्मीद है कि वह और अधिक वित्तीय सेवा साझेदारी में प्रवेश करेगा।

भारत-यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (सीईपीए)

खबरों में क्यों

भारत, संयुक्त अरब अमीरात के बीच सबसे बड़ा द्विपक्षीय व्यापार समझौता लागू।

महत्वपूर्ण बिंदु

- भारत-यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (सीईपीए), दो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच सबसे

  बड़ा द्विपक्षीय व्यापार समझौता, सक्रिय हो गया।
- भारत ब्रिटेन, कनाडा और यूरोपीय संघ सहित पूरक अर्थव्यवस्थाओं के साथ बहुत तेज गति से व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है।
- दोनों पक्षों के बीच 18 फरवरी को समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
- महत्वपूर्ण अवसर पर सचिव, वाणिज्य विभाग, बी.वी. आर. सुब्रह्मण्यम ने भारत-यूएई सीईपीए के तहत भारत से संयुक्त अरब अमीरात के लिए आभूषण वस्तुओं से युक्त सामानों की पहली खेप को हरी झंडी दिखाई।
- श्री सुब्रह्मण्यम ने रत्न और आभूषण क्षेत्र के तीन निर्यातकों को "उत्पत्ति का प्रमाण पत्र" सौंपा।
- नई सीमा शुल्क प्रणाली के तहत, खेप पर "शून्य सीमा शुल्क" लगेगा।
- उपरोक्त खेप जो अब इस समझौते के तहत शून्य सीमा शुल्क को आकर्षित करेगी, दुबई पहुंचने की उम्मीद है।
- भारत-यूएई सीईपीए उन प्रमुख द्विपक्षीय व्यापार समझौतों में से पहला है, जिसके लिए भारत कोविड-19 के बाद के परिदृश्य में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को शुरू करने के लिए बातचीत कर रहा है।

भारत-यूएई सीईपीए की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- भारत-यूएई सीईपीए पिछले एक दशक में किसी भी देश के साथ भारत द्वारा हस्ताक्षरित पहला गहरा और पूर्ण मुक्त व्यापार समझौता है।
- समझौता एक व्यापक समझौता है, जिसमें माल के व्यापार, उत्पत्ति के नियम, सेवाओं में व्यापार, व्यापार के लिए तकनीकी बाधाएं (टीबीटी), स्वच्छता और पादप स्वच्छता (एसपीएस) उपाय, विवाद निपटान, प्राकृतिक व्यक्तियों की आवाजाही, दूरसंचार, सीमा शुल्क शामिल होंगे। प्रक्रियाएं, फार्मास्युटिकल उत्पाद, सरकारी खरीद, आईपीआर, निवेश, डिजिटल व्यापार और अन्य क्षेत्रों में सहयोग।

प्रभाव या लाभ:

- सीईपीए दोनों देशों के बीच व्यापार को प्रोत्साहित करने और सुधारने के लिए एक संस्थागत तंत्र प्रदान करता है।
- भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच सीईपीए में भारत (11,908 टैरिफ लाइन) और संयुक्त अरब अमीरात (7581 टैरिफ लाइन) द्वारा निपटाए गए लगभग सभी टैरिफ लाइन शामिल हैं।
- भारत को 97% से अधिक टैरिफ लाइनों पर संयुक्त अरब अमीरात द्वारा प्रदान की जाने वाली तरजीही बाजार पहुंच से लाभ होगा, जो मूल्य के संदर्भ में संयुक्त अरब अमीरात को भारतीय निर्यात का 99% हिस्सा है, विशेष रूप से रत्न और आभूषण,

वस्त्र, जैसे सभी श्रम प्रधान क्षेत्रों के लिए – चमड़ा, जूते, खेल के सामान, प्लास्टिक, फर्नीचर, कृषि और लकड़ी के उत्पाद, इंजीनियरिंग उत्पाद, चिकित्सा उपकरण और ऑटोमोबाइल।

- भारत अपनी 90% से अधिक टैरिफ लाइनों पर यूएई को तरजीही पहुंच प्रदान करेगा, जिसमें यूएई को निर्यात ब्याज की लाइनें भी शामिल हैं।
- जहां तक सेवाओं के व्यापार का संबंध है, भारत ने लगभग 100 उप-क्षेत्रों में यूएई को बाजार पहुंच की पेशकश की है, जबकि भारतीय सेवा प्रदाताओं की 11 व्यापक सेवा क्षेत्रों के लगभग 111 उप-क्षेत्रों तक पहुंच होगी।
- क्षेत्रों में 'व्यावसायिक सेवाएं', 'संचार सेवाएं', 'निर्माण और संबंधित इंजीनियरिंग सेवाएं', 'वितरण सेवाएं', 'शैक्षिक सेवाएं', 'पर्यावरण सेवाएं', 'वित्तीय सेवाएं', 'स्वास्थ्य संबंधी और सामाजिक सेवाएं', 'पर्यटन और यात्रा संबंधी सेवाएं', 'मनोरंजक सांस्कृतिक और खेल सेवाएं' और 'परिवहन सेवाएं'।
- दोनों पक्षों ने निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करने वाले उत्पादों के लिए 90 दिनों में भारतीय फार्मास्यूटिकल्स उत्पादों, विशेष रूप से स्वचालित पंजीकरण और विपणन प्राधिकरण तक पहुंच की सुविधा के लिए फार्मास्यूटिकल्स पर एक अलग अनुबंध पर भी सहमति व्यक्त की है।

YOUR SUCCESS OUR PRIORITY
RAO'S ACADEMY
for Competitive Exams
(A unit of RACE)

5 विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी

जीएसएलवी-एफ10

खबरों में क्यों

पैनल ने जीएसएलवी मिशन की विफलता का कारण बताया।

महत्वपूर्ण बिंदु

- GSLV-F10/EOS-03 मिशन को पिछले साल अगस्त में सामान्य उत्थापन के बाद निरस्त कर दिया गया था।
- जीएसएलवी-एफ10/ईओएस-03 मिशन, जो पिछले साल अगस्त में श्रीहरिकोटा से लांच किया गया था, राष्ट्रीय स्तर की विफलता विश्लेषण समिति (FAC) के गठन के बाद पाया गया है, प्रक्षेपण यान के क्रायोजेनिक ऊपरी चरण (सीयूएस) के 'प्रदर्शन में विचलन' के कारण विफल रहा।
- हालांकि जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल

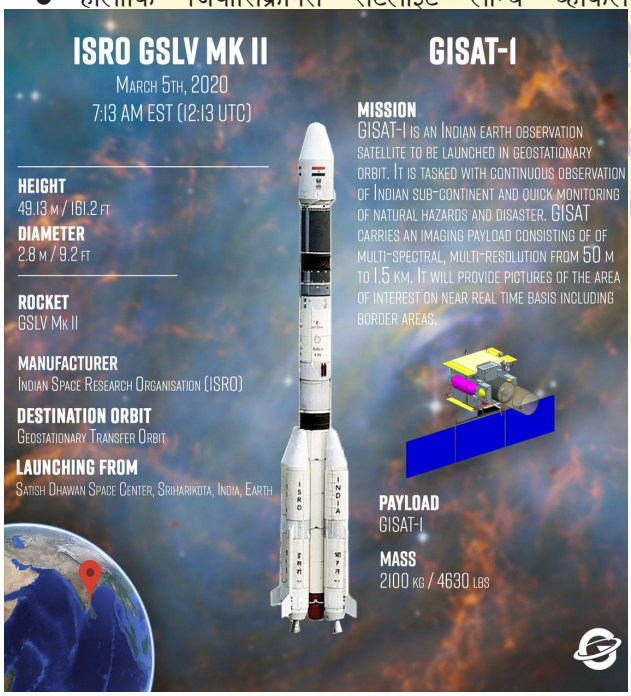

(जीएसएलवी) का 26 घंटे की उलटी गिनती के बाद सामान्य उत्थापन हुआ था, लेकिन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की निराशा के कारण मिशन को काफी हद तक निरस्त करना पड़ा।

- एफएसी, जिसमें अंतरिक्ष एजेंसी और शिक्षा जगत के विशेषज्ञ शामिल थे, ने हाल ही में अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किए।
- एफएसी ने निष्कर्ष निकाला है कि एक वेंट और रिलीफ वाल्व (वीआरवी) में रिसाव, संभवत: नरम सील में क्षति से उत्पन्न हुआ, जिसके परिणामस्वरूप एलएच 2 (तरल हाइड्रोजन, प्रणोदक) टैंक में कम दबाव हुआ जब सीयूएस इंजन प्रज्वलित हुआ।
- इससे फ्यूल बूस्टर टर्बो पंप (FBTP) खराब हो गया, जिससे अंतत: मिशन विफल हो गया।

सिफारिशों

- इसरो के अनुसार, एफएसी ने भविष्य के जीएसएलवी मिशनों के लिए सीयूएस की श्शमजबूती बढ़ानेश्श के लिए व्यापक सिफारिशें की हैं।
- अनुशंसाओं में इंजन के जलने से पहले टैंक में पर्याप्त दबाव की गारंटी के लिए एक सक्रिय LH_2 टैंक दबाव प्रणाली का समावेश शामिल है। अन्य सिफ़ारिशों में रिसाव से बचने के लिए वीआरवी और संबंधित द्रव सर्किट को मजबूत करना शामिल है।

जीएसएलवी मिशन ईओएस-03 पर सवार था, एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिसे भू-तुल्यकालिक स्थानांतरण कक्षा (जीटीओ) में रखा जाना था। इसने स्वदेश निर्मित क्रायोजेनिक इंजन के साथ आठवीं उड़ान और जीएसएलवी की 14वीं उड़ान को चिह्नित किया। असफल प्रक्षेपण के तुरंत बाद की गई प्रारंभिक जांच ने सीयूएस में खलनायक के रूप में एक विसंगति की ओर इशारा किया था।

इसरो फ्यूचर मिशन

- ♦ मिशन का नाम अपेक्षित प्रक्षेपण अंतरिक्ष यान
- ♦ गगनयान 1 जून 2022 मानव रहित अंतरिक्ष यान उड़ान परीक्षण
- ♦ आदित्य-एल1 मध्य 2022 सौर अवलोकन
- ♦ चंद्रयान-3 अगस्त 2022 लूनर लैंडर, रोवर

- ♦ गगनयान 2 2022-2023 मानव रहित अंतरिक्ष यान उड़ान परीक्षण

जीनोम अनुक्रमण

खबरों में क्यों

अधिकांश मानव जीनोम की मैपिंग के दो दशक बाद, वैज्ञानिकों ने अब जो अंतराल बना हुआ है उसे भर दिया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- लगभग दो दशक पहले, जब वैज्ञानिकों ने पहली बार मानव जीनोम का नक्शा प्रकाशित किया था, तो इसे एक सफलता के रूप में देखा गया था।
- यह अधूरा था, हालांकि: मानव डीएनए का लगभग 8% बिना क्रम के छोड़ दिया गया था।
- अब, विज्ञान में प्रकाशित पत्रों की एक श्रृंखला में, एक बड़ी टीम ने पहली बार मानव जीनोम की तस्वीर को पूरा करते हुए, उस 8% के लिए जिम्मेदार है।

जीनोम अनुक्रमण का महत्व

- एक पूर्ण मानव जीनोम व्यक्तियों के बीच या आबादी के बीच आनुवंशिक भिन्नता का अध्ययन करना आसान बनाता है।
- जीनोम एक जीव में सभी आनुवंशिक सामग्री को संदर्भित करता है, और मानव जीनोम ज्यादातर सभी लोगों में समान होता है, लेकिन डीएनए का एक बहुत छोटा हिस्सा एक व्यक्ति और दूसरे के बीच भिन्न होता है।
- एक संपूर्ण मानव जीनोम का निर्माण करके, वैज्ञानिक विभिन्न व्यक्तियों के जीनोम का अध्ययन करते समय इसका उपयोग संदर्भ के लिए कर सकते हैं, जिससे उन्हें यह समझने में मदद मिलेगी कि कौन सी विविधताएं, यदि कोई हो, बीमारी के लिए जिम्मेदार हो सकती हैं।

मानव जीनोम परियोजना

- मानव जीनोम परियोजना से 2003 में उपलब्ध कराए गए आनुवंशिक अनुक्रम, 1990 और 2003 के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, में यूक्रोमैटिन नामक मानव जीनोम के एक क्षेत्र की जानकारी शामिल थी।
- यहाँ, गुणसूत्र जीनों में समृद्ध है, और डीएनए प्रोटीन के लिए कूटबद्ध करता है।
- जो 8% बचा था वह हेटरोक्रोमैटिन नामक क्षेत्र में था। यह जीनोम का एक छोटा हिस्सा है, और प्रोटीन का उत्पादन नहीं करता है।

हेटरोक्रोमैटिन को कम प्राथमिकता देने के कम से कम दो प्रमुख कारण थे।

- जीनोम के इस भाग को "जंक डीएनए" माना जाता था, क्योंकि इसका कोई स्पष्ट कार्य नहीं था। इसके अलावा, यूक्रोमैटिन में अधिक जीन होते थे जो उस समय उपलब्ध उपकरणों के साथ अनुक्रम में सरल थे।
- पूरी तरह से अनुक्रमित जीनोम एक वैश्विक सहयोग के प्रयासों का परिणाम है जिसे टेलोमेरे-2-टेलोमेरे (टी2टी) परियोजना कहा जाता है।
- डीएनए अनुक्रमण और कम्प्यूटेशनल विश्लेषण के नए तरीकों के आविष्कार ने शेष 8% जीनोम को पढ़ने में मदद की।

8% में क्या है?

- नए संदर्भ जीनोम, जिसे T2T-CHM13 कहा जाता है, में टेलोमेरेस (गुणसूत्रों के सिरों पर संरचनाएं) और सेंट्रोमियर (प्रत्येक गुणसूत्र के मध्य भाग में) में और उसके आसपास पाए जाने वाले अत्यधिक दोहराव वाले डीएनए अनुक्रम शामिल हैं।
- नए अनुक्रम से डीएनए के लंबे हिस्सों का भी पता चलता है जो जीनोम में दोहराए जाते हैं और विकास और बीमारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए जाने जाते हैं।

स्वदेशी बुद्धिमान परिवहन प्रणाली (आईटीएस)

खबरों में क्यों

InTranSE-II कार्यक्रम के तहत भारतीय यातायात परिदृश्य के लिए स्वदेशी इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम (ITS) समाधान लॉन्च किया गया।

महत्वपूर्ण बिंदु

- इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) की भारतीय शहरों के चरण- II पहल के लिए इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंडेवर के तहत एक स्वदेशी ऑनबोर्ड ड्राइवर सहायता और चेतावनी प्रणाली - ODAWS, बस सिग्नल प्रायो. रिटी सिस्टम और कॉमन SMartiotConnectiv (CoSMiC) सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है।

RAO'S ACADEMY for Competitive Exams (A unit of RACE)

- उत्पाद को उन्नत कंप्यूटिंग के विकास केंद्र (सीडीएसी) और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास (आईआईटी-एम) द्वारा संयुक्त पहल के रूप में विकसित किया गया था। महिंद्रा एंड महिंद्रा इस परियोजना के औद्योगिक सहयोगी थे।

1. **जहाज पर चालक सहायता और चेतावनी प्रणाली - ODAWS:**

- ओडीएडब्ल्यूएस में चालक सहायता के लिए ध्वनिक और दृश्य अलर्ट देने के लिए चालक की प्रवृत्ति और वाहन के परिवेश की निगरानी के लिए वाहन-जनित सेंसर शामिल हैं।
- परियोजना में नेविगेशनल यूनिट, ड्राइवर सहायता कंसोल और एमएमवेव रडार सेंसर जैसे उप-मॉड्यूल का विकास शामिल है।
- आसपास के वाहनों की स्थितिगत और गतिशील विशेषताओं की जांच एमएमवेव रडार सेंसर का उपयोग करके की जाती है।
- नेविगेशनल सेंसर वाहन के सटीक भू-स्थानिक अभिविन्यास के साथ-साथ ड्राइविंग व्यवहार में रुझान प्रदान करता है।
- ODAWS एल्गोरिथम का उपयोग सेंसर डेटा की व्याख्या करने और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ड्राइवर को रीयल-टाइम सूचनाएं प्रदान करने के लिए किया जाता है।

2. **बस सिग्नल प्राथमिकता प्रणाली:**

- बस सिग्नल प्राथमिकता प्रणाली एक परिचालन रणनीति है जो सिग्नल नियंत्रित चौराहों पर सेवा में सार्वजनिक बसों को बेहतर ढंग से समायोजित करने के लिए सामान्य ट्रैफिक सिग्नल संचालन को संशोधित करती है।
- आपातकालीन वाहनों के लिए दी जाने वाली अंधा प्राथमिकता के विपरीत, यहां यह एक सशर्त प्राथ. मिकता है, जो केवल तभी दी जाती है जब सभी वाहनों के लिए देरी में समग्र रूप से कमी आती है।
- विकसित प्रणाली सार्वजनिक परिवहन बसों को प्राथमिकता देकर, ग्रीन एक्सटेंशन या रेड ट्रंकेशन के माध्यम से, सिग्नल वाले चौराहे पर आने वाले सभी वाहनों को ध्यान में रखते हुए, व्यक्ति की देरी को कम करने में सक्षम बनाएगी।

3. **कॉमन स्मार्ट आईओटी कनेक्टिव** (CoSMiC):

- यह एक मिडलवेयर सॉफ्टवेयर है जो oneM2M आधारित वैश्विक मानक का पालन करते हुए IoT का मानक आधारित परिनियोजन प्रदान करता है।
- यह विभिन्न वर्टिकल डोमेन में उपयोगकर्ताओं और एप्लिकेशन सेवा प्रदाताओं को एक एम2एम मानक का अनुपालन करने वाली अच्छी तरह से परिभाषित सामान्य सेवा कार्यात्मकताओं के साथ एंड टू एंड संचार के लिए एप्लिकेशन अज्ञेय खुले मानकों और खुले इंटरफेस का उपयोग करने की सुविधा प्रदान करता है।
- CoSMiC प्लेटफॉर्म CoSMiCI लेटफॉर्म से कनेक्ट होने के लिए गैर-oneM2M (NoDN) डिवाइस या तृतीय-पक्ष एप्लिकेशन को जोड़ने के लिए इंटरवर्किंग प्रॉक्सी एंटिटी (IPE) API भी प्रदान करता है।
- CoSMiC एक भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) मानचित्र में IoTb काइयों, उत्पादों, अनुप्रयोगों और इसके लाइव डेटा को दर्शाने वाला एक डैशबोर्ड पृष्ठ प्रदान करता है।

ग्लोबल वार्मिंग चुनौती

खबरों में क्यों

कार्बन के लिए नई सामग्री और प्रक्रियाएं ग्लोबल वार्मिंग चुनौती पर नई रोशनी दिखा सकती हैं।

महत्वपूर्ण बिंदु

- भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान, आईआईसीटी, हैदराबाद के वैज्ञानिकों के एक समूह ने एक हाइब्रिड सामग्री तैयार की है जो ग्रीनहाउस गैस मीथेन को अवशोषित कर सकती है और इसे स्वच्छ हाइड्रोजन में परिवर्तित कर सकती है।
- उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने और इसे गैर-ईंधन ग्रेड बायोएथेनॉल से उच्च शुद्धता हाइड्रोजन में परिवर्तित करने की एक प्रक्रिया का अनुकरण किया है।
- इन वैज्ञानिकों ने एक ऐसी सुविधा भी तैयार की है जो इस तरह की सामग्रियों का परीक्षण कर सकती है और संस्थान में आगे कार्बन कैप्चर अनुसंधान में मदद कर सकती है।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि कार्बन कैप्चर और उपयोग के लिए ये नई सामग्री और

YOUR SUCCESS OUR PRIORITY
RAO'S ACADEMY for Competitive Exams (A unit of RAAS)

प्रक्रियाएं ग्लोबल वार्मिंग चुनौती पर नई राह दिखा सकती हैं।

- शोधकर्ताओं ने एक ऐसी सुविधा भी तैयार की है जो संस्थान में कार्बन कैप्चर और रूपांतरण अनुसंधान को आगे बढ़ा सकती है।
- सुविधा, एक दोहरी परिचालन स्थिर सह द्रवित बिस्तर रिएक्टर प्रणाली (एफबीआर) मॉडलिंग और प्रारंभिक प्रयोगात्मक अध्ययनों के आधार पर उच्च शुद्धता एच 2 उत्पादन के लिए सॉर्प्शन एन्हांस्ड स्टीम मीथेन सुधार (एसईएसएमआर) कर सकती है।
- आईआईसीटी हैदराबाद को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित एक मिशन इनोवेशन प्रोजेक्ट के तहत सीएसआईआर-आईआईसीटी, हैदराबाद में हाल ही में जनवरी 2022 में एफबीआर सुविधा को सफलतापूर्वक चालू किया गया है।
- फ्लुइडाइज्ड बेड रिएक्टर सिस्टम में एसईएसएमआर के लिए दोहरी कार्यात्मक सामग्री के प्रदर्शन का परीक्षण करने के लिए यह देश में पहली बार अद्वितीय और उपलब्ध है।
- SESMR सॉर्बेंट्स के माध्यम से इन-सीटू CO2 हटाने के विशिष्ट लाभ प्रदान करता है और इस तरह भाप सुधार की संतुलन सीमाओं को पार करता है और उच्च शुद्धता H2 उत्पादन की ओर जाता है।
- सैद्धांतिक भविष्यवाणियों से पहचानी गई संभावित दोहरी कार्यात्मक सामग्री को अब संश्लेषित किया जा रहा है और साथ ही कार्बन कैप्चर और उपयोग और संबंधित अनुसंधान की बढ़ती चुनौतियों का सामना करने के लिए मौजूदा सॉर्बेंट/उत्प्रेरक सामग्री के लिए एफबीआर परिचालन स्थितियों को अनुकूलित किया जा रहा है।

झींगा की खेती

खबरों में क्यों

झींगा की खेती को बढ़ावा देने के लिए जलीय कृषि रोग. जनक के लिए नया पेटेंट निदान उपकरणविकसित किया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- वैज्ञानिकों ने एक आसान नैदानिक उपकरण विकसित किया है जो एक जलीय कृषि रोगजनक का पता लगाता है जिसे व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस (WSSV) के रूप में जाना जाता है।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के एक स्वायत्त संस्थान, आगरकर अनुसंधान संस्थान (एआरआई) के वैज्ञानिकों द्वारा पेप्टाइड-आधारित नैदानिक उपकरण को वैकल्पिक जैव पहचान तत्व के रूप में 31 मार्च 2022 को पेटेंट दिया गया है।
- WSSV के कारण झींगे को संक्रमण के कारण पेनियस वन्नामेई से फसल को भारी नुकसान होता है।
- यह उच्च मूल्य का सुपर-फूड वायरल और बैक्टीरियल रोगजनकों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए अतिसंवेदनशील है और संक्रमण होने की संभावना काफी अधिक है।
- उन्नत पोषण, प्रोबायोटिक्स, रोग प्रतिरोधक क्षमता, पानी, बीज और चारा का गुणवत्ता नियंत्रण, प्रतिरक्षी उत्तेजक और किफायती टीके उत्पादन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- मैदान पर रोगजनकों का शीघ्र और तेजी से पता लगाने के लिए प्रौद्योगिकियों से मछली और शंख-मछली की खेती में मदद मिलेगी जो देश को महत्वपूर्ण निर्यात राजस्व प्रदान करता है जो संयुक्त राज्य अमेरिका को झींगा का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है।
- WSSV के लिए एक आसान, स्व-उपयोग निदान प्रदान करने के लिए, वैज्ञानिक ने परिणामों के आसान दृश्य के लिए सोने के नैनोकणों का उपयोग करके एक पार्श्व प्रवाह परख विकसित की।
- परख विकास में पॉली-/मोनो-क्लोनल एंटीबॉडी का उपयोग करने के बजाय, एआरआई वैज्ञानिकों ने बायोपैनिंग द्वारा एक फेज डिस्प्ले लाइब्रेरी से बारह अमीनो एसिड युक्त पेप्टाइड्स का चयन किया।
- एंटीसेरा प्राप्त करने के लिए प्रयोगशाला पशुओं के प्रतिरक्षण की आवश्यकता को समाप्त करते हुए, यह एक समय और लागत बचाने वाला दृष्टिकोण था। पेप्टाइड्स के उपयोग के साथ, भंडारण के लिए कोल्ड-चेन की आवश्यकताएं कम हो जाती हैं और परख उत्पादन के अनुकूल हो जाती है।

व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस (WSSV)

- सफेद धब्बे रोग (डब्लूएसडी) डिकैपोड क्रस्टेशियंस का एक अत्यधिक संक्रामक वायरल संक्रमण है जो संवर्धित झींगा में उच्च स्तर की मृत्यु का कारण बन सकता है।

RAJ'S ACADEMY for Competitive Exams (A unit of RACE)

- 1992-93 में अपने पहले प्रकोप के बाद से, इस बीमारी ने गंभीर आर्थिक नुकसान किया है।
- WSD का प्रेरक एजेंट व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस (WSSV) है, जो एक बड़ा, गैर-आच्छादित, आच्छादित, रॉड के आकार का अण्डाकार डीएनए वायरस है जिसके एक सिरे पर पूंछ जैसा विस्तार होता है।
- WSSV नाभिक में गुणा करता है और क्रस्टेशियंस के बीच एक बहुत व्यापक मेजबान श्रेणी है।
- यह रोग विषाणुओं के एक समूह से जुड़ा है जो आनुवंशिक संरचना में समान प्रतीत होते हैं और भौगोलिक रूप से व्यापक रूप से फैले हुए हैं।

पोर्टेबल सोलर रूफटॉप

खबरों में क्यों

गुजरात को मिला भारत का पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम।

महत्वपूर्ण बिंदु

- भारत में कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए अक्षय संसाधनों की आवश्यकता का हवाला देते हुए, पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम अब गांधीनगर, गुजरात में स्थापित किया गया है।
- नया 10 पीवी पोर्ट सिस्टम अत्यधिक लागत प्रभावी होने के लिए डिजाइन किया गया है, कम रखरखाव की आवश्यकता है, और इसे एक व्यक्ति द्वारा स्थापित किया जा सकता है।
- ड्यूश गेसेलशाफ्ट फर इंटरनेशनेल जुसमेनरबीट (जीआईजेड) नामक एक जर्मन विकास एजेंसी द्वारा विकसित 10 पीवी पोर्ट सिस्टम गांधीनगर में स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर परिसर में स्थापित किया गया है।
- इस पर केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की पहल का ध्यान रखा जाता है। पीवी पोर्ट सिस्टम मानक प्लग-एंड-प्ले फोटोवोल्टिक सिस्टम हैं, जिसमें न्यूनतम 2ॅच होता है, जो बैटरी स्टोरेज के साथ या बिना आता है।
- पीवी पोर्ट सिस्टम को 100% स्व-उपभोग के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मतलब है कि ग्रिड में कोई बिजली नहीं डाली जाती है।
- सिस्टम को अधिक शक्ति और उच्च दक्षता प्रदान करने के लिए सौर पैनलों के नीचे की जगह का उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है। इनमें से एक प्रणाली एक भारतीय परिवार को हर साल बिजली बिलों पर औसतन 24,000 रुपये तक बचाने में मदद कर सकती है।
- 10 पीवी पोर्ट सिस्टम, जो भारतीय जलवायु के लिए डिजाइन किए गए हैं, नई दिल्ली स्थित कंपनी सर्वोटेक पावर सिस्टम्स लिमिटेड द्वारा निर्मित हैं, जो उच्च अंत सौर उत्पादों के अग्रणी निर्माताओं में से एक है।
- कंपनी मेक इन इंडिया पहल के तहत काम करती है और पूरे गांधीनगर में 40 ऐसे पीवी पोर्ट सिस्टम स्थापित करने की जिम्मेदारी दी गई है।
- कंपनी पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी, इंद्रोदा पार्क, निफ्ट, आर्य भवन, जीएसपीसी भवन और अन्य स्थानों पर पहले ही 30 सिस्टम स्थापित कर चुकी है।

रूफटॉप सोलर पीवी सिस्टम: यह कैसे काम करता है?

- सोलर पीवी रूफटॉप सिस्टम मूल रूप से रूफटॉप पर एक छोटा पावर प्लांट है।
- ग्रिड इंटरएक्टिव रूफ टॉप सोलर फोटो वोल्टाइक (पीवी) में मुख्य रूप से तीन प्रमुख घटक होते हैं।
- ये सौर पीवी मॉड्यूल, मॉड्यूल के लिए माउंटिंग संरचना और इन्वर्टर या पावर कंडीशनिंग इकाइयां हैं।
- सौर पीवी मॉड्यूल एक सरणी बनाते हैं और अधिकतम उत्पादन के लिए आवश्यक कोण पर पीवी मॉड्यूल रखने के लिए इसे एक बढ़ते ढांचे की आवश्यकता होती है।
- सौर पैनल सौर ऊर्जा को प्रकाश के रूप में डीसी रूप (डायरेक्ट करंट) में बिजली में परिवर्तित करते हैं।
- डीसी विद्युत ऊर्जा को इन्वर्टर/पावर कंडीशनिंग इकाई द्वारा एसी (वैकल्पिक वर्तमान) शक्ति में परिवर्तित किया जाता है जो एसी वितरण बोर्ड के माध्यम से पावर ग्रिड से जुड़ा होता है।
- एसी पावर आउटपुट को इससे जुड़े मीटरिंग पैनल के माध्यम से मापा जा सकता है।
- सिस्टम के 415 वी एसी आउटपुट को ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज किया जा सकता है और सौर

RAO'S ACADEMY for Competitive Exams (A unit of RACE) YOUR SUCCESS OUR PRIORITY

ऊर्जा उत्पादन और स्थानीय खपत के आधार पर बिजली को ग्रिड को निर्यात किया जा सकता है।

5जी सेवा

खबरों में क्यों

हाल ही में केंद्रीय संचार मंत्री ने कहा था कि अगस्त-सितंबर 2022 से 5G सेवाओं के वाणिज्यिक रोलआउट की उम्मीद की जा सकती है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- सरकार जून की शुरुआत में 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी कर सकती है।
- सरकार ने कहा कि दूरसंचार विभाग अपेक्षित समय सीमा के अनुसार काम कर रहा है और स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण के आसपास उद्योग की चिंताओं को हल करने की प्रक्रिया जारी है।
- 5जी सेवाओं के रोलआउट के लिए मंच तैयार करते हुए, दूरसंचार नियामक ट्राई ने 30 वर्षों में आवंटित रेडियो तरंगों के लिए कई बैंडों में आधार मूल्य पर 7.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की एक मेगा नीलामी योजना तैयार की है।
- डिजिटल संचार आयोग ट्राई की सिफारिशों पर विचार करेगा और स्पष्टीकरण के लिए उनसे संपर्क करेगा।
- अगर सरकार इसे 30 साल की अवधि के लिए आवंटित करती है तो वॉचडॉग ने 1 लाख मेगाहर्ट्ज से अधिक स्पेक्ट्रम के लिए 7.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक की मेगा नीलामी योजना की सिफारिश की है।
- बैक-ऑफ-द-लिफाफा गणना के अनुसार, 20 वर्षों के मामले में, प्रस्तावित स्पेक्ट्रम नीलामी का कुल मूल्य आरक्षित मूल्य पर लगभग 5.07 लाख करोड़ रुपये होगा।
- जहां ट्राई ने पिछले मूल्य की तुलना में स्पेक्ट्रम की कीमत में लगभग 39 प्रतिशत की कमी की है, वहीं दूरसंचार ऑपरेटरों ने कहा है कि अनुशंसित दरें वैश्विक बेंचमार्क से अधिक हैं।
- सरकार ने कहा कि ग्रामीण और दूरदराज के परिवारों को जोड़ने की जरूरत है जिसके लिए उद्योग को स्वस्थ होना है और सस्ती दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए स्पेक्ट्रम की उचित कीमत होनी चाहिए।

लगभग 5जी

- 5G वायरलेस तकनीक की पांचवीं पीढ़ी है।
- यह 4जी एलटीई नेटवर्क की तुलना में उच्च गति, कम विलंबता और अधिक क्षमता प्रदान कर सकता है। यह दुनिया की अब तक की सबसे तेज, सबसे मजबूत तकनीकों में से एक है।
- इंडस्ट्री 4.0, स्मार्ट फैक्ट्री, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IIoT) - ये औद्योगिक निर्माण का भविष्य हैं। उत्पादन संयंत्रों और इंट्रालॉजिस्टिक्स को अधिक लचीला, स्वायत्त और कुशल बनाने के लिए सही संचार ढांचे और व्यापक कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है। नया 5G संचार मानक महत्वपूर्ण नई संभावनाओं को खोलता है।

एलसीआरडी

खबरों में क्यों

नासा की नई संचार प्रणाली स्ब्क

महत्वपूर्ण बिंदु

- नासा ने हाल ही में अपने लेजर संचार रिले प्रदर्शन (एलसीआरडी) का प्रदर्शन किया।
- नासा ने फ्लोरिडा में केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से अपना नया लेजर कम्युनिकेशंस रिले डिमॉन्स्ट्रेशन (एलसीआरडी) - एजेंसी की पहली लेजर संचार प्रणाली - लॉन्च की।
- एलसीआरडी एजेंसी को अंतरिक्ष में ऑप्टिकल संचार का परीक्षण करने में मदद करेगा।
- यह एजेंसी की पहली लेजर संचार प्रणाली है।

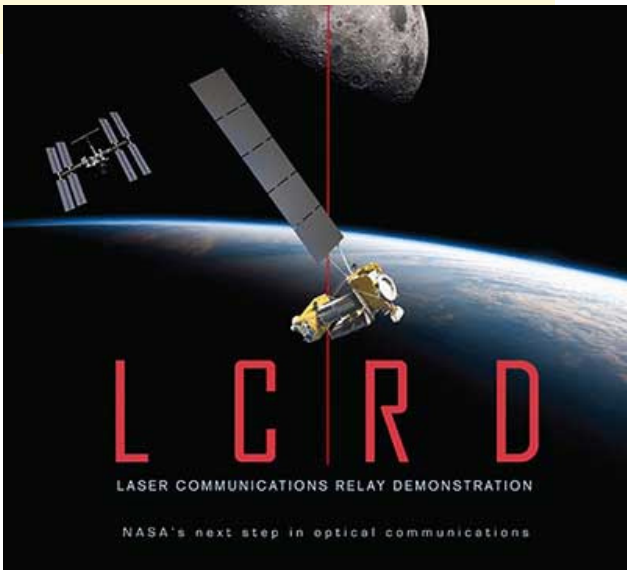

RAO'S ACADEMY for Competitive Exams (A unit of RACE)

- वर्तमान में, नासा के अधिकांश अंतरिक्ष यान डेटा भेजने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी संचार का उपयोग करते हैं। ऑप्टिकल संचार रेडियो फ्रीक्वेंसी सिस्टम की तुलना में बैंडविड्थ को 10 से 100 गुना अधिक बढ़ाने में मदद करेगा।
- एलसीआरडी लेजर सिस्टम का उपयोग करने के सभी लाभों को प्रदर्शित करेगा और हमें यह सीखने की अनुमति देगा कि उनका सर्वोत्तम संचालन कैसे किया जाए।
- एलसीआरडी के दो ऑप्टिकल टर्मिनल हैं – एक उपयोगकर्ता अंतरिक्ष यान से डेटा प्राप्त करने के लिए, और दूसरा ग्राउंड स्टेशनों पर डेटा संचारित करने के लिए मोडेम डिजिटल डेटा को लेजर सिग्नल में ट्रांसलेट करेगा।
- इसके बाद इसे प्रकाश के एन्कोडेड बीम के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा। एजेंसी ने एक विज्ञप्ति में कहा कि ये क्षमताएं एलसीआरडी नासा का पहला टू-वे, एंड-टू-एंड ऑप्टिकल रिले बनाती हैं।
- लेजर वी.एस. रेडियो
- लेजर संचार और रेडियो तरंगें प्रकाश की विभिन्न तरंग दैर्ध्य का उपयोग करती हैं। लेजर अवरक्त प्रकाश का उपयोग करता है और रेडियो तरंगों की तुलना में कम तरंग दैर्ध्य होता है। इससे कम समय में ज्यादा डाटा ट्रांसफर करने में मदद मिलेगी।

लाभ

- ऑप्टिकल संचार प्रणालियां आकार, वजन में छोटी होती हैं और रेडियो उपकरणों की तुलना में कम शक्ति की आवश्यकता होती है।
- छोटे आकार का अर्थ है विज्ञान के उपकरणों के लिए अधिक जगह।
- कम वजन का मतलब कम खर्चीला लॉन्च है। कम शक्ति का अर्थ है अंतरिक्ष यान की बैटरियों का कम निकास। रेडियो के पूरक ऑप्टिकल संचार के साथ, मिशन में अद्वितीय संचार क्षमताएं होंगी।

लेजर सिस्टम कहां होगा?

- एलसीआरडी पेलोड को अमेरिकी रक्षा विभाग के अंतरिक्ष परीक्षण कार्यक्रम सैटेलाइट 6 (एसटीपीएसएटी -6) पर होस्ट किया गया है। यह भू-समकालिक कक्षा में होगा, जो पृथ्वी से 35,000 किमी ऊपर होगा।

RAO'S ACADEMY
for Competitive Exams
(A unit of RACE)
YOUR SUCCESS OUR PRIORITY

6 सामाजिक मुद्दे

धूम्रपान

खबरों में क्यों

धूम्रपान से सालाना सात मिलियन से अधिक मौतें होती हैं।

महत्वपूर्ण बिंदु

भारत में करीब 12 करोड़ धूम्रपान करने वाले हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य के आलोक में इसे कम करने की जरूरत है।

डब्ल्यूएचओ (और यूएस के एफडीए) के अनुमानों के अनुसार 1.3 बिलियन लोग (दुनिया भर में 7.9 बिलियन में से) धूम्रपान करते हैं, और उनमें से 80% निम्न और मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं।

इस प्रकार धूम्रपान एक महामारी और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा है, जिससे साल भर में आठ मिलियन से अधिक लोग मारे जाते हैं। इनमें से सात मिलियन से अधिक लोग सीधे तंबाकू के सेवन से मर जाते हैं, और 12 लाख गैर धूम्रपान करने वाले जो सेकेंड हैंड धुएं के संपर्क में आते हैं।

डॉ. स्मिलजानिक स्टाशा का एक हालिया लेख बताता है कि-

1. धूम्रपान से हर साल 70 लाख से अधिक मौतें होती हैं,
2. 5.6 मिलियन युवा अमेरिकी धूम्रपान के कारण मर सकते हैं
3. सेकेंड हैंड स्मोकिंग से दुनिया भर में 1.2 मिलियन लोगों की मौत होती है
4. धूम्रपान दुनिया की गरीबी के प्रमुख कारणों में से एक है, और
5. 2015 में, 10 में से 7 धूम्रपान करने वालों (68%) ने बताया कि वे पूरी तरह से धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं।

डब्ल्यूएचओ ने 2003 में तंबाकू नियंत्रण पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन को अपनाया, इसे 2030 के सतत विकास एजेंडा (एसडी) में वैश्विक विकास लक्ष्य के रूप में शामिल किया गया है। यदि सभी 155 हस्ताक्षरकर्ता देश धूम्रपान प्रतिबंध, स्वास्थ्य चेतावनी, विज्ञापन प्रतिबंध को अपनाते हैं और सिगरेट की लागत बढ़ाते हैं, तो यह स्थायी विकास वास्तव में संभव है।

भारतीय परिदृश्य

- भारत ने एक कम आय वाले देश से एक विकसित देश में स्नातक किया है, और अनुमान है कि 120 मिलियन धूम्रपान करने वाले (138 करोड़ की आबादी में से), या लगभग 9% भारतीय लोग हैं।
- भारत और पड़ोसी देशों में कैनबिस नामक सामग्री प्रचलित थी। भांग एक पौधा उत्पाद है जिसे मारिजुआना, चरस, हशीश, गांजा और भांग आदि स्थानीय नामों से जाना जाता है ।
- इसका सेवन (धूम्रपान) करने पर उपयोगकर्ता 'सक्रिय' महसूस करता है। कैनबिस में सक्रिय सिद्धांत टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनोल नामक एक साइको एक्टिव अणु है, जो इसके मनो-सक्रिय और नशीले प्रभावों के लिए जिम्मेदार है।
- तंबाकू में सक्रिय सिद्धांत निकोटीन अणु है।

तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध

- भारत में लगभग 12 करोड़ लोग धूम्रपान करते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य के आलोक में इसे काफी कम करने की आवश्यकता है। भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय सिगरेट की बिक्री पर रोक लगाने के लिए तैयार है। भारत तंबाकू नियंत्रण पर WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन का एक पक्ष बन गया है।
- इस ढांचे और एसडी लक्ष्यों के अनुसार, हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय ने कई सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों जैसे स्वास्थ्य सेवा, शैक्षिक और सरकारी सुविधाओं और सार्वजनिक परिवहन में धूम्रपान पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। ये स्वागत योग्य कदम हैं और हम जनता को इनका सहयोग

RAO'S ACADEMY for Competitive Exams (A unit of RACE)

करना चाहिए।

एवीजीसी प्रचार कार्य

खबरों में क्यों

केंद्र ने एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक सेक्टर के लिए एवीजीसी प्रमोशन टास्क फोर्स की स्थापना की।

महत्वपूर्ण बिंदु

- सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (एवीजीसी) प्रमोशन टास्क फोर्स का गठन किया है।
- सूचना एवं प्रसारण सचिव की अध्यक्षता में कार्यबल 90 दिनों के भीतर अपनी पहली कार्य योजना प्रस्तुत करेगा। इसमें उद्योग, शिक्षा और राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व है।

टास्क फोर्स को जिन जिम्मेदारियों को सौंपा गया है उनमें शामिल हैं:

- राष्ट्रीय एवीजीसी नीति तैयार करना,
- एवीजीसी से संबंधित क्षेत्रों में स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे की सिफारिश करना,
- शैक्षणिक संस्थानों, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों और उद्योग के सहयोग से कौशल पहल को सुगम बनाना,
- रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना,
- भारतीय एवीजीसी उद्योग की वैश्विक पहुंच बढ़ाने के लिए प्रचार और बाजार विकास गतिविधियों को सुगम बनाना,
- एवीजीसी क्षेत्र में एफडीआई आकर्षित करने के लिए निर्यात में वृद्धि और प्रोत्साहन की सिफारिश करना।
- यह रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देगा; भारतीय उद्योग की वैश्विक पहुंच बढ़ाने के लिए प्रचार और बाजार विकास गतिविधियों में मदद करना; इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए निर्यात में वृद्धि और प्रोत्साहन की सिफारिश करना।
- टास्क फोर्स में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सचिव शामिल हैं।

राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक

खबरों में क्यों

स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स-राउंड-I लॉन्च किया गया।

महत्वपूर्ण बिंदु

- नीति आयोग ने 11 अप्रैल 2022 को स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स-राउंड-I लॉन्च किया है।

स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स (SECI) राउंड-I, राज्यों के प्रदर्शन को 6 मापदंडों पर रैंक करता है, अर्थात;

1. डिस्कॉम का प्रदर्शन
2. ऊर्जा की पहुंच, वहनीयता और विश्वसनीयता
3. स्वच्छ ऊर्जा पहल
4. ऊर्जा दक्षता
5. पर्यावरणीय स्थिरता; और
6. नई पहल।

- मापदंडों को आगे 27 संकेतकों में विभाजित किया गया है।
- समग्र SECI राउंड-I स्कोर के आधार पर, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तीन समूहों में वर्गीकृत किया गया है: फ्रंट रनर, अचीवर्स और एस्पिरेंट्स।
- राज्यों को आकार और भौगोलिक अंतर के आधार पर बड़े राज्यों, छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- गुजरात, केरल और पंजाब को बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष तीन प्रदर्शनकर्ताओं के रूप में स्थान दिया गया है।
- गुजरात ने नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक-राउंड-1 (एसईसीआई) में बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान हासिल किया है, जिसका उद्देश्य डिस्कॉम के प्रदर्शन, ऊर्जा दक्षता और पर्यावरणीय स्थिरता सहित छह मापदंडों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) की रैंकिंग करना है।
- गोवा, छोटे राज्यों की श्रेणी में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा, इसके बाद त्रिपुरा और मणिपुर का स्थान है।
- केंद्र शासित प्रदेशों में, चंडीगढ़, दिल्ली और दमन

RAO'S ACADEMY for Competitive Exams (A unit of RACE) YOUR SUCCESS OUR PRIORITY

और दीव/दादरा और नगर हवेली शीर्ष प्रदर्शनकर्ता हैं।

- नीति आयोग ने जोर देकर कहा कि सीओपी-26, ग्लासगो में माननीय प्रधान मंत्री द्वारा घोषित 'पंचामृत' लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रयासों को एक जन आंदोलन में बदलने की आवश्यकता है।
- सूचकांक का उपयोग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपने साथियों के खिलाफ अपने प्रदर्शन को बेंचमार्क करने के लिए किया जा सकता है, बेहतर नीति तंत्र विकसित करने के लिए संभावित चुनौतियों का विश्लेषण करने और अपने ऊर्जा संसाधनों को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए किया जा सकता है।

रेशम शहरों का वैश्विक नेटवर्क

खबरों में क्यों

बेंगलुरु रेशम शहरों के वैश्विक नेटवर्क में शामिल हुआ।

महत्वपूर्ण बिंदु

- बेंगलुरू रेशम शहरों के वैश्विक नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है।
- बेंगलुरु अब सिल्की सिटी नेटवर्क का एक हिस्सा है, जो आठ देशों में स्थित शहरों और रेशम महानगरों का एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क है।
- इसके साथ, भारत इस रेशम मानचित्र पर फ्रांस, चीन, ब्राजील, जापान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, इटली और स्पेन के साथ नौवां देश बन गया है।
- रेशम शहरों का वैश्विक नेटवर्क: नेटवर्क 2019 में फ्रांस में मेट्रोपोल डी लियोन और एक फ्रांसीसी रेशम संघ, इंटरसोई कंसोर्टियम द्वारा बनाया गया था। इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र शामिल हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय रेशम उत्पादन आयोग (आईएससी), एक अंतर-सरकारी संगठन, जो रेशम उत्पादन और रेशम उद्योग के विकास पर केंद्रित है, ने अपना कार्यालय फ्रांस के ल्योन से बेंगलुरु स्थानांतरित कर दिया और जनवरी 2013 से कार्य कर रहा है।
- बेंगलुरू को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, यह तकनीकी क्षमता प्रदान करती है जो वस्त्रों में नवाचार की सुविधा प्रदान कर सकती है, जिस तरह फ्रांस में एक कपड़ा समूह टेकटेरा सहयोगी नवाचार के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने का प्रयास करता है।
- नेटवर्क में बेंगलुरु का प्रवेश इस साल के अंत में फ्रांस में नवंबर के महीने में रेशम केंद्रित कार्यक्रम के दौरान किया जा सकता है।

स्वनिधि से समृद्धि

खबरों में क्यों

अतिरिक्त 126 शहरों में 'स्वनिधि से समृद्धि' कार्यक्रम लॉन्च किया गया।

महत्वपूर्ण बिंदु

- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में 14 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के अतिरिक्त 126 शहरों में 'स्वनिधि से समृद्धि' कार्यक्रम शुरू किया।
- 'स्वनिधि से समृद्धि', PMSVANidhi का एक अतिरिक्त कार्यक्रम 4 जनवरी 2021 को चरण 1 में 125 शहरों में शुरू किया गया था, जिसमें लगभग 35 लाख स्ट्रीट वेंडर और उनके परिवार शामिल थे।
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत 16 लाख बीमा लाभ और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत 2.7 लाख पेंशन लाभ सहित अन्य लाभों के साथ 22.5 लाख योजनाओं को मंजूरी दी गई है।
- चरण-I की सफलता को ध्यान में रखते हुए, MoHUAus वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कुल 20 लाख योजना स्वीकृतियों के लक्ष्य के साथ 28 लाख स्ट्रीट वेंडरों और उनके परिवारों को कवर करने के उद्देश्य से अतिरिक्त 126 शहरों में कार्यक्रम का विस्तार शुरू किया। शेष शहरों को धीरे-धीरे कार्यक्रम में जोड़ा जाएगा।
- एमओएचयूए 1 जून 2020 से प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वानिधि), एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना लागू कर रहा है।
- इस योजना का उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स को एक किफायती कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना है और सफ. लतापूर्वक 30 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है। जैसा कि माननीय प्रधान मंत्री ने कल्पना की थी, इस योजना का उद्देश्य न केवल रेहड़ी-पटरी वालों को ऋण देना है, बल्कि उनका समग्र विकास और आर्थिक उत्थान भी करना है।

RAO'S ACADEMY for Competitive Exams (A unit of RAO'S) YOUR SUCCESS OUR PRIORITY

- इसे ध्यान में रखते हुए रेहड़ी-पटरी वालों को उनके समग्र विकास और सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए 'स्वनिधि से समृद्धि' कार्यक्रम शुरू किया गया था।
- एमओएचयूए ने उल्लेख किया कि कार्यक्रम की दो मुख्य उपलब्धियां हैं: एक, स्ट्रीट वेंडरों और उनके परिवारों का एक केंद्रीय डेटाबेस विभिन्न सामाजिक-आर्थिक संकेतकों पर बनाया गया है।
- दूसरा, रेहड़ी-पटरी बेचने वाले परिवारों को कल्याणकारी योजनाओं के सुरक्षा जाल का विस्तार करने के लिए विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों के बीच अपनी तरह का पहला अंतर-मंत्रालयी अभिसरण मंच स्थापित किया गया है।
- कार्यक्रम के तहत, भारत सरकार की 8 कल्याण कारी योजनाओं के लिए उनकी पात्रता का आकलन करने और पात्र योजनाओं की मंजूरी की सुविधा के लिए PMSVANidhi लाभार्थियों और उनके परिवारों की सामाजिक-आर्थिक रूपरेखा तैयार की जाती है।
- भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) कार्यक्रम के लिए कार्यान्वयन भागीदार है।

इन योजनाओं में शामिल हैं-

- ♦ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
- ♦ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
- ♦ प्रधानमंत्री जन धन योजना
- ♦ भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार का विनियमन और सेवा की शर्तें) अधिनियम (बीओसीडब्ल्यू) के तहत पंजीकरण
- ♦ प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना
- ♦ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) सुवाह्यता लाभ - एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ONORC)
- ♦ जननी सुरक्षा योजना और
- ♦ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)।

हरियाणा में चारे के परिवहन पर प्रतिबंध

खबरों में क्यों

हरियाणा सरकार ने गेहूं चारे के अंतर-जिला और अंतर-राज्यीय परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- हरियाणा में अधिकारियों ने गेहूं चारे के अंतर-जिला और अंतर-राज्यीय परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया है, यह कहते हुए कि वे पहले स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करना चाहते हैं।
- इस फैसले की किसान समूहों और विपक्ष ने तीखी आलोचना की है।
- हरियाणा में चारे के परिवहन पर दो तरह की पाबंदी लगाई गई है. फतेहाबाद और सिरसा जैसे कुछ जिलों ने अन्य जिलों में भी परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया है।
- ईंट-भट्ठा और गत्ते की फैक्ट्रियों के लिए भी गेहूं, धान, सरसों और गौर के भूसे से बने सूखे चारे की अंतर-जिला बिक्री पर रोक लगा दी गई है।
- फतेहाबाद के किसान नेताओं ने दावा किया कि वहां की सरकार ने जिले की सीमा पर करीब 100 ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को भी रोक दिया है।
- अंबाला और यमुनानगर समेत अन्य जिलों के प्रशासन ने राज्य के बाहर चारे के परिवहन पर रोक लगा दी है।
- हरियाणा कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने दावा किया कि स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए केवल चारे के अंतरराज्यीय परिवहन पर प्रतिबंध लगाया गया है।
- हरियाणा राज्य के भीतर चारे के परिवहन को नहीं रोकेगा, राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद अंतर-राज्यीय प्रतिबंध भी हटा लिया जाएगा।

चारे की कमी की आशंका

- मुख्य रूप से दो कारण हैं: एक, दक्षिणी हरियाणा में गेहूं के स्थान पर सरसों की फसल का चयन करने वाले अधिक किसान और दो, गर्मी की शुरुआत के कारण गेहूं के सामान्य उत्पादन से कम और इस वर्ष पारा में असाधारण वृद्धि के साथ।
- अधिकारियों का मानना है कि प्रतिकूल मौसम की स्थिति गेहूं के चारे के उत्पादन को भी प्रभावित कर सकती है। किसानों का कहना है कि डीएपी (डाय-अमोनियम फॉस्फेट) उर्वरक की कमी ने भी गेहूं की फसल को प्रभावित किया है।
- अंतरराज्यीय परिवहन की तुलना में चारे के अंतर

RAO'S ACADEMY for Competitive Exams (A unit of RAOS)

-जिला परिवहन पर प्रतिबंध से किसान अधिक परेशान हैं।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (NCF)

खबरों में क्यों

हाल ही में 'जनादेश दस्तावेज: एनसीएफ के विकास के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए थे।

महत्वपूर्ण बिंदु

- शिक्षा को बदलना नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 का विजन और आत्मा है।
- शिक्षा को और अधिक समावेशी बनाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मैंडेट डॉक्यूमेंट जारी किया।

जनादेश दस्तावेज में क्या है?

- राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एनसीएफ) को परिवर्तनकारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के केंद्र के रूप में देखा जाता है जिसमें देश में उत्कृष्ट शिक्षण और सीखने को सशक्त बनाने और सक्षम करने की क्षमता है।
- एनईपी 2020 चार क्षेत्रों- स्कूल शिक्षा, प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई), शिक्षक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे (एनसीएफ) के विकास की सिफारिश करता है।
- जनादेश दस्तावेज एनसीएफ की प्रक्रिया के विकास, इसकी संरचना, उद्देश्यों और एनईपी 2020 के कुछ बुनियादी सिद्धांतों के लिए जिम्मेदार है जो चार एनसीएफ के विकास को सूचित करेंगे।
- जनादेश दस्तावेज एनईपी 2020 और एनसीएफ के बीच एक सेतु का काम करता है।

जनादेश दस्तावेज

- यह एक सुसंगत और व्यापक एनसीएफ के विकास के लिए तंत्र स्थापित करता है, जो पहले से चल रहे व्यापक परामर्श का पूरी तरह से लाभ उठाता है।
- प्रक्रिया को समग्र, एकीकृत और बहु-विषयक शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए एनईपी 2020 में निर्बाध एकीकरण - लंबवत (चरणों में) और क्षैतिज रूप से (एक ही चरण में विषयों में) सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है।
- यह समग्र शिक्षक शिक्षा क्षेत्र में एनईपी 2020 द्वारा परिकल्पित परिवर्तनकारी सुधारों के एक अभिन्न अंग के रूप में शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रम के साथ स्कूलों के पाठ्यक्रम के बीच महत्वपूर्ण जुड़ाव को सक्षम बनाता है, इस प्रकार कठोर तैयारी, निरंतर व्यावसायिक विकास और हमारे सभी शिक्षकों के लिए पर्यावरणसकारात्मक कार्य को सक्षम बनाता है।
- यह देश के सभी नागरिकों के लिए जीवनपर्यंत सीखने के अवसरों के सृजन की सूचना देता है
- ध्वनि सिद्धांत और अत्याधुनिक शोध से प्रेरित और सूचित, फिर भी विभिन्न संदर्भों में कक्षाओं और स्कूलों से वास्तविक जीवन के चित्रण के साथ सरल भाषा का उपयोग करना
- आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, NCF शिक्षा मंत्रालय द्वारा NIPUN भारत, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरिकेसी के लिए राष्ट्रीय मिशन जैसी अन्य पहलों के लिए भी पूरी तरह से जिम्मेदार होगा, जिन्हें आवश्यक तात्कालिकता के साथ लागू किया जा रहा है, जबकि NCF विकसित किया जा रहा है।

नया राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा क्यों महत्वपूर्ण है?

- एक नया राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा (एनसीएफ) विकसित करने के लिए सितंबर 2021 में एक 12-सदस्यीय राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया गया था, जो पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों को डिजाइन करने और देश में शिक्षण प्रथाओं को सूचित करने के लिए एक दिशानिर्देश के रूप में काम कर सकता है।
- यह उजागर करना प्रासंगिक है कि भारत वर्तमान में चौथे एनसीएफ का अनुसरण कर रहा है - जिसे 2005 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा प्रकाशित किया गया था।
- लेकिन 2005 से अब तक, नए अवसरों के उद्भव के संदर्भ में जहां रोजगार पैदा हुए हैं और मांग और आपूर्ति के मामले में रोजगार बाजार की गतिशीलता में भारी बदलाव आया है।
- आज भारत में 65% से अधिक बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं।
- इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारत में 1.5 मिलियन स्कूलों, 9.6 मिलियन से अधिक शिक्षकों और 264 मिलियन से अधिक बच्चों के साथ दुनिया के सबसे बड़े शिक्षा क्षेत्रों में से एक है; सीखने के परिणामों को प्राथमिकता देना अनिवार्य

RAO'S ACADEMY for Competitive Exams (A Unit of RACE) YOUR SUCCESS OUR PRIDE

हो जाता है।

- आधारभूत सीखने के कौशल महत्वपूर्ण हैं और इसमें निरंतर सुधार की आवश्यकता हैऔर इसका एक बड़ा हिस्सा पाठ्यक्रम तैयार करने के तरीके में निहित है।
- नि:संदेह, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का बहु-विषयक शिक्षा और कम उम्र के कौशल पर ध्यान देना प्रशंसनीय है।

ई-बीसीएएस

खबरों में क्यों

नागरिक उड्डयन मंत्रालय आंतरिक प्रक्रियाओं को स्वचालित करने पर विचार कर रहा है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- नागर विमानन मंत्रालय से जुड़ी संसदीय सलाहकार समिति की बैठक।
- चर्चा का विषय 'ई-बीसीएएस परियोजना' था।
- बीसीएएस राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा कार्यक्रम की स्थापना, विकास, रखरखाव और समीक्षा करता है।
- यह उड़ानों की सुरक्षा, नियमितता और दक्षता को ध्यान में रखते हुए, गैरकानूनी हस्तक्षेप और खतरे के कृत्यों के खिलाफ नागरिक उड्डयन संचालन की सुरक्षा भी करता है।
- इसने अब ई-बीसीएएस शुरू किया है, जो आंतरिक प्रक्रियाओं के स्वचालन के लिए ई-गवर्नेंस के तहत एक पहल है।
- हितधारकों की सुविधा के लिए यह एक ऑनलाइन मंच होगा।
- यह पूरी गतिविधियों को पारदर्शी, उपयोगकर्ता के अनुकूल और कुशल बनाने के उद्देश्य से मौजूदा प्रक्रियाओं और संगठनात्मक संरचना की ताकत का लाभ उठाएगा।
- यह विभिन्न प्रभागों और प्रक्रियाओं में तकनीकी एकीकरण द्वारा कार्यालय प्रक्रियाओं को डिजिटाइज करेगा, तेजी से अनुमोदन की सुविधा प्रदान करेगा और व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करेगा।

'ई-बीसीएएस परियोजना'

- बायोमेट्रिक सक्षम केंद्रीकृत अभिगम नियंत्रण प्रणाली (सीएसीएस) और ई-बीसीएएस परियोजना के प्रशिक्षण मॉड्यूल को लॉन्च किया गया - हवाई अड्डों पर कर्मचारी आंदोलन प्रक्रिया को डिजिटाइज करने का लक्ष्य है।
- वर्तमान में एएआई के 43 हवाई अड्डों और 5 संयुक्त उद्यम हवाई अड्डों को कवर करते हुए, सीएसीएस परियोजना का उद्देश्य हवाई अड्डों पर कर्मचारी आंदोलन प्रक्रिया को डिजिटल बनाना है।
- 'ई-बीसीएएस परियोजना: प्रशिक्षण मॉड्यूल' का उद्देश्य विभिन्न हितधारकों के 1.5 लाख से अधिक कर्मचारियों को प्रशिक्षण की मैनुअल प्रक्रिया से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित करके मदद करना है।
- ई-बीसीएएस परियोजना का उद्देश्य बीसीएएस में सभी गतिविधियों को पारदर्शी, उपयोगकर्ता के अनुकूल और कुशल बनाना है और सबसे बढ़कर, परियोजना का उद्देश्य हितधारकों के साथ व्यापार करने में आसानी प्रदान करना है।

RAO'S ACADEMY for Competitive Exams (A unit of RACE)

7 अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध

ओपेक+ (OPEC+)

खबरों में क्यों

ओपेक+ पर पुतिन और सऊदी क्राउन प्रिंस सकारात्मक सहयोग के लिए तैयार।

महत्वपूर्ण बिंदु

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने विश्व तेल बाजार को स्थिर करने के लिए ओपेक + उत्पादक समूह पर उनके सहयोग के लिए ष्सकारात्मक मूल्यांकनष् दिया।

सऊदी अरब और अन्य प्रमुख फारस की खाड़ी के तेल उत्पादकों ने अब तक उत्पादन बढ़ाने के लिए अमेरिकी नीति का विरोध किया है क्योंकि यूक्रेन में संकट और रूसी निर्यात पर संभावित प्रतिबंधों के बारे में चिंताओं के बीच कीमतों में वृद्धि हुई है। इसलिए, स्थिति को ठीक करने के लिए इस तरह के उपाय आवश्यक हैं।

OPEC के बारे में

- पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन (OPEC) एक स्थायी, अंतरसरकारी संगठन है, जिसे ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला द्वारा 10-14 सितंबर, 1960 को बगदाद सम्मेलन में बनाया गया था।
- OPEC का मुख्यालय अपने अस्तित्व के पहले पांच वर्षों में जिनेवा, स्विटजरलैंड में था। इसे 1 सितंबर, 1965 को वियना, ऑस्ट्रिया में स्थानांतरित कर दिया गया था।
- OPEC ने उत्पादन के समन्वय और कीमतों को स्थिर करने के लिए रूस और कई अन्य प्रमुख निर्यातकों के साथ भागीदारी की।
- जुलाई 2019 में, उन्होंने यू.एस. की आपत्तियों के बावजूद इस नए ओपेक+ गठबंधन को औपचारिक रूप दिया, क्योंकि वाशिंगटन को चिंता थी कि यह व्यवस्था वैश्विक तेल बाजारों पर मॉस्को के प्रभाव को बढ़ाएगी।

उद्देश्य:

OPEC का उद्देश्य पेट्रोलियम उत्पादकों के लिए उचित और स्थिर कीमतों को सुरक्षित करने के लिए सदस्य देशों के बीच पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय और एकीकरण करना है; उपभोग करने वाले देशों को पेट्रोलियम की कुशल, आर्थिक और नियमित आपूर्ति; और उद्योग में निवेश करने वालों को पूंजी पर उचित प्रतिफल प्राप्त करना।

- रूस और अन्य देशों के साथ तथाकथित OPEC$ गठबंधन बनाकर ब्लॉक ने अनुकूलित किया है, लेकिन COVID - 19 महामारी के कारण हुए व्यवधानों ने उन प्रयासों को कमजोर कर दिया है।
- 2022 में, यूक्रेन में रूस के युद्ध और इसके परिणा मस्वरूप वैश्विक तेल कीमतों में उछाल ने ओपेक पर ध्यान केंद्रित किया।
- ओपेक के लिए आज सबसे प्रमुख चुनौती शेल-आधा रित ऊर्जा जैसे अपरंपरागत तेलों से आती है, जो हाल की तकनीकी प्रगति के माध्यम से उपलब्ध हो गए हैं।
- 2022 में, यूक्रेन पर रूस के आक्रमण और प्रतिक्रिया में पश्चिम द्वारा लगाए गए कठोर प्रतिबंधों के कारण वैश्विक तेल कीमतों में वृद्धि हुई है और ओपेक की भूमिका पर नए सिरे से ध्यान दिया गया है।

RAO'S ACADEMY for Competitive Exams (A unit of RACE)

स्मारकों और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस

खबरों में क्यों

18 अप्रैल को स्मारकों और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है

महत्वपूर्ण बिंदु

- हर साल, संयुक्त राष्ट्र18 अप्रैल को स्मारकों और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में चिह्नित करता है, कई देशों में इसे विश्व विरासत दिवस के रूप में भी मनाया जाता है।
- इस वर्ष का विषय ष्जटिल अतीतः विविध भविष्यष है।
- विश्व स्तर पर, इस दिन को स्मारकों और स्थलों पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद (ICOMOS) द्वारा प्रचारित किया जाता है।

विश्व विरासत दिवस

- 1982 में ICOMOS ने 18 अप्रैल को स्मारकों और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस या विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था।
- यूनेस्को द्वारा 1983 में अपने 22वें आम सम्मेलन के दौरान स्वीकृत, यह दिन ऐतिहासिक महत्व के स्थलों को पहचानने, उनके बारे में जागरूकता बढ़ाने और उन्हें पुनर्स्थापित करने और संरक्षित करने की आवश्यकता पर बल देने के लिए समर्पित है।
- इस प्रकार, यह दिन सांस्कृतिक महत्व को बढ़ावा देता है, साथ ही ऐसा करने में कई बाधाओं को भी उजागर करता है।
- हर साल, उस दिन के लिए एक थीम प्रस्तावित की जाती है जो आईसीओएमओएस राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समितियों और अन्य निकायों द्वारा समारोहों और कई गतिविधियों का मार्गदर्शन करती है।

भारत में विश्व धरोहर स्थल

- वर्तमान में, भारत में 40 विश्व धरोहर स्थल स्थित हैं।
- एक विरासत स्थल को 'मिश्रित', खांगचेंदजोंगा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- 2019 में, 'जयपुर सिटी' संस्कृति के तहत भारत की सूची में 38वां जोड़ बन गया।
- रामप्पा मंदिर (तेलंगाना) भारत का 39वां विश्व धरोहर स्थल था।
- गुजरात में हड़प्पा शहर धौलावीरा भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में सम्मिलित किया गया था।

चीन-पाक आर्थिक गलियारा

खबरों में क्यों

पाकिस्तान ने चीन-पाक आर्थिक गलियारा प्राधिकरण को रद्द करने का आदेश पारित किया।

महत्वपूर्ण बिंदु

- पाकिस्तान की नई सरकार ने चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा प्राधिकरण को समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू की है।
- पाकिस्तान की नई सरकार ने कहा है कि चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा प्राधिकरण एक "अनावश्यक संगठन" था जिसने संसाधनों को बर्बाद किया और महत्वाकांक्षी क्षेत्रीय संपर्क कार्यक्रम के त्वरित कार्यान्वयन को विफल कर दिया।
- चीन - पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) प्राधिकरण 2019 में एक अध्यादेश के माध्यम से स्थापित हुआ।
- इसका उद्देश्य सीपीईसी से संबंधित गतिविधियों की गति को तेज करना, विकास के नए चालकों को खोजना, क्षेत्रीय और वैश्विक कनेक्टिविटी के माध्यम से परस्पर जुड़े उत्पादन नेटवर्क और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं की संभावनाओं को खोलना था।
- सीपीईसी प्राधिकरण को बंद करने का निर्णय समानांतर सेटअप की स्थापना के खिलाफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) की पुरानी नीति के अनुरूप था।

चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC)

- चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपीईसी), बीजिंग के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के सबसे महत्वाकांक्षी घटकों में से एक, 2015 में बड़ी धूमधाम से घोषित किया गया था।
- सीपीईसी का लक्ष्य अंततः दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान के ग्वादर शहर को चीन के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र शिनजियांग से राजमार्गों और रेलवे के विशाल नेटवर्क के माध्यम से जोड़ना है।
- प्रस्तावित परियोजनाओं को भारी सब्सिडी वाले ऋणों

द्वारा वित्तपोषित किया जाता है, जो चीनी बैंकिंग दिग्गजों द्वारा पाकिस्तान सरकार को वितरित किए जाते हैं।

- सीपीईसी से ऋण लगभग 5.8 अरब डॉलर था, जो पाकिस्तान के कुल विदेशी कर्ज का 5.3% है।

भारत प्रारम्भ से ही इससे बाहर रहा

- बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर रहने का एक मुख्य कारण यह है कि इसमें शिनजियांग को पाकिस्तान से जोड़ने वाले गलियारे के हिस्से के रूप में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में परियोजनाएं शामिल हैं।
- इसके अतिरिक्त कश्मीर मुद्दे पर चीन की टिप्पणी विरोधात्मक थी।

फॉकलैंड आइलैंड

खबरों में क्यों

अर्जेंटीना, भारत में फॉकलैंड मुद्दे को पुनर्जीवित करेगा।

महत्वपूर्ण बिंदु

- हाल ही मेंफॉकलैंड द्वीप समूह पर यूनाइटेड किंगडम के साथ ष्संवाद के लिए आयोगष का उद्घाटन भारत और अर्जेंटीना द्वारा किया गया था।
- अर्जेंटीना सरकार भारत में एक अभियान शुरू करेगी जिसमें ब्रिटेन में फॉकलैंड द्वीप समूह के रूप में जाने जाने वाले इस्लास माल्विनास पर क्षेत्रीय विवाद को निपटाने के लिए यूनाइटेड किंगडम के साथ बातचीत की मांग की जाएगी।
- यह पहल, जो यूके के प्रधान मंत्री बोरिस जॉनसन की यात्रा के दो दिन बाद आती है, यूके और अर्जेंटीना के बीच संघर्ष की 40वीं वर्षगांठ के साथ मेल खाती है, जो द्वीपसमूह पर ब्रिटिश नियंत्रण की पुनः स्थापना के साथ समाप्त हुई।
- 1982 में "शत्रुता की समाप्ति" के साथ विवाद का समाधान नहीं हुआ और द्विपक्षीय वार्ता को फिर से शुरू करने का आग्रह किया।
- अर्जेंटीना का दावा है कि एक सशस्त्र संघर्ष का परिणाम माल्विनास/फॉकलैंड द्वीप समूह जैसे क्षेत्रीय विवाद को सुलझा नहीं सकता है।
- आयोग संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों और माल्विनास द्वीप समूह के प्रश्न पर अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों की घोषणाओं के अनुपालन को बढ़ावा देना चाहता है, जो अर्जेंटीना और यूनाइटेड किंगडम के बीच वार्ता को फिर से शुरू करने का आह्वान करता है।
- आयोग के सदस्यों में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु, भाजपा नेता शाजिया इल्मी, कांग्रेस के लोकसभा सांसद शशि थरूर और अनुभवी शांतिदूत तारा गांधी भट्टाचार्जी शामिल होंगे।
- हाल ही में काला सागर में रूसी मिसाइल क्रूजर मोस्कवा के डूबने से समानताएं फॉकलैंड युद्ध के दौरान हुई थीं, जो 2 अप्रैल, 1982 को शुरू हुआ था जब अर्जेंटीना की सेना ने यूके-नियंत्रित द्वीपों पर आक्रमण किया था।
- 78 दिनों तक चलने वाला फॉकलैंड युद्ध एक अनूठी घटना थी जिसमें शीत युद्ध के अंत के दौरान यूनाइटेड किंगडम और अर्जेंटीना शामिल थे और समुद्री युद्ध में सबक छोड़ दिया जिसने फ्रेंच एक्सोसेट मिसाइलों को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया।
- अर्जेन्टीना ने युद्ध की 40वीं वर्षगांठ का लाभ उठाते हुए फॉकलैंड मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फ्लैग करने की योजना बनाई, लेकिन यह सुनिश्चित किया कि भारत में आयोग शुरू करने की अर्जेंटीना की योजना के संबंध में भारतीय पक्ष के साथ कोई आधिकारिक परामर्श नहीं किया गया था।
- फॉकलैंड युद्ध मुख्य रूप से यूके और अर्जेंटीना दोनों में एक भावनात्मक मुद्दा बना हुआ है क्योंकि इसमें दोनों पक्षों के सैकड़ों युवा सैन्यकर्मी मारे गए हैं।

फॉकलैंड द्वीप समूह के बारे में

- फॉकलैंड द्वीप समूह दक्षिण अमेरिका के दक्षिण-पूर्वी तट से 400 मील (650 किमी) दूर स्थित है और इसमें लगभग 740 द्वीप हैं।
- सबसे बड़े द्वीपों को ईस्ट फॉकलैंड और वेस्ट फॉकलैंड कहा जाता है, जिसमें राजधानी स्टेनली पूर्व में स्थित है।
- परिदृश्य में पर्वत श्रृंखलाएं, समतल मैदान, ऊबड़-खाबड़ तटरेखा, रेतीले समुद्र तट और चट्टानें शामिल हैं।
- फॉकलैंड का उच्चतम बिंदु पूर्वी फॉकलैंड पर माउंट उसबोर्न है और इसकी सबसे ऊंची चोटी 705 मीटर (2,312 फीट) है।
- फॉकलैंड द्वीप समूह का मौसम ठंडे दक्षिण अटलांटिक महासागर से अत्यधिक प्रभावित होता

YOUR SUCCESS OUR PRIORITY
RAO'S ACADEMY
for Competitive Exams
(A unit of RACE)

है, जो इसे एक संकीर्ण वार्षिक तापमान देता है।

- वर्षा आम तौर पर हर मौसम में अलग-अलग नहीं होती है, गर्मियों में औसतन 48.7 मिमी प्रति माह और सर्दियों में 47.2 मिमी।
- 1 अप्रैल 1982 को अर्जेंटीना की सेना ने फॉकलैंड द्वीप पर आक्रमण किया। 14 जून 1982 को ब्रिटिश सेना ने 74 दिनों के कब्जे के बाद फॉकलैंड द्वीप समूह को मुक्त कराया।
- फॉकलैंड द्वीप के सभी लोग स्वेच्छा से यूनाइटेड किंगडम का प्रवासी क्षेत्र है।

सतत विकास लक्ष्य

खबरों में क्यों

पंचायती राज मंत्रालय, यूएनडीपी ने सतत विकास लक्ष्यों पर समझौते पर हस्ताक्षर किए

महत्वपूर्ण बिंदु

- पंचायती राज मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ने सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण पर एक संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए।
- पंचायती राज संस्थान (पीआरआई) ग्रामीण भारत में स्थानीय स्वशासन का एक महत्वपूर्ण घटक रहे हैं और भारत ने विभिन्न विभागों/मंत्रालयों की विभिन्न योजनाओं के अंतिम-मील संपर्क और निष्पादन में इन संस्थानों के योगदान को देखा है।
- एसडीजी को भी पंचायती राज संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी से ही प्राप्त किया जा सकता है।
- भारत की लगभग 65% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और सरकार ग्रामीण स्थानीय निकायों के माध्यम से स्वच्छता, आवास और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के वित्तपोषण को तेजी से आगे बढ़ा रही है।
- यूएनडीपी सतत विकास समन्वय केंद्रों के अपने हस्ताक्षर समाधान के माध्यम से एसडीजी को स्थानीयकृत और तीव्र करने के लिए नीति आयोग और राज्य सरकारों, विशेष रूप से हरियाणा, कर्नाटक, नागालैंड, पंजाब और उत्तराखंड के साथ साझेदारी में अग्रणी प्रयास कर रहा है।

सतत विकास लक्ष्यों के बारे में

- सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स (SDGs), जिन्हें ग्लोबल गोल्स के रूप में भी जाना जाता है, को संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2015 में अपनाया गया था।
- इसे गरीबी को समाप्त करने, ग्रह की रक्षा करने और 2030 तक सभी लोगों को शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई के लिए एक सार्वभौमिक आह्वान के रूप में माना जाता है।

- 17 एसडीजी एकीकृत हैं-वे मानते हैं कि एक क्षेत्र में कार्रवाई दूसरों में परिणामों को प्रभावित करेगी, और विकास को सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिरता को संतुलित करना चाहिए।
- देश उन लोगों के लिए प्रगति को प्राथमिकता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो सबसे पीछे हैं। एसडीजी को गरीबी, भूख, एड्स और महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है।

नाटो

खबरों में क्यों

रूस ने स्वीडन और फिनलैंड को नाटो सदस्यता के खिलाफ चेताया।

महत्वपूर्ण बिंदु

- रूस ने फिनलैंड और स्वीडन को नाटो में शामिल होने के खिलाफ चेतावनी दी है, यह तर्क देते हुए कि इस कदम से यूरोप में स्थिरता नहीं आएगी।
- नाटो, फिनलैंड और स्वीडन को "काफी जल्दी" अनुमति देना संभव होगा, लेकिन नाटो ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है कि एक फास्ट-ट्रैक प्रक्रिया क्या होगी।
- फिनलैंड सरकार ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद विदेश और सुरक्षा नीति के वातावरण में "मौलिक परिवर्तन" पर संसद को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, एक प्रक्रिया के भाग के रूप में जिसके

YOUR SUCCESS OUR PRIORITY
RAO'S ACADEMY
for Competitive Exams
(A unit of RACE)

परिणामस्वरूप उत्तर अटलांटिक संधि संगठन(नाटो) में शामिल होने या न होने पर निर्णय लेने की उम्मीद है।

- माना जाता है कि वाशिंगटन इस कदम का समर्थन करता है जिससे पश्चिमी गठबंधन 32 सदस्यों तक बढ़ जाएगा।
- आक्रमण शुरू करने से पहले, रूस ने मांग की थी कि गठबंधन भविष्य के किसी भी विस्तार को रोकने के लिए सहमत हो, लेकिन युद्ध ने अपने पूर्वी हिस्से पर अधिक नाटो सैनिकों की तैनाती और स्वीडिश और फिनिश सदस्यता के लिए सार्वजनिक समर्थन में वृद्धि का नेतृत्व किया है।
- यूक्रेन ने रूस पर पत्रकारों, कार्यकर्ताओं और निर्वाचित अधिकारियों सहित नागरिकों को रूसी क्षेत्र की जेलों में रखने का आरोप लगाया है।

नाटो के बारे में

- वाशिंगटन संधि पर हस्ताक्षर के साथ 1949 में गठित, नाटो उत्तरी अमेरिका और यूरोप के 30 देशों का एक सुरक्षा गठबंधन है। नाटो का मूल लक्ष्य राजनीतिक और सैन्य तरीकों से मित्र राष्ट्रों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की रक्षा करना है।
- नाटो ट्रान्साटलांटिक समुदाय का प्रमुख सुरक्षा साधन और अपने सामान्य लोकतांत्रिक मूल्यों की अभिव्यक्ति बना हुआ है।
- यह व्यावहारिक साधन है जिसके माध्यम से उत्तरी अमेरिका और यूरोप की सुरक्षा स्थायी रूप से एक साथ जुड़ी हुई है। नाटो के विस्तार ने पूरे यूरोप, स्वतंत्र और शांति के अमेरिकी लक्ष्य को आगे बढ़ाया है।
- संधि के अनुच्छेद पांच में कहा गया है कि यदि किसी सदस्य राज्य के खिलाफ सशस्त्र हमला होता है, तो इसे सभी सदस्यों के खिलाफ हमला माना जाना चाहिए, और अन्य सदस्य यदि आवश्यक हो तो सशस्त्र बलों के साथ हमला करने वाले सदस्य की सहायता करेंगे।
- नाटो के दो मुख्य भाग हैं, राजनीतिक और सैन्य घटक।
- नाटो मुख्यालय वह जगह है जहां सभी सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि एक साथ आम सहमति के आधार पर निर्णय लेने के लिए आते हैं।

नाटो कमांडर द्वारा नाटो सैन्य अभ्यास निर्धारित किया जाता है। इसका उद्देश्य गठबंधन के पूर्ण मिशन स्पेक्ट्रम में नाटो की सैन्य क्षमता को स्थापित करना, बढ़ाना और प्रदर्शित करना है जो तीन गठबंधन सैन्य मिशनों पर आधारित है:

1. अनुच्छेद 5 सामूहिक रक्षा;
2. गैर-अनुच्छेद 5 संकट प्रतिक्रिया; और
3. परामर्श और सहयोग।

वैश्विक सुरक्षा पहल

खबरों में क्यों

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक नई वैश्विक सुरक्षा पहल प्रस्तुत की है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा पेश की गई एक नई वैश्विक सुरक्षा पहल यू.एस. इंडो-पैसिफिक रणनीति और क्वाड - भारत, यू.एस., ऑस्ट्रेलिया, जापान समूह का मुकाबला करने के लिए देखेगी।
- शीजिनपिंग ने सबसे पहले "आधिपत्यवाद, सत्ता की राजनीति और गुट टकराव" के खिलाफ चेतावनी देते हुए, चीन में बोआओ फोरम में बोलते हुए एक वैश्विक सुरक्षा पहल का प्रस्ताव रखा।
- विशेष रूप से, उन्होंने एकतरफा प्रतिबंधों और लंबे समय तक अधिकार क्षेत्र के बेहूदा इस्तेमाल का विरोध किया, जो पश्चिमी प्रतिबंधों को संदर्भित करता प्रतीत होता है।
- चीन ने कहा कि कुछ देश विशेष 'छोटे घेरे' और 'छोटे समूहों' में शामिल होने के लिए उत्सुक थे, चीनी अधिकारियों ने पहले क्वाड के साथ-साथ AUKUS (ऑस्ट्रेलिया-यू.के.-यू.एस.)सुरक्षा समझौते का वर्णन करने के लिए उपयोग किया है।
- चीन की प्रस्तावित सुरक्षा पहल "तथाकथित 'नियमों' के बैनर तले अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का विनाश और 'नए शीत युद्ध' के बादल के नीचे दुनिया को घसीटने" का "विरोध" करेगी, और" आपसी सम्मान, खुलेपन और एकीकरण के एशियाई सुरक्षा मॉडल का निर्माण करें।
- चीन ने जोर देकर कहा कि वह क्षेत्र को विभाजित करने और 'नया शीत युद्ध' बनाने के लिए 'इंडो-पैसिफिक' रणनीति के इस्तेमाल और 'नाटो के एशियाई संस्करण' को एक साथ रखने के लिए सैन्य

गठबंधनों के इस्तेमाल का कड़ा विरोध करता है।

- चीन ने बीजिंग में वार्षिक नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के दौरान यह सुझाव देते हुए क्वाड पर निशाना साधा था कि यह समूह "फाइव आईज" के बराबर था।
- "फाइव आइज" ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यू.एस., यू.के. और औकस संधि को शामिल करने वाला एक खुफिया गठबंधन है।
- क्वाड के सदस्यों ने इस धारणा को खारिज कर दिया है कि यह एक एशियाई नाटो या एक सैन्य गठबंधन है, और टीके और प्रौद्योगिकी सहित इसके व्यापक-आधारित सहयोग की ओर इशारा किया है।

फाइव आईज के बारे में

- ♦ यह ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका की खुफिया एजेंसियों का गठबंधन है।
- ♦ इसकी उत्पत्ति द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में और मुख्य रूप से ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने की आवश्यकता से पता लगाया जा सकता है ताकि दोनों देश अपने करीबी युद्ध प्रयासों को बढ़ा सकें।
- ♦ 5 मार्च 1946 को यू.के.-यू.एस.ए. समझौते के रूप में जाने जाने वाले सिग्नल इंटेलिजेंस (SIGINT) में सहयोग के लिए बहुपक्षीय समझौते के माध्यम से, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद औपचारिक रूप से फाइव आइज की स्थापना की गई थी।
- ♦ प्रारंभ में, केवल यू.के. और संयुक्त राज्य अमे. रिका से समझौता करते हुए, इसका विस्तार 1948 में कनाडा और 1956 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को भी शामिल करने के लिए किया गया था।

साइबर सुरक्षा

खबरों में क्यों

माइक्रोसॉफ्ट ने भारत, 22 देशों में साइबर सुरक्षा कौशल अभियान शुरू किया।

महत्वपूर्ण बिंदु

- माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट सुरक्षा पेशेवरों की खतरनाक कमी को दूर करने के लिए भारत सहित 23 भौगोलिक क्षेत्रों में साइबर सुरक्षा कौशल विकास अभियान शुरू किया है।
- 2025 तक वैश्विक साइबर अर्थव्यवस्था पर नजर रखने वाले एक शोधकर्ता, साइबर सुरक्षा वेंचर्स के अनुसार, वैश्विक स्तर पर 3.5 मिलियन साइबर सुरक्षा नौकरियां उपलब्ध होंगी, जो आठ साल की अवधि में 350 प्रतिशत की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करती हैं।
- उस समय तक, अकेले भारत में निजी और सार्वज निक दोनों क्षेत्रों में लगभग 3.5 लाख साइबर सुरक्षा नौकरी पदों को भरने की प्रतीक्षा में होने का अनुमान है।
- आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान से लेकर रैंसमवेयर हमलों तक, साइबर अपराधी तेजी से परिष्कृत हो गए हैं और खतरे का परिदृश्य अधिक विविध हो गया है।
- ये साइबर सुरक्षा चुनौतियाँ कार्यबल की कमी से जटिल हो जाती हैं; खुली नौकरियों को भरने के लिए आवश्यक साइबर सुरक्षा कौशल सेट वाले पर्याप्त लोग नहीं हैं।
- माइक्रोसॉफ्ट ने इस अभियान को पहले यू.एस. में लॉन्च किया था और अब इसे भारत, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्राजील, कनाडा, कोलंबिया, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इजराइल, इटली, जापान, कोरिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, रोमानिया, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, स्विट्जरलैंड और यू.के.
- इन देशों में साइबर खतरे का खतरा बढ़ गया है, साथ ही साइबर सुरक्षा में काम करने वाले पेशेवरों की संख्या बनाम मांग के साथ-साथ विविधता की कमी दोनों के मामले में उनके साइबर सुरक्षा कार्यबल में एक महत्वपूर्ण अंतर है।
- इन देशों में, औसतन केवल 17% साइबर सुरक्षा कार्यबल महिलाएं हैं।
- महिलाओं को साइबर सुरक्षा कार्यबल में शामिल करने पर उनकी प्रतिभा निखर कर सामने आएगी और इससे कौशल अन्तर को समाप्त करने में सहायता मिलेगी।

यू.ए.ई. गोल्डन वीजा

खबरों में क्यों

यूएई गोल्डन वीजा प्राप्त करने के लिए रणवीर सिंह सेलेब्स की सूची में शामिल किया गया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- यास द्वीप अबू धाबी के ब्रांड एंबेसडर के रूप में हस्ताक्षर करने के कुछ दिनों बाद, बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को अबू धाबी संस्कृति और पर्यटन विभाग द्वारा यूएई गोल्डन वीजा से सम्मानित किया गया है।
- 'गली बॉय' अभिनेता के परिवार को भी इसी से सम्मानित किया गया है।
- उन्हें द्वीप के मिरल के सीईओ मोहम्मद अब्दुल्ला अल जाबी द्वारा प्रतिष्ठित 10 वर्षीय निवास वीजा प्राप्त हुआ।
- वीजा के लाभों में से एक यह है कि यह विदेशियों को संयुक्त अरब अमीरात में काम करने, रहने और अध्ययन करने में सक्षम बनाता है। हालाँकि, एक अंतर है क्योंकि व्यक्तियों को प्रायोजक की आवश्यकता नहीं होगी।
- सिंह यह सम्मान पाने वाले पहले बॉलीवुड सेलिब्रिटी नहीं हैं।
- वास्तव में, दुनिया भर में कई हस्तियां हैं जिन्हें गोल्डन वीजा से सम्मानित किया गया है जिनमें शाहरुख खान, संजय दत्त, सुनील शेट्टी, सोनू निगम, अली जफर, बोनी कपूर और अर्जुन कपूर शामिल हैं।
- मलयालम फिल्म उद्योग के लोकप्रिय सितारे, जैसे मोहनलाल, ममूटी, और पृथ्वीराज सुकुमारन के पास भी यह प्रतिष्ठित वीजा है।
- अभिनेता ने हाल ही में यास आइलैंड के मार्केटिंग अभियान, 'यस है खास' (यस स्पेशल) के हिस्से के रूप में एक वीडियो में दिखाया था, जिसमें अभिनेता ने स्थल के आकर्षण और प्रसाद की विविधता का प्रदर्शन किया था।
- अभियान का उद्देश्य भारत के यात्रियों को किसी अन्य की तरह छुट्टी का अनुभव करने के लिए आमंत्रित करना था।

गोल्डन वीजा

- गोल्डन वीजा प्रणाली अनिवार्य रूप से निम्नलिखित समूहों से संबंधित लोगों को 5 और 10 साल की लंबी अवधि के निवास की पेशकश करती है: निवेशक, उद्यमी, उत्कृष्ट प्रतिभा वाले व्यक्ति जैसे शोधकर्ता, चिकित्सा और वैज्ञानिक और ज्ञान पेशेवर, और उत्कृष्ट छात्र।
- रेजीडेंसी और विदेश मामलों के सामान्य निदेशालय (जीडीआरएफए) ने 'यू आर स्पेशल' नामक एक नई 24×7 सेवा की घोषणा की। इस सेवा का उद्देश्य अन्य लोगों के साथ - साथ गोल्डन वीजा धारकों की सहायता करना है।
- वीजा का मुख्य लाभ सुरक्षा होगा, क्योंकि गोल्डन वीजा जारी करने के माध्यम से, यूएई सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह प्रवासियों, निवेशकों और अनिवार्य रूप से यूएई को अपना घर बनाने के इच्छुक सभी लोगों को एक अतिरिक्त कारण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अपने भविष्य को लेकर सुरक्षित महसूस करते हैं।

यूएई गोल्डन वीजा के लिए पात्रता

- कम से कम एईडी 10 मिलियन के सार्वजनिक निवेश वाले निवेशक 10 वर्षीय वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं, चाहे वह निवेश कोष के रूप में हो या कंपनी के रूप में।
- हालांकि, कुल निवेश का कम से कम 60 प्रतिशत अचल संपत्ति के रूप में नहीं होना चाहिए और निवेश की गई राशि को उधार नहीं दिया जाना चाहिए या संपत्ति के मामले में, निवेशकों को पूर्ण स्वामित्व लेना चाहिए।
- निवेशक को भी कम से कम तीन साल के लिए निवेश रखने में सक्षम होना चाहिए।
- व्यापार भागीदारों को शामिल करने के लिए 10 साल के गोल्डन वीजा को तब तक बढ़ाया जा सकता है जब तक कि प्रत्येक भागीदार एईडी 10 मिलियन का योगदान देता है। लंबी अवधि के वीजा में धारक के पति या पत्नी और बच्चों के साथ-साथ एक कार्यकारी निदेशक और सलाहकार भी शामिल हो सकते हैं।
- 5 साल के गोल्डन वीजा के लिए, नियम निवेशकों के लिए बहुत समान हैं, केवल अंतर यह है कि आवश्यक निवेश राशि AED 5 मिलियन है।
- संयुक्त अरब अमीरात में अपनी कंपनी स्थापित करने के इच्छुक विदेशी भी गोल्डन बिजनेस वीजा योजना के माध्यम से 5 साल के स्थायी निवास के लिए आवेदन कर सकते हैं।

RAO'S ACADEMY for Competitive Exams (A unit of RACE) YOUR SUCCESS OUR PRIORITY

8 सरकारी योजना

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएम-जीकेएवाई)

खबरों में क्यों

कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएम-जीकेएवाई) के विस्तार को 6 महीने के लिए मंजूरी दी।

महत्वपूर्ण बिंदु

- प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएम-जीकेएवाई) योजना को और छह महीने यानी सितंबर 2022 (चरण-VI) तक बढ़ा दिया है।
- PM-GKAY योजना का चरण-V मार्च 2022 में समाप्त होना था। ध्यातव्य होगा कि PM-GKAY कोदुनिया के सबसे बड़े खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के रूप में अप्रैल 2020 से लागू किया जा रहा है।
- विस्तारित पीएम-जीकेएवाई के तहत प्रत्येक लाभार्थी को एनएफएसए के तहत खाद्यान्न के अपने सामान्य कोटे के अलावा प्रति व्यक्ति प्रति माह अतिरिक्त 5 किलो मुफ्त राशन मिलेगा। इसका मतलब है कि हर गरीब परिवार को सामान्य मात्रा से लगभग दोगुना राशन मिलेगा।
- वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) योजना के तहत देश भर में लगभग 5 लाख राशन की दुकानों से किसी भी प्रवासी श्रमिक या लाभार्थी द्वारा पोर्टेबिलिटी के माध्यम से मुफ्त राशन का लाभ उठाया जा सकता है। अब तक, 61 करोड़ से अधिक पोर्टेबिलिटी लेनदेन ने लाभार्थियों को उनके घरों से दूर कर लाभान्वित किया है।

वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC)

- वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के अंतर्गत आने वाले सभी लाभार्थियों को उनकी भौतिक स्थिति पर ध्यान दिए बिनादेश में कहीं भी सब्सिडी वाली खाद्य सुरक्षा पात्रताओं का निर्बाध वितरण सुनिश्चित करने के लिए विभाग की एक महत्वाकांक्षी योजना और प्रयास है।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य सभी एनएफएसए लाभार्थियों को देश में कहीं भी अपनी खाद्य सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भर होने के लिए सशक्त बनाना है, अपने मौजूदा राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी के माध्यम से किसी भी ईपीओएस (इलेक्ट्रॉनिक) से अपने सब्सिडी वाले खाद्यान्न (आंशिक या पूर्ण) को निर्बाध रूप से उठाने के लिए। पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस) ने देश में उचित मूल्य की दुकान को बायोमेट्रिक / आधार प्रमाणीकरण के साथ पोर्टेबिलिटी के माध्यम से खाद्यान्न उठाने के समय सक्षम किया।

रैंप (RAMP)

खबरों में क्यों

कैबिनेट ने "एमएसएमई प्रदर्शन को बढ़ाने और तेज करने" के लिए 808 मिलियन अमरीकी डालर को मंजूरी दी।

महत्वपूर्ण बिंदु

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 808 मिलियन अमरीकी डालर या 6,062.45 करोड़ रुपये, "एमएसएमई प्रदर्शन को बढ़ाने और तेज करने" (RAMP) पर विश्व बैंक सहायता प्राप्त कार्यक्रम को मंजूरी दी।
- RAMP एक नई योजना है और वित्त वर्ष 2022-23 में शुरू होगी।

रैंप (RAMP)

- यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MoMSME) के विभिन्न कोरोना वायरस रोग 2019 (COVID) के लचीलेपन और रिकवरी हस्तक्षेपों का समर्थन करने वाली एक विश्व बैंक सहायता प्राप्त केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
- कार्यक्रम का उद्देश्य बाजार और ऋण तक पहुंच में सुधार करना, केंद्र और राज्य में संस्थानों और शासन को मजबूत करना, केंद्र-राज्य संबंधों और

RAO'S ACADEMY for Competitive Exams (A Unit of RACE)

साझेदारी में सुधार करना, विलंबित भुगतान के मुद्दों को संबोधित करना और एमएसएमई को हरा-भरा बनाना है।

रोजगार सृजन क्षमता और लाभार्थियों की संख्या सहित प्रमुख प्रभाव:

- RAMP कार्यक्रम विशेष रूप से प्रतिस्पर्धा के मोर्चे पर मौजूदा MSME योजनाओं के प्रभाव में वृद्धि के माध्यम से MSME क्षेत्र में सामान्य और COVID संबंधित चुनौतियों का समाधान करेगा।
- राज्यों के साथ बढ़े हुए सहयोग के माध्यम से RAMP कार्यक्रम, एक नौकरी देने वाला, बाजार प्रवर्तक, वित्त सुविधाकर्ता होगा और कमजोर वर्गों और हरित पहल का समर्थन करेगा।
- RAMP उद्योग मानकों, प्रथाओं में नवाचार और वृद्धि को बढ़ावा देकर आत्म निर्भर भारत मिशन का पूरक होगा और एमएसएमई को आवश्यक तकनीकी इनपुट प्रदान करेगा।

RAMP इस प्रकार होगा:

- "पॉलिसी प्रदाता": प्रतिस्पर्धात्मकता और व्यावसायिक स्थिरता में सुधार के लिए अधिक प्रभावी और लागत प्रभावी एमएसएमई हस्तक्षेपों के वितरण को सक्षम करने के लिए साक्ष्य-आधारित नीति और कार्यक्रम डिजाइन के लिए बढ़ी हुई क्षमता के माध्यम से।
- "ज्ञान प्रदाता": अंतरराष्ट्रीय अनुभवों का लाभ उठाकर बेंच-मार्किंग, सर्वोत्तम प्रथाओं/सफलता की कहानियों को साझा करने और प्रदर्शित करने के माध्यम से, और
- "प्रौद्योगिकी प्रदाता": अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी तक पहुंच प्रदान करना जिसके परिणाम स्वरूप अत्या धुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), मशीन लर्निंग आदि के माध्यम से MSMEs का डिजिटल और तकनीकी परिवर्तन हुआ।

न्यू इंडिया लिट्रेसी प्रोग्राम

खबरों में क्यों

शिक्षा मंत्रालय (MoE) ने 'न्यू इंडिया लिट्रेसी प्रोग्राम' को मंजूरी दी।

महत्वपूर्ण बिंदु

- भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 (एनईपी) के साथ वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को एकीकृत करने के लिए अगले पांच वित्तीय वर्षों (2022-27) के लिए 'न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम' को मंजूरी दी है।
- इसके अतिरिक्त, शिक्षा मंत्रालय ने 'वयस्क शिक्षा' के बजाय 'सभी के लिए शिक्षा' का उपयोग करना चुना है, क्योंकि पिछली शब्दावली 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के गैर-साक्षरों पर लागू नहीं थी।
- योजना को ऑनलाइन मोड के माध्यम से स्वयंसेवा के माध्यम से लागू किया जाएगा।
- स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण, अभिविन्यास, कार्यशालाओं का आयोजन आमने-सामने मोड के माध्यम से किया जा सकता है।
- टीवी, रेडियो, सेल फोन-आधारित मुफ्त या ओप. न-सोर्स ऐप या पोर्टल आदि जैसे आसानी से सुलभ डिजिटल मोड के माध्यम से पंजीकृत स्वयंसेवकों तक आसान पहुंच के लिए सभी सामग्री और संसाधन डिजिटल रूप से उपलब्ध कराए जाएंगे।
- योजना के क्रियान्वयन के लिए स्कूल इकाई होगा। लाभार्थियों और स्वैच्छिक शिक्षकों का सर्वेक्षण करने के लिए उपयोग किए जाने वाले स्कूल का उपयोग किया जायेगा। अलग-अलग आयु वर्ग के लिए अलग-अलग रणनीति अपनाई जानी है।
- नवोन्मेषी गतिविधियों को शुरू करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लचीलापन प्रदान किया जाएगा।
- 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के सभी गैर-साक्षर लोगों को महत्वपूर्ण जीवन कौशल के माध्यम से मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्रदान की जाएगी।

इस योजना के पांच घटक हैं, अर्थात:

1. मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता।
2. महत्वपूर्ण जीवन कौशल।
3. व्यावसायिक कौशल विकास।
4. बुनियादी शिक्षा।
5. सतत शिक्षा।

योजना के उद्देश्य हैं:

- आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता के लिए 05 करोड़ शिक्षार्थियों तक पहुंचना

RAO'S ACADEMY for Competitive Exams (A unit of RAJE)

- व्यावसायिक कौशल विकास प्रदान करना (स्थानीय रोजगार के लिए)
- बुनियादी शिक्षा प्रदान करने के लिए
- स्थानीय शिक्षार्थियों को रुचि या उपयोग के विषयों पर शिक्षा प्रदान करना

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान

खबरों में क्यों

कैबिनेट ने ग्रामीण स्थानीय निकायों को बढ़ावा देने की योजना के लिए 5,911 करोड़ रुपये को मंजूरी दी।

महत्वपूर्ण बिंदु

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2.78 लाख ग्रामीण स्थानीय निकायों को सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के लिए 5,911 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय को मंजूरी दी।
- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) की शासन क्षमताओं को बढ़ावा देने के प्रयास में 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2026 तक केंद्र प्रायोजित योजना को जारी रखने के लिए अपनी सहमति दी।
- 5,911 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय में से केंद्र का हिस्सा 3,700 करोड़ रुपए और राज्यों का 2,211 करोड़ रुपए है।
- 2018-19 से 2021-22 तक लागू करने के लिए योजना को पहली बार 2018 में कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया था।
- देश भर में पारंपरिक निकायों सहित ग्रामीण स्थानीय निकायों के लगभग 60 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि, पदाधिकारी और अन्य हितधारक इस योजना के प्रत्यक्ष लाभार्थी होंगे।
- पंचायतों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होता है, और ये संस्थाएं जमीनी स्तर के सबसे करीब हैं, पंचायतों को मजबूत करने से सामाजिक न्याय और समुदाय के आर्थिक विकास के साथ-साथ समानता और समावेशिता को बढ़ावा मिलेगा।
- पंचायती राज संस्थाओं द्वारा ई-गवर्नेंस के अधिक उपयोग से बेहतर सेवा वितरण और पारदर्शिता हासिल करने में मदद मिलेगी।
- यह योजना ग्राम सभाओं को नागरिकों, विशेष रूप से कमजोर समूहों के सामाजिक समावेश के साथ प्रभावी संस्थानों के रूप में कार्य करने के लिए मजबूत करेगी।
- यह राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर पर्याप्त मानव संसाधन और बुनियादी ढांचे के साथ पंचायती राज संस्थाओं के क्षमता निर्माण के लिए संस्थागत ढांचे की स्थापना करेगा।
- मंत्रिमंडल ने कोयला और ऊर्जा से संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास और स्थापना के लिए गैर-खनन योग्य भूमि के उपयोग के लिए एक नीति को भी मंजूरी दी।
- अनुमोदित नीति उन भूमियों के उपयोग के लिए एक स्पष्ट ढांचा प्रदान करती है जो अब कोयला खनन गतिविधियों के लिए उपयुक्त या आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं हैं; या भूमि जहां से माइन आउट/डी-कोयल्ड है और उसे पुनः प्राप्त किया गया है।
- मंत्रिमंडल ने अपशिष्ट जल के उपचार के लिए प्रौद्योगिकियों की खोज में सहयोग के लिए जापान के साथ हस्ताक्षरित एक समझौते को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की।
- जल शक्ति मंत्रालय ने विकेंद्रीकृत घरेलू अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पिछले महीने जापान के पर्यावरण मंत्रालय के साथ सहयोग के एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान

- यह एक ऐसी परियोजना है जिसे भारत में विभिन्न राज्यों में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा पंचायत स्तरों में सुधार और मजबूती के लिए लागू किया जाता है।
- यह आरजीएसए योजना केंद्र सरकार साथ ही राज्य सरकारदोनों द्वारा प्रायोजित है।
- योजना के केंद्रीय घटकों को पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा।
- राज्य घटकों के लिए वित्त पोषण पैटर्न केंद्र और राज्यों के बीच क्रमशः 60:40 के अनुपात में होगा, जम्मू-कश्मीर के पूर्वोत्तर, पहाड़ी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) को छोड़कर जहां केंद्र और राज्य का हिस्सा 90:10 होगा। हालांकि, अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्रीय हिस्सा 100% होगा।
- योजना का मुख्य उद्देश्य देश भर में निर्वाचित होने

RAO'S ACADEMY for Competitive Exams (A Unit of RACE)

वाली ग्राम पंचायतों को प्रशिक्षित करना और उनकी सहायता करना है ताकि वे बुनियादी स्तर पर अपना काम कुशलता से कर सकें।

- सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने के लिए योजना की गतिविधियों के कार्यान्वयन और निगरानी को व्यापक रूप से संरेखित किया जाएगा।
- पंचायतें एसडीजी हासिल करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों / विभागों और राज्य सरकार की सभी विकासात्मक गतिविधियों और योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए केंद्र बिंदु हैं।

आयुष वीजा

खबरों में क्यों

भारत आयुष उपचार के लिए विशेष वीजा श्रेणी शुरू करेगा।

महत्वपूर्ण बिंदु

- प्रधान मंत्री ने घोषणा की कि केंद्र जल्द ही उन विदेशी नागरिकों के लिए एक विशेष आयुष वीजा श्रेणी शुरू करेगा जो चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने की पहल के तहत पारंपरिक चिकित्सा का लाभ लेने के लिए भारत आना चाहते हैं।
- गांधीनगर के महात्मा मंदिर में वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन 2022 के उद्घाटन सत्र में बोलते हुए, पीएम ने कहा कि केंद्र के पास आयुष क्षेत्र को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए कई पहल हैं।
- पीएम ने इस बात पर जोर दिया कि कैसे आयुर्वेदिक दवाएं, आयुष कड़ा और ऐसे कई अन्य उत्पाद लोगों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद कर रहे हैं।
- कोविड-19 के समय में भारत से हल्दी का निर्यात कई गुना बढ़ गया। नवाचार और निवेश किसी भी क्षेत्र की क्षमता को कई गुना बढ़ा देते हैं। अब समय आ गया है कि आयुष क्षेत्र में जितना हो सके निवेश बढ़ाया जाए।
- प्रधानमंत्री ने निकट भविष्य में इस क्षेत्र को और प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा नियोजित पहलों पर प्रकाश डाला, जिसमें किसानों की सहायता करना, स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना और चिकित्सा पर्यटन को प्रोत्साहित करना शामिल है।
- प्राकृतिक पूरक, दवा आपूर्ति श्रृंखला, आयुष-आधारित निदान या टेलीमेडिसिन हो, चारों ओर नवाचार और निवेश की संभावनाएं हैं।
- पारंपरिक चिकित्सा क्षेत्र में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। कुछ दिन पहले अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के तहत एक ऊष्मायन केंद्र का उद्घाटन किया गया था। 2022 के चार महीनों में, भारत में 14 स्टार्टअप यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हुए।
- हिमालय हर्बल पौधों के लिए जाना जाता है, भारत सरकार हर्बल और औषधीय पौधों के उत्पादन को प्रोत्साहित कर रही है।
- यह स्थायी आय का एक जरिया हो सकता है और इसमें रोजगार सृजन की गुंजाइश है। हालांकि, ऐसे पौधों का बाजार सीमित और विशिष्ट है। ऐसे किसानों के लिए बाजार से जुड़ना आसान होगा।
- इस प्रकार सरकार एक ई-मार्केटप्लेस के लिए तेजी से काम कर रही है जो एक ऐसा पोर्टल है जो आयुष उत्पाद बनाने वाली कंपनियों को औषधीय पौधे उगाने वाले किसानों से जोड़ेगा।
- 'आयुषमार्क' भी विकसित किया जा रहा है, जो विश्व स्तर पर उच्च गुणवत्ता का आश्वासन देने के लिए उत्पादों पर मुहर लगाएगा।
- पारंपरिक दवाओं के कौशल पर बोलते हुए, मोदी ने केन्या के पूर्व प्रधान मंत्री रैला ओडिंगा की बेटी रोजमेरी ओडिंगा का उदाहरण दिया, जिन्हें कथित तौर पर केरल में आयुर्वेद उपचार द्वारा अंधेपन से ठीक किया गया था।

ई-श्रम पोर्टल

खबरों में क्यों

भारत सरकार कार्यों में असंगठित श्रमिकों के दुर्घटना दावों को संसाधित करने के लिए एक तंत्र की तलाश कर रही है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के शीर्ष पदाधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि मंत्रालय ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित श्रमिकों द्वारा दुर्घटना बीमा दावों को संसाधित करने के लिए एक तंत्र पर काम कर रहा था, जिसमें अब तक 27 करोड़ से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं।
- असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने और उनके लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को

RAO'S ACADEMY for Competitive Exams (A unit of RACE) YOUR SUCCESS OUR PRIORITY

सुगम बनाने के उद्देश्य से छह महीने पहले इस पोर्टल की शुरुआत की गई थी।

- उस समय किए गए वादों में यह भी था कि श्रमिक दुर्घटना बीमा के रूप में 2 लाख रुपये के पात्र होंगे।
- मंत्रालय ने कहा कि केंद्र की मौजूदा दुर्घटना बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के साथ ई-श्रम पोर्टल को जोड़ने पर चर्चा चल रही है।
- यह योजना श्रमिकों को ई-श्रम यूनिक आईडी नंबर के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्राप्त करने की अनुमति देगी।
- अधिकारी ने कहा कि ई-श्रम पोर्टल पर यूनिक आईडी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) से एक ही श्रृंखला में हैं।
- बजट भाषण 2022-2023 में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चार पोर्टलों राष्ट्रीय करियर सेवा, ई-श्रम, उद्यम (एमएसएमई शुरू करने में रुचि रखने वालों के लिए) और असीम (आत्मानबीर कुशल कर्मचारी नियोक्ता मानचित्रण) को जोड़ने की घोषणा की थी।
- श्रम मंत्रालय ने घोषणा की कि एनसीएस और ई-श्रम पोर्टलों को आपस में जोड़ने का काम हाल ही में पूरा किया गया है।
- इस जुड़ाव ने ई-श्रम पर पंजीकृत असंगठित कामगारों को एनसीएस पर निर्बाध रूप से पंजीकरण करने और एनसीएस के माध्यम से बेहतर रोजगार के अवसरों की तलाश करने में सक्षम बनाया है।
- अब तक 26,000 से अधिक ई-श्रम लाभार्थियों ने एनसीएस पर पंजीकरण कराया है और इस लिंकेज से लाभान्वित होने लगे हैं।

ई-श्रम पोर्टल

- पोर्टल, जिसे अगस्त 2021 में लॉन्च किया गया था, में अब तक 23 करोड़ से अधिक पंजीकरण हैं और अंततः इसका उद्देश्य असंगठित श्रमिकों के एक राष्ट्रीय डेटाबेस का निर्माण करना है जिसका उपयोग कल्याणकारी योजनाओं को शुरू करने के लिए किया जाएगा।
- यह प्रवासी श्रमिकों, निर्माण श्रमिकों, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों आदि सहित असंगठित श्रमिकों का पहला राष्ट्रीय डेटाबेस है।
- इसमें नाम, व्यवसाय, पता, व्यवसाय का प्रकार, शैक्षिक योग्यता, कौशल प्रकार और परिवार के विवरण आदि का विवरण होगा ताकि उनकी रोजगार योग्यता की अधिकतम प्राप्ति हो सके और उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभों का विस्तार किया जा सके।

जिवला

खबरों में क्यों

महाराष्ट्र कारागार विभाग ने राज्य भर की जेलों में सजा काट रहे कैदियों के लिए एक ऋण योजना शुरू की है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- महाराष्ट्र कारागार विभाग ने राज्य भर की जेलों में सजा काट रहे कैदियों के लिए एक ऋण योजना शुरू की है। जिवला नामक क्रेडिट योजना महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक द्वारा पेश की जा रही है।
- पायलट को पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में बंदियों के लिए पेश किया गया था, और धीरे-धीरे इसे राज्य भर की लगभग 60 जेलों में विस्तारित किया जाएगा।
- बैंक और जेल अधिकारियों के अनुसार, यह भारत में कैदियों के लिए पहली तरह की क्रेडिट योजना होने की संभावना है। कैदियों के लिए मौजूदा ऋण पहल उनकी जेल की अवधि पूरी होने के बाद पुनर्वास के लिए है।

कैदियों के लिए महाराष्ट्र की ऋण योजना क्या है, और कौन पात्र है?

- क्रेडिट योजना, जिसे जिवला कहा जाता है, जिसका मराठी में अर्थ 'स्नेह' होता है, मुख्य रूप से उन सजायाफ्ता कैदियों के लिए शुरू की गई है जो तीन साल से अधिक की जेल की सजा काट रहे हैं।
- अधिकारियों ने कहा कि अधिकांश कैदी अकेले कमाने वाले हैं, और उनकी कैद ने उनके परिवारों को आय के स्रोत के बिना छोड़ दिया है।
- इसलिए, ऋण कैदी के नाम पर वितरित किया जाएगा, यह नामित परिवार के सदस्यों को जारी किया जाएगा।
- शुरूआती चरण में 7 फीसदी ब्याज दर पर 50,000 रुपये का कर्ज दिया जाएगा.
- बैंक जो ब्याज कमाता है, उसका एक प्रतिशत

सिस्टम को वापस कैदी कल्याण कोष में योगदान के रूप में दिया जाएगा।

- बिना किसी बंधक या गारंटर की आवश्यकता के ऋण प्रदान किया जाएगा।
- कैदी अपने बच्चों की शिक्षा, परिवार के सदस्यों के चिकित्सा उपचार, कानूनी शुल्क, या किसी अन्य खर्च के लिए ऋण का उपयोग करने में सक्षम होंगे।
- बैंक अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने पाया कि 75 प्रतिशत से अधिक आवेदन कृषि उद्देश्यों के लिए थे।

जिवला योजना का शुभारंभ और आगे की राह

- 1 मई को महाराष्ट्र दिवस पर राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने यरवदा केंद्रीय कारागार में जिवला योजना की शुरुआत की।
- उन्होंने समारोह के दौरान एक कैदी को एक प्रतिनिधि त्वात्मक चेक सौंपा।
- प्रायोगिक चरण में, यरवदा केंद्रीय कारागार से 222 पुरुष और आठ महिला कैदियों के ऋण आवेदनों पर बैंक अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जा रही है।
- पायलट योजना की प्रतिक्रिया और कैदियों की साख के आधार पर, ऋण राशि बढ़ाने का निर्णय लिया जाएगा।

YOUR SUCCESS OUR PRIORITY
RAO'S ACADEMY
for Competitive Exams
(A unit of RACE)

9 विविध

मनाली - सरचू रोड

खबरों में क्यों

BRO ने रिकॉर्ड समय में मनाली-सरचू रोडखोली।

महत्वपूर्ण बिंदु

- BRO ने बारालाचा ला दर्रे (16043 फीट) पर बातचीत करते हुए रिकॉर्ड समय सीमा में मनाली से सरचू तक सड़क खोली।
- बीआरओ ने बर्फ हटाने के लिए एक विशेष टीम को शामिल करने के लिए हवाई प्रयास किया और उम्मीद से एक महीने से अधिक समय पहले रोड और पास को खोला।
- प्रारंभिक चरण में केवल आवश्यक आपूर्ति ले जाने वाले सेना के वाहनों को ही सड़क पर चलने की अनुमति दी जाएगी, स्थानीय नागरिक प्रशासन से अनुमोदन के बाद नागरिक यातायात की आवाजाही की अनुमति दी जाएगी।
- उत्तर-पश्चिमी सीमा क्षेत्रों में दर्रे खोलने की एक और बड़ी सफलता में, सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) ने हिमाचल में राष्ट्रीय राजमार्ग-1D पर 210 किलोमीटर लंबी मनाली-सरचू सड़क को खोल दिया है।
- यह उपलब्धि बीआरओ द्वारा NH-1 पर श्री नगर-कारगिल-लेह रोड पर नागरिक यातायात के लिए जोजिला दर्रा खोले जाने के एक दिन बाद आई है। मनाली-सरचू रोड को खोलना हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले से महत्वपूर्ण संपर्क स्थापित करता है जो आगे लेह-लद्दाख की ओर जाता है।
- दर्रा और सड़क, अतीत में, आम तौर पर अप्रैल के अंतिम सप्ताह में खोला जाता था, लेकिन बीआरओ द्वारा एक सड़क काफिले के सफल आवागमन के साथ लगभग एक महीने पहले पास को खोल दिया गया है जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है।
- सर्दियों के दौरान आम तौर पर सड़क साल में 160-180 दिनों के लिए बंद रहती है, लेकिन इस बार बीआरओ के प्रोजेक्ट दीपक ने 117 दिनों में सड़क खोल दी है।
- जास्कर रेंज के सबसे ऊंचे दर्रों में से एक, दुर्जेय बारालाचा ला दर्रा (16,043 फीट) पर बर्फ हटाने के सफल संचालन के आधार पर मनाली-सरचू रोड को खोलना था।
- बीआरओ ने दो तरफ से बर्फ हटाने वाली टीमों की एक साथ तैनाती के साथ दोतरफा दृष्टिकोण अपनाया, एक पाट्सियो से बारालाचा ला तक और दूसरा सरचू से बारालाचा ला तक।
- चूंकि सर्दियों के दौरान सरचू देश के बाकी हिस्सों से कट जाता है, इसलिए परियोजना द्वारा सक्रिय कार्रवाई और योजना के तहत पिछले साल नवंबर के दौरान सरचू कैंप में स्नो क्लीयरेंस प्लांट उपकरण और पुर्जों का स्टॉक अग्रिम रूप से किया गया था।

पीएम गति शक्ति

खबरों में क्यों

पीएम गति शक्ति देश में हर स्थान की भू-स्थानिक मैपिंग पर जोर देती है।

महत्वपूर्ण बिंदु

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि पीएम गति शक्ति देश में हर स्थान के भू-स्थानिक मानचित्रण पर जोर देती है, नक्शे की विभिन्न परतें जो एक-दूसरे से बात करती हैं, जिससे एकीकृत योजना बनती है, जिसमें समय और

RAO'S ACADEMY
for Competitive Exams
(A unit of RACE)

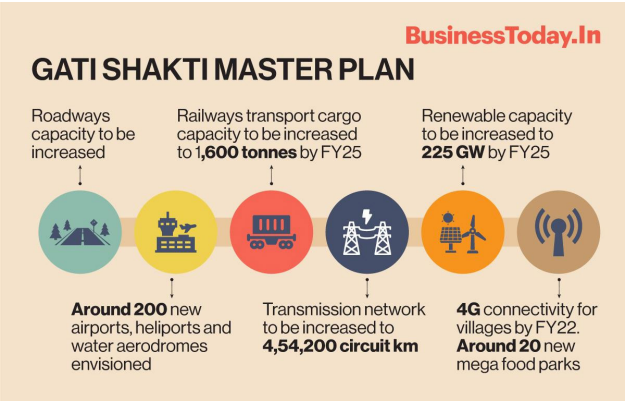

लागत का बेहतर अनुकूलन होता है।

भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी क्या है?

- भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियां एक शब्द है जिसका उपयोग पृथ्वी और मानव समाज के भौगोलिक मानचित्रण और विश्लेषण में योगदान करने वाले आधुनिक उपकरणों की श्रेणी का वर्णन करने के लिए किया जाता है।
- भू-स्थानिक डेटा की पहचान निगरानी, अनुरेखण, माप, मूल्यांकन, पहचान, या मॉडलिंग को सक्षम बनाता है। भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों की मूल सूची में रिमोट सेंसिंग (आरएस), जीपीएस और जीआईएस शामिल हैं।

उद्योग अनुप्रयोगों में प्रयुक्त स्थानिक प्रौद्योगिकियों के प्रकार:

- रिमोट सेंसिंग: सैटेलाइट इमेजरी और भू-स्थानिक डेटा सैटेलाइट सेंसर या एयरबोर्न कैमरों से एकत्र किया जाता है। सैटेलाइट इमेजरी जीआईएस मैपिंग प्रोजेक्ट को काफी बढ़ाता है और भू-स्थानिक मूल्यांकन और मॉडलिंग के लिए विश्लेषण और वर्गीकरण का समर्थन करने के लिए सूचना और डेटा के स्रोत के रूप में कार्य करता है।
- भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस): भू-स्थानिक डेटा के विश्लेषण के लिए मानचित्रण उपकरण जो भू-संदर्भित है। जीआईएस का उपयोग प्राकृतिक खतरों और आपदाओं, वैश्विक जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों, वन्यजीव संरक्षण, भूमि कवर परिवर्तन का पता लगाने और कई अन्य अनुप्रयोगों के लिए पर्यावरण प्रबंधन का समर्थन करने के लिए किया जा सकता है।
- ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस): उपग्रह-आधारित नेविगेशन सिस्टम 24 उपग्रहों के नेटवर्क से बना है, जिन्हें निर्देशांक स्थानों को एकत्रित करने के लिए कक्षा में रखा गया है।

पीएम गतिशक्ति के बारे में:

- यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो सड़क और राजमार्ग, रेलवे, शिपिंग, पेट्रोलियम और गैस, बिजली, दूरसंचार, शिपिंग और विमानन सहित 16 मंत्रालयों को जोड़ता है।
- इसका उद्देश्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समग्र योजना और निष्पादन सुनिश्चित करना है।

पीएम गति शक्ति छह स्तंभों पर आधारित है:

- **व्यापकता:** इसमें एक केंद्रीकृत पोर्टल के साथ विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की सभी मौजूदा और नियोजित पहल शामिल होंगी। प्रत्येक विभाग को अब व्यापक तरीके से परियोजनाओं की योजना और निष्पादन के दौरान महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करने वाली एक-दूसरे की गतिविधियों की दृश्यता होगी।
- **प्राथमिकता:** इसके माध्यम से विभिन्न विभाग क्रॉस-सेक्टोरल इंटरैक्शन के माध्यम से अपनी परियोजनाओं को प्राथमिकता देने में सक्षम होंगे।
- **अनुकूलन:** राष्ट्रीय मास्टर प्लान महत्वपूर्ण अंतरालों की पहचान के बाद परियोजनाओं की योजना बनाने में विभिन्न मंत्रालयों की सहायता करेगा। माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए, योजना समय और लागत के मामले में सबसे इष्टतम मार्ग चुनने में मदद करेगी।
- **तुल्यकालन:** अलग-अलग मंत्रालय और विभाग अक्सर एकांत में काम करते हैं। परियोजना के नियोजन एवं क्रियान्वयन में समन्वय का अभाव है जिसके परिणामस्वरूप विलम्ब होता है। पीएम गति शक्ति प्रत्येक विभाग की गतिविधियों के साथ-साथ शासन की विभिन्न परतों को उनके बीच काम का समन्वय सुनिश्चित करके समग्र रूप से समन्वयित करने में मदद करेगी।
- **विश्लेषणात्मक:** योजना जीआईएस आधारित स्थानिक योजना और 200+ परतों वाले विश्लेषणात्मक उपकरणों के साथ एक ही स्थान पर संपूर्ण डेटा प्रदान करेगी, जिससे निष्पादन एजेंसी को बेहतर दृश्यता प्राप्त होगी।
- **गतिशील:** सभी मंत्रालय और विभाग अब जीआईएस प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्रॉस-सेक्टोरल परियोजनाओं की प्रगति की कल्पना, समीक्षा और निगरानी करने में सक्षम होंगे, क्योंकि उपग्रह इमेजरी समय-समय पर जमीनी प्रगति देगी और परियोजनाओं की प्रगति को अपडेट किया जाएगा पोर्टल पर नियमित रूप से यह मास्टर प्लान को बढ़ाने और अद्यतन करने के लिए महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों की पहचान करने में मदद करेगा।

RAO'S ACADEMY for Competitive Exams (A unit of RACE)

पिनाका एमके-I रॉकेट सिस्टम

खबरों में क्यों

भारत ने पिनाका मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया।

महत्वपूर्ण बिंदु

- डीआरडीओ द्वारा पिनाका रॉकेट प्रणाली के एक नए संस्करण का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया है।
- कम से कम 24 पिनाका एमके-I (एन्हांस्ड) रॉकेट सिस्टम (ईपीआरएस) को विभिन्न रेंजों के लिए दागा गया और हथियारों को आवश्यक सटीकता और निरंतरता के साथ पूरा किया गया।
- EPRS पिनाका संस्करण का उन्नत संस्करण है जो पिछले एक दशक से भारतीय सेना के साथ सेवा में है।
- भगवान शिव के धनुष के नाम पर पिनाका रॉकेट प्रणाली को पुणे स्थित आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान (ARDE) और उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला (HEMRL) द्वारा विकसित किया गया है।
- परीक्षणों के एक ही सेट के हिस्से के रूप में, एआरडीई द्वारा पिनाका के लिए डिजाइन किए गए और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के तहत उद्योग भागीदारों द्वारा निर्मित एरिया डेनियल मुनिशन (एडीएम) का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था।
- एडीएम गोला-बारूद की एक श्रेणी है जिसका उपयोग विरोधी को किसी विशेष क्षेत्र पर कब्जा करने या वहां से गुजरने से रोकने के लिए किया जाता है।
- पिनाका का विकास, जो एक बहु-बैरल रॉकेट प्रणाली है, डीआरडीओ द्वारा 1980 के दशक के अंत में रूसी मेक के मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के विकल्प के रूप में शुरू किया गया था, जिसे 'ग्रैड' कहा जाता है, जो कुछ रेजिमेंट के अभी भी उपयोग में हैं।
- 1990 के अंत में पिनाका मार्क-1 के सफल परीक्षणों के बाद, 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान पहली बार युद्ध के मैदान में इसका इस्तेमाल काफी सफलतापूर्वक किया गया था।
- डीआरडीओ ने पिनाका एमके-II का भी विकास और सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जिसकी सीमा 60 किमी है, और गाइडेड पिनाका प्रणाली, जिसकी सीमा 75 किमी है।
- गाइडेड पिनाका मिसाइल की नेविगेशन प्रणाली भी भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (आई. आरएनएसएस) द्वारा सहायता प्राप्त है।

मुनिशन्स इंडिया लिमिटेड (MIL)

- Munitions India Limited (MIL) एक भारतीय राज्य के स्वामित्व वाली रक्षा कंपनी है, जिसका मुख्यालय पुणे, भारत में है, जिसकी स्थापना 2021 में आयुध निर्माणी बोर्ड के सात अलग-अलग सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पुनर्गठन और निगमीकरण के हिस्से के रूप में की गई थी।
- मुनिशन्स इंडिया मुख्य रूप से भारतीय सशस्त्र बलों, विदेशी सेनाओं और घरेलू नागरिक उपयोग के लिए गोला-बारूद, विस्फोटक, रॉकेट और बम बनाती है।

Munitions India के कुछ उल्लेखनीय उत्पादों में शामिल हैं:

- पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर
- हाई स्पीड लो ड्रैग बम
- एफएसएपीडीएस
- शिवालिक मल्टी मोड ग्रेनेड

जीसीटीएम

खबरों में क्यों

प्रधानमंत्री ने डब्ल्यूएचओ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मे. डिसिन की आधारशिला रखी।

महत्वपूर्ण बिंदु

- प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जामनगर में डब्ल्यूएचओ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन (जीसीटीएम) की आधारशिला रखी।
- डब्ल्यूएचओ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन (जीसीटीएम) दुनिया भर में पारंपरिक चिकित्सा के लिए पहला और एकमात्र वैश्विक चौकी केंद्र होगा क्योंकि यह वैश्विक कल्याण के एक अंतरराष्ट्रीय केंद्र के रूप में उभरेगा।
- उल्लेखनीय है कि पांच दशक से भी अधिक समय पहले जामनगर में दुनिया का पहला आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था।

RAO'S ACADEMY for Competitive Exams (A unit of RACE) YOUR SUCCESS OUR PRIORITY

- नया केंद्र डेटा, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करेगा और पारंपरिक चिकित्सा के उपयोग को अनुकूलित करेगा।
- WHO GCTM का प्राथमिक उद्देश्य आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से दुनिया भर से पारंपरिक चिकित्सा की क्षमता का दोहन करना और दुनिया भर के समुदायों के समग्र स्वास्थ्य में सुधार करना है।
- केंद्र पारंपरिक चिकित्सा की क्षमता को उजागर करेगा और इसके सुरक्षित और प्रभावी उपयोग को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी प्रगति का उपयोग करेगा।
- केंद्र पांच मुख्य क्षेत्र होंगे अनुसंधान और नेतृत्व, साक्ष्य और शिक्षा, डेटा और विश्लेषण, स्थिरता और इक्विटी और नवाचार और प्रौद्योगिकी।
- पारंपरिक चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली का एक प्रमुख स्तंभ है और न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- हाल के वर्ष में, पारंपरिक चिकित्सा उपचारों में भी एक बड़ा परिवर्तन देखा गया है क्योंकि कृत्रिम बुद्धि के उपयोग, तकनीकी नवाचारों ने इसे जनता के लिए अधिक सुलभ बना दिया है।
- जीसीटीएम का लक्ष्य पारंपरिक चिकित्सा के लाभों को आधुनिक विज्ञान की उपलब्धियों के साथ एकीकृत करना और एक व्यापक स्वास्थ्य रणनीति तैयार करना है।

जीसीटीएम पांच लक्ष्य निर्धारित करेगा:

- सबसे पहले, प्रौद्योगिकी का उपयोग करके पारंपरिक ज्ञान प्रणाली का डेटाबेस बनाना।
- दूसरा, यह पारंपरिक दवाओं के परीक्षण और प्रमाणन के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों का निर्माण करेगा ताकि इन दवाओं में विश्वास में सुधार हो।
- तीसरा, जीसीटीएम को एक ऐसे मंच के रूप में विकसित होना चाहिए जहां पारंपरिक दवाओं के वैश्विक विशेषज्ञ एक साथ आएं और अनुभव साझा करें।
- चौथा, जीसीटीएम को पारंपरिक दवाओं के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए धन जुटाना चाहिए।
- पांचवां, जीसीटीएम को विशिष्ट रोगों के समग्र उपचार के लिए प्रोटोकॉल विकसित करना चाहिए ताकि मरीज पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा दोनों से लाभान्वित हो सकें।

मलेरिया से मुक्त

खबरों में क्यों

कर्नाटक ने मलेरिया मुक्त बनने के लिए 2027 का लक्ष्य निर्धारित किया।

महत्वपूर्ण बिंदु

- कर्नाटक ने केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित 2030 के लक्ष्य से तीन साल पहले 2027 तक मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य रखा है।
- भारत में मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा (एनएफएमईआई) पहल के हिस्से के रूप में, 2015 और 2021 के बीच, पिछले छह वर्षों में मलेरिया को खत्म करने के अपने प्रयासों के लिए कर्नाटक को राष्ट्रीय मान्यता और प्रशंसा मिली है।
- कर्नाटक, जिसका मलेरिया उन्मूलन में श्रेणी- 2 वर्गीकरण था, को श्रेणी-1 के रूप में उन्नत और वर्गीकृत किया गया है। राज्य में पिछले तीन वर्षों में हर साल कम मामले सामने आ रहे हैं।
- केंद्र सरकार का 2030 तक भारत को मलेरिया मुक्त बनाने का लक्ष्य है, और पहले से ही कर्नाटक के 10 जिलों में पिछले तीन वर्षों में मलेरिया का एक भी मामला नहीं देखा गया है।
- वर्तमान में, कर्नाटक में सबसे अधिक मलेरिया के मामले उडुपी और दक्षिण कन्नड़ जिलों में हैं और इसके कारण को समझने के लिए शोध किया जा रहा है।
- मलेरिया का पता लगाने का सबसे आसान तरीका रक्त परीक्षण करवाना है, जो सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सरकारी तालुक अस्पतालों और सरकारी जिला अस्पतालों में उपलब्ध है।
- विश्व मलेरिया दिवस 2022: जानलेवा बीमारी की रोकथाम और नियंत्रण की आवश्यकता को उजागर करने के लिए प्रतिवर्ष 15 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है।
- मलेरिया एक परजीवी के कारण होता है जो एक निश्चित प्रकार के मच्छर के माध्यम से मनुष्यों में फैलता है। जब एक संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर

RAO'S ACADEMY for Competitive Exams (A unit of RACE)

किसी व्यक्ति को काटती है, तो यह प्लाजमोडियम परजीवी को रक्तप्रवाह में इंजेक्ट कर देता है जिससे वह संक्रमित हो जाता है।

- हालांकि यह रोग इलाज योग्य और रोकथाम योग्य है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2020 में दुनिया भर में मलेरिया के लगभग 241 मिलियन मामले थे। इसके अलावा, घातक बीमारी ने 2020 में दुनिया भर में 6.27 लाख लोगों के जीवन का दावा किया।
- कुछ देश ऐसे हैं जो मलेरिया का सफलतापूर्वक उन्मूलन करने में सफल रहे हैं। डब्ल्यूएचओ ने विश्व स्तर पर 40 देशों और क्षेत्रों को मलेरिया मुक्त प्रमाणीकरण प्रदान किया है।
- इनमें से चीन नवीनतम देश है जिसे डब्ल्यूएचओ द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था। मलेरिया मुक्त क्लब में शामिल होने वाले अन्य हालिया देश अल सल्वाडोर (2021), अर्जेंटीना (2019), पराग्वे (2018), और उज्बेकिस्तान (2018) हैं।
- भारत में अब तक कोई भी राज्य मलेरिया को पूरी तरह खत्म नहीं कर पाया है। 2019 में, WHO दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में भारत में मलेरिया के 88 प्रतिशत मामले और मलेरिया के कारण 86 प्रतिशत मौतें हुईं। यह अफ्रीका के बाहर भी एकमात्र देश है जो 11 'उच्च बोझ से उच्च प्रभाव' वाले देशों में शामिल है।
- भारत अब वर्ष 2030 तक मलेरिया के शून्य मामलों तक पहुंचने की राह पर है। यह मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा (एनएफएमई) का एक हस्ताक्षरकर्ता है और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा है।
- पर्याप्त उपाय करके, भारत 2017 की तुलना में मलेरिया के मामलों की संख्या को 60 प्रतिशत तक कम करने में सक्षम था और 2018 की तुलना में 46 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई।
- ओडिशा उन राज्यों में से एक है जो मलेरिया मुक्त लक्ष्य हासिल करने के करीब पहुंच रहा है। राज्य सरकार ने पिछले साल घोषणा की थी कि उसने पिछले तीन वर्षों में मलेरिया के मामलों में 90 प्रतिशत की कमी दर्ज की है।

S-400 वायु रक्षा मिसाइल

खबरों में क्यों

भारत को S-400 प्रशिक्षण के लिए रूस से सिमुलेटर, प्रशिक्षण उपकरण प्राप्त हुए।

महत्वपूर्ण बिंदु

- भारत को रूस से S-400 वायु रक्षा मिसाइल स्क्वाड्रन के प्रशिक्षण के लिए सिमुलेटर और अन्य उपकरण प्राप्त हुए हैं।
- एस-400 प्रशिक्षण स्क्वाड्रन के लिए सिमुलेटर, अध्ययन सामग्री और दस्तावेजों सहित उपकरण आ चुके हैं, जिसे भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के कर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए जल्द ही स्थापित किया जाएगा।
- प्रणाली में मिसाइल या संबंधित हथियार शामिल नहीं हैं।
- S-400 मिसाइल प्रणाली की खेप जहाज द्वारा वितरित की गई थी और अब यह चालू है। मिसाइल प्रणाली के कुछ हिस्सों को हवाई और समुद्री दोनों मार्गों के माध्यम से पहुंचा और निर्दिष्ट स्थानों पर जल्दी से तैनात किया गया।
- पिछले दिसंबर में, भारत ने पहली S-400 रेजिमेंट की डिलीवरी ली, जिनमें से पांच को रूस से अक्टूबर 2018 में हस्ताक्षरित 5.43 बिलियन डॉलर के सौदे के तहत अनुबंधित किया गया था। पहली इकाई को पंजाब में तैनात किया गया है और यह चालू है।
- CAATSA (काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज F: सेंक्शंस एक्ट) के तहत अमेरिकी प्रतिबंधों की धमकी के साथ, नई दिल्ली और मॉस्को ने इस सौदे के लिए रुपया-रूबल एक्सचेंज के माध्यम से भुगतान किया था।
- दोनों पक्ष अब बड़े द्विपक्षीय व्यापार के लिए समान भुगतान मार्ग तलाश रहे हैं।
- चीन के पास S-400 ट्रायम्फलंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली भी है, जिसे वर्तमान में भारत द्वारा शामिल किया जा रहा है, और यह प्रणाली उनके लिए एक शक्तिशाली हथियार बनी हुई है।
- "प्रत्यक्ष सामरिक योजना" के आधार पर, भारतीय वायु सेना (IAF) की रणनीति के आधार पर उनका

RAO'S ACADEMY for Competitive Exams (A unit of RAO'S) YOUR SUCCESS OUR PRIORITY

मुकाबला करना होगा, IAF के एक प्रतिनिधि ने रक्षा पर संसदीय स्थायी समिति को सूचित किया।

S-400 के बारे में

- दुनिया में सबसे उन्नत और शक्तिशाली वायु रक्षा प्रणालियों में से एक माना जाता है, S-400 ट्रायम्फ में ड्रोन, मिसाइल, रॉकेट और यहां तक कि लड़ाकू जेट सहित लगभग सभी प्रकार के हवाई हमलों से बचाने की क्षमता है।
- प्रणाली, एक विशेष क्षेत्र पर ढाल के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से, एक लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है।
- रूस 1993 से S-400 विकसित कर रहा है। परीक्षण 1999-2000 में शुरू हुआ और रूस ने इसे 2007 में तैनात किया।
- प्रणाली चार प्रकार की मिसाइलों से सुसज्जित है: 40 किमी तक की छोटी दूरी; मध्यम-सीमा 120 किमी तक; लंबी दूरी की 48N6 250 किमी तक जा रही है, और बहुत लंबी दूरी की 40N6E 400 किमी तक और 180 किमी की उड़ान ऊंचाई तक।
- यह एक साथ 600 किमी की सीमा में 160 वस्तुओं को ट्रैक कर सकता है, और 400 किमी की सीमा में 72 वस्तुओं को लक्षित कर सकता है।

यह कैसे काम करता है?

- S-400 वायु रक्षा बुलबुले (जिस क्षेत्र को इसे सुरक्षित करना है) के निकट एक हवाई खतरे का पता लगाता है, खतरे के प्रक्षेपवक्र की गणना करता है, और इसका मुकाबला करने के लिए मिसाइलों को दागता है।
- इसमें लंबी दूरी के निगरानी राडार होते हैं जो कमांड वाहन को सूचना भेजते हैं। लक्ष्य की पहचान करने पर, कमांड वाहन मिसाइल लॉन्च की अनुमति देता है।

अतिरिक्त तटस्थ शराब (ईएनए)

खबरों में क्यों

शराब निर्माता आयात शुल्क कम करने की मांग कर रहे हैं।

महत्वपूर्ण बिंदु

- शराब विनिर्माताओं ने नीति आयोग को पत्र लिखकर आयात शुल्क कम करने की मांग की है।
- घरेलू आपूर्ति में कमी की आशंका को देखते हुए, उन्होंने वैश्विक बाजारों से अतिरिक्त तटस्थ अल्कोहल आयात करने के लिए इसे लागत प्रभावी बनाने के लिए शुल्क में कमी की मांग की है।

अतिरिक्त तटस्थ शराब (ईएनए)

- यह मादक पेय बनाने के लिए प्राथमिक कच्चा माल है।
- यह एक रंगहीन खाद्य-ग्रेड अल्कोहल है जिसमें कोई अशुद्धियाँ नहीं होती हैं।
- इसमें एक तटस्थ गंध और स्वाद होता है, और आम तौर पर मात्रा के हिसाब से इसमें 95 प्रतिशत से अधिक अल्कोहल होता है।
- यह विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होता है - गन्ना गुड़ और अनाज - और इसका उपयोग मादक पेय जैसे व्हिस्की, वोदका, जिन, बेंत, लिकर और मादक फलों के पेय के उत्पादन में किया जाता है।
- ENA सौंदर्य प्रसाधन और व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों जैसे परफ्यूम, प्रसाधन सामग्री, हेयर स्प्रे आदि के निर्माण में एक आवश्यक घटक के रूप में भी कार्य करता है।
- एक अच्छे विलायक के रूप में इसके गुणों को देखते हुए, ENA का औद्योगिक उपयोग भी होता है और इसका उपयोग छपाई उद्योग के लिए कुछ लाख, पेंट और स्याही के उत्पादन के साथ-साथ एंटीसेप्टिक्स, दवाओं, सिरप, औषधीय स्प्रे जैसे दवा उत्पादों में भी किया जाता है।
- कंसल्टेंसी फर्म IMARC ग्रुप के अनुमानों ने 2018 में भारत में ENA बाजार को 2.9 बिलियन लीटर की मात्रा में रखा।
- एथेनॉल की तरह, ईएनए चीनी उद्योग का एक उपोत्पाद है, और गन्ने के प्रसंस्करण के अवशेष शीरे से बनता है।
- नीति आयोग को लिखे अपने पत्र में, कम आपूर्ति की आशंका के चलते, भारतीय मादक पेय कंपनियों के परिसंघ ने तेल विपणन कंपनियों द्वारा जैव-ईंधन मिश्रण के लिए इथेनॉल के उपयोग और महाराष्ट्र और कर्नाटक में हाल ही में आई बाढ़ का हवाला दिया है, जिसने इस क्षेत्र में गन्ने की फसल को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है।

RAO'S ACADEMY for Competitive Exams (A unit of RACE)

दिल्ली विश्वविद्यालय

खबरों में क्यों

दिल्ली विश्वविद्यालय (DU)2022 में अपनी शताब्दी मना रहा है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- दिल्ली विश्वविद्यालय ने घोषणा की है कि अंतिम वर्ष में कॉलेज छोड़ने वाले छात्र परीक्षाओं में शामिल होने और अपनी डिग्री पूरी करने के लिए एक बार के 'शताब्दी' अवसर के लिए पंजीकरण कर सकते हैं।
- 1 मई, 2022 को शुरू किए गए दिल्ली विश्वविद्यालय के साल भर चलने वाले शताब्दी समारोह के मद्देनजर ड्रॉपआउट छात्रों को अवसर दिया गया है।
- नियमित पाठ्यक्रम लेने वाले स्नातक, स्नातकोत्तर और व्यावसायिक पाठ्यक्रम के छात्र, गैर कॉलेजिएट महिला शिक्षा बोर्ड (एनसीडब्ल्यूईबी), स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (एसओएल) और बाहरी सेल पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकेंगे।
- पूर्व छात्र शताब्दी अवसर के लिए अपना पंजीकरण फॉर्म जमा कर सकते हैं।
- दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले सभी संकायों, विभागों, कॉलेजों और केंद्रों को 20 जून, 2022 तक ऐसे छात्रों द्वारा भरे गए पंजीकरण फॉर्म की पुष्टि और सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कहा गया है।
- पूर्व छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय के ऑनलाइन छात्र पोर्टल लिंक का उपयोग करके भी अपना पंजीकरण फॉर्म भर सकते हैं। पंजीकरण फॉर्म भरने के बाद, छात्र आगे के संचार के लिए भरे हुए फॉर्म का प्रिंटआउट रख सकते हैं।
- अनंतिम प्रवेश पत्र उनके संबंधित संकाय, विभाग, कॉलेज या केंद्र द्वारा पंजीकरण फॉर्म की पुष्टि के बाद जारी किए जाएंगे।

दिल्ली विश्वविद्यालय के बारे में

- तत्कालीन केंद्रीय विधान सभा के अधिनियम द्वारा 1922 में एकात्मक, शिक्षण और आवासीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित, शिक्षण, अनुसंध ान और सामाजिक आउटरीच में उत्कृष्टता के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता ने विश्वविद्यालय को अन्य विश्वविद्यालयों के लिए एक रोल-मॉडल और ट्रेंड सेटर बना दिया है।
- भारत के राष्ट्रपति कुलाधिपति हैं, उपराष्ट्रपति कुलाधि पति हैं और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विश्वविद्यालय के प्रो-चांसलर हैं।
- आदर्श वाक्य: 'निष्ठा धृति सत्य' 'विनिष्ठा धृति सत्यम्श (समर्पण, दृढ़ता और सत्य)।

ऑपरेशन सतर्क

खबरों में क्यों

आरपीएफ ने "ऑपरेशन सतर्क" के तहत केंद्रित प्रयास शुरू किया

महत्वपूर्ण बिंदु

- रेलवे सुरक्षा बल संघ का एक सशस्त्र बल है जिसे रेलवे संपत्ति, यात्री क्षेत्र और यात्रियों की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। यह रेलवे सुरक्षा के क्षेत्र में अग्रणी सुरक्षा एजेंसी है जिसकी पहुंच अखिल भारतीय स्तर पर है।
- भारतीय रेलवे, देश का प्राथमिक ट्रांसपोर्टर होने के नाते, कर चोरों, तस्करों, बंदूक चलाने वालों और देश के विरोधी ताकतों द्वारा अपने नापाक मंसूबों पर कार्रवाई करने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में अवैध वस्तुओं के परिवहन के लिए इस्तेमाल किए जाने की संभावना है।
- "ऑपरेशन सतर्क" के तहत केंद्रित प्रयास 5 अप्रैल से 30 अप्रैल 2022 तक शुरू किया गया था, जिसमें अवैध तंबाकू उत्पादों के परिवहन के 26 मामलों का पता चला था, जिसमें 44 लाख रुपये से अधिक मूल्य के तंबाकू उत्पाद जब्त किए गए थे और 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया था।
- 97 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर अवैध शराब के परिवहन के 177 मामलों को रोका गया और लगभग 18 लाख रुपये की अवैध शराब जब्त की गई।
- बेहिसाब सोने/चांदी के आभूषण और बेहिसाब नकदी कर चोरी के उद्देश्य से रेल के माध्यम से ले जाया जाता है।
- आरपीएफ ने कर चोरी के ऐसे 23 मामलों का पता लगाया और संबंधित कर अधिकारियों को लगभग 2.60 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी/सोना/चांदी सौंप दी।

YOUR SUCCESS OUR PRIORITY RAO'S ACADEMY for Competitive Exams (A unit of RACE)

- रेल के माध्यम से तस्करी के मामलों में प्रथम प्रतिसादकर्ता के रूप में अपनी जिम्मेदारी से अवगत होने के कारण, आरपीएफ ने ऐसे मामलों में ठोस कार्रवाई की और ऊपर उल्लिखित अवधि के दौरान लगभग 3.18 करोड़ रुपये की तस्करी का सामान जब्त किया। ।
- देश के विभिन्न हिस्सों में अपराध करने या नापाक मंसूबों को साकार करने के लिए कभी-कभी राष्ट्र विरोधी ताकतों द्वारा हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक ले जाया जाता है। आरपीएफ ऐसे तत्वों के डिजाइन को विफल करने के लिए "ऑपरेशन सतर्क" के तहत स्टेशनों, ट्रेनों और रेलवे क्षेत्र में गहन जांच कर रहा है।

देश भर में इस तरह के प्रयास के दौरान, आरपीएफ ने 17 व्यक्तियों को पकड़ा और एक एके 47 राइफल, एक पाइप गन, एक डबल बैरल गन, एक पिस्तौल, 06 देशी पिस्तौल, 3 खंजर, 12 बोर गोला बारूद के 10 टुकड़े, 140 टुकड़े.315 "बुलेट, 7.62 मिमी की गोलियों के 404 टुकड़े और विभिन्न कैलिबर गोला बारूद के 9 टुकड़े बरामद किए।

- भारतीय रेल राष्ट्र की जीवन रेखा है और रेल पर प्रहरी होने के नाते आरपीएफ इसे सुरक्षित रखने और नापाक गतिविधियों के लिए इसके उपयोग की अनुमति देने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा।

YOUR SUCCESS OUR PRIORITY
RAO'S ACADEMY
for Competitive Exams
(A unit of RACE)

RAO'S ACADEMY
for Competitive Exams
(A unit of RACE)

RAO'S ACADEMY
for Competitive Exams

UPSC | MPPSC
CLAT

आपकी सफलता
हमारी प्राथमिकता !

R-26, Zone-II, Opp, Railway Track, M.P. Nagar, Bhopal
CONTACT: 0755-7967814, 7967718, +91 83196 18002